RNI No : MPHIN/2022/82783
कुल पृष्ठ : 52, मूल्य : 50 रुपए
वर्ष 03, अंक 7 मासिक पत्रिका
25 जुलाई 2024

हमारा देश हमारा अभिमान

हर-हर महादेव

नये भारत में बदलाव के कानून...

जल्द मिलेगा न्याय...

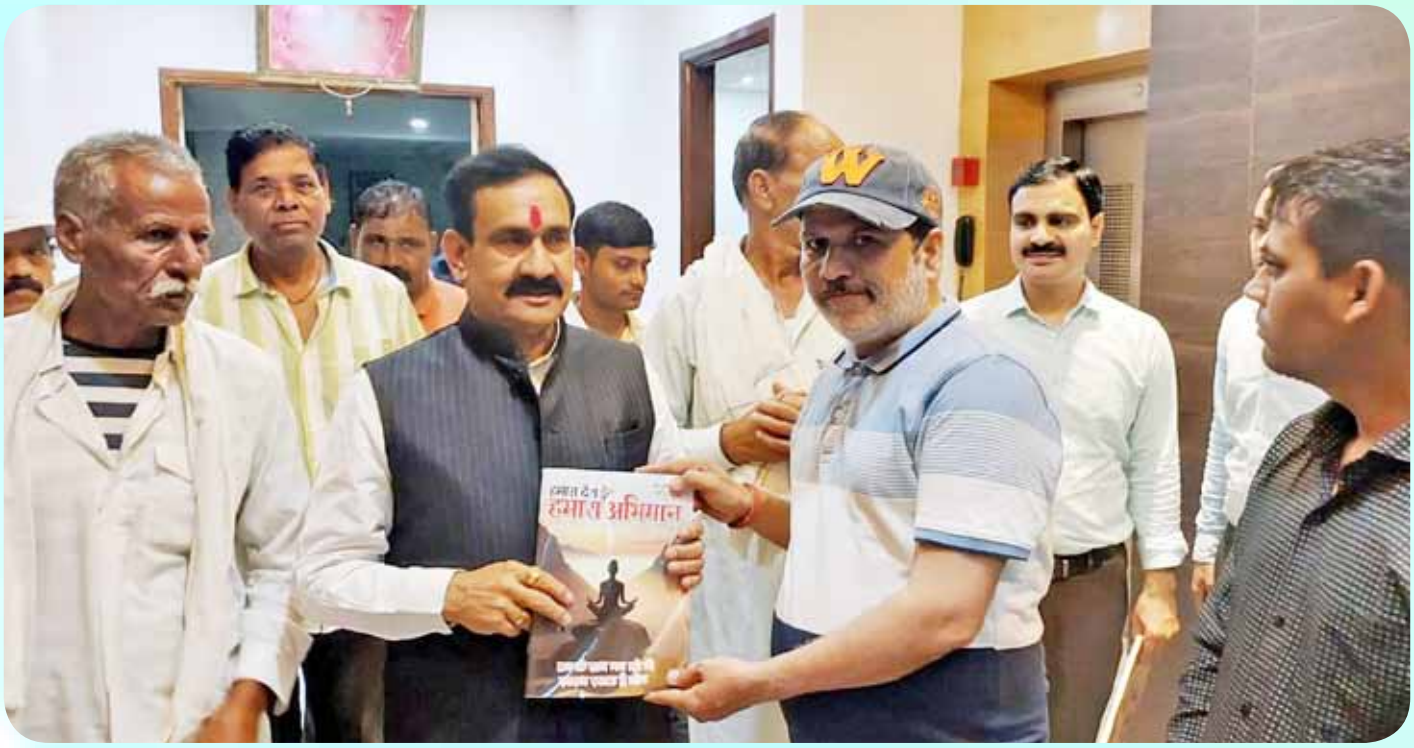

मध्यप्रदेश के पूर्व गृहमंत्री एवं बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर श्री नरोत्तम मिश्रा एवं संपादक मनोज चतुर्वेदी के साथ विशेष चर्चा।

मैसर्स पलिया कंस्ट्रक्शन कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर इंजीनियर श्री अनूप शर्मा ने हमारा देश हमारा अभिमान पत्रिका की वरिष्ठ संरक्षक दीदी डॉक्टर शालिनी कौशिक जी को पुष्पों का गुलदस्ता भेंट कर आशीर्वाद लिया साथ मैं उनके पुत्र एवं कंपनी के सह प्रबंधक इंजिनियर शिवम शर्मा ने भी पुष्प भेंट किए और आशीर्वाद लिया

मानवेंद्र सिंह अति. पुलिस अधीक्षक एवं सुरक्षा अधिकारी उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर एवं मनोज चतुर्वेदी संपादक के साथ विशेष चर्चा ।

विवेक शर्मा एसडीओपी डबरा के साथ हमारा देश हमारा अभिमान पत्रिका के संपादक मनोज चतुर्वेदी ने की विशेष चर्चा

हमारा देश
हमाराअभिमान

25 जुलाई 2024

वरिष्ठ संरक्षक मंडल

- अनन्त श्री विभूषित श्रीमद जगद्गुरु श्री राम स्वरूपचार्य जी महाराज कामदगिरि पीठाधीश्वर चित्रकूट धाम
- श्री महामंडलेश्वर रामप्रिय दास
- श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर अनिरुद वन जी, श्री धूमेस्वर धाम
- श्री डॉ. श्रीमन नारायण मिश्रा
- डॉ. श्रीमती शालिनी कौशिक
- श्री नागेंद्रनाथ सुरेंद्र नाथ चौबे

संरक्षक मंडल

- श्री लोकेश चतुर्वेदी
- श्री डॉ. दिनेश उपाध्याय
- श्री अरविंद जैन
- श्री प्रदीप कुमार शर्मा
- श्री शिवदयाल धाकड़
- श्री अरुण कांत शर्मा
- श्री महेश पुरोहित
- श्री विनोद भारद्वाज, अधिवक्ता ग्वालियर हाईकोर्ट,
- श्री मनोज भारद्वाज
- श्री अनिल जैन
- श्री निर्मल वासवानी
- श्री विद्याभूषण शर्मा
- श्रीमती अर्चना बाजपेयी
- एडवोकेट श्रीमती रिचा पांडेय (सुप्रीम कोर्ट)
- श्री के.एल.दलवानी
- श्री राकेश कुमार सगर
- श्री जयराज कुबेर
- श्री अभिनव पल्लव
- श्री बृजेश श्रीवास्तव
- श्री दीपक कुमार शुक्ला
- श्रीमति निवेदिता गुप्ता
- श्री विनोद कुमार बांगडे
- श्री विनायक शर्मा
- कमांडो कमल किशोर (पूर्व सांसद)
- श्री के. कान्याल

संपादक : मनोज चतुर्वेदी

पंकज दीक्षित
प्रमुख परामर्शदाता

विशेष संवाददाता
- रवि परिहार • रविकांत शर्मा

ब्यूरो : अविनाश (उज्जैन संभाग)

छिंदवाड़ा ब्यूरो : जितेंद्र चौरे

मुम्बई ब्यूरो (महाराष्ट्र)
सचिंदर शर्मा (फ़िल्म डायरेक्टर)

कानूनी सलाहकार
- एडवोकेट अनिल शुक्ला शासकीय अधिवक्ता, ग्वालियर हाईकोर्ट
- एडवोकेट एस.के. पाठक, ग्वालियर
- दीपेंद्र कुमार पाण्डेय, एडवोकेट, उच्च न्यायालय

सलाहकार

- डॉ सुनील शर्मा, नेत्र रोग विशेषज्ञ
- श्री डॉ. मुकेश चतुर्वेदी
- डॉ. दिनेश प्रसाद (हड्डी रोग सर्जन)
- श्री अनिल दुबे
- श्री विकास चतुर्वेदी
- श्री सुरेश शर्मा
- श्री नारायणदास गुप्ता
- श्री पीयूष श्रीवास्तव
- पंडित श्री चंद्रशेखर शास्त्री
- श्री बृज मोहन आर्य
- श्री विवेक शर्मा
- श्री अशोक कुमार वर्मा
- श्री आनंद कुमार
- श्रीमती रितु मुदगल
- श्री कुंज बिहारी शर्मा
- सुश्री पूजा मावई
- श्री संदीप कुमार पांडेय
- श्री मनोज सिंह
- प्रदीप यादव
- निरंजन शर्मा
- विनीत गोयल
- डॉ. सुधीर राजौरिया, हड्डी रोग विशेषज्ञ
- आशीष त्रिवेदी
- डॉक्टर अशोक राजौरिया
- हेमाटोलाजिस्ट और बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक्सपर्ट
- डॉक्टर कमल कटारिया
- यशवंत गोयल
- दीपक भार्गव
- अमित जैन इंदौर
- सुरजीत परमार
- संजू जादौन
- डॉक्टर हिमांशु डेंटिस्ट
- रागिनी चतुर्वेदी
- प्रवेंद्र चतुर्वेदी
- प्रखर सिंह

ब्यूरो राजस्थान
सुभाष सोरल (फ़िल्म निर्माता) कोटा

ब्रजेश जैन साक्षात्कार व्यवस्थापक और विज्ञापन संवाददाता इंदौर

संवाददाता : संदीप पाटिल, इंदौर

मार्केटिंग प्रमुख : शैलेन्द्र जैन

मार्केटिंग मैनेजर
- सुनील • हरशूल

डिजाइन : मनोज पंवार

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक मनोज कुमार चतुर्वेदी द्वारा कंचन ऑफसेट डी-1/63, सेक्टर-4, विनय नगर ग्वालियर- फोन नं. 0751-2481433, (म. प्र.) से मुद्रित एवं शिव कॉलोनी गली नं. 4 , रेलवे स्टेशन के पीछे, तहसील डबरा, जिला ग्वालियर, (मध्यप्रदेश) प्रकाशित। संपादक-मनोज कुमार चतुर्वेदी ।
(सभी विवादों का न्यायालय क्षेत्र ग्वालियर रहेगा।)

विवरणिका

संपादकीय	.....	02
शुभाशीष	.....	03
कवर स्टोरी	.....	04-05
हादसा	.....	06-07
हमारा ग्वालियर	.....	08-09
देश	.....	08
जबलपुर	.....	10
प्रदेश	.....	11
देश	.....	12-13
इन्दौर	.....	14
देश	.....	16
इन्दौर	.....	17
देश	.....	18-19
प्रदेश	.....	22-23
हमारा ग्वालियर	.....	24-25
देश	.....	26
राजस्थान	.....	27
प्रदेश	.....	28
देश	.....	30-31
प्रदेश	.....	32
कृषि-मंडी	.....	33
देश-प्रदेश	.....	34-35
धर्म	.....	42-43
स्वास्थ्य	.....	44
खेल	.....	45
ग्लैमर	.....	46
ग्लैमर	.....	47
ग्लैमर	.....	48

48

मैं अपनी खुशी से सिंगल हूं

संपादकीय

बांग्लादेश में हिंसक आंदोलन : किस तरह के आरक्षण का विरोध कर रहे युवा?

बांग्लादेश में हिंसक विरोध प्रदर्शनों के केंद्र में यहां की आरक्षण व्यवस्था है। इस व्यवस्था के तहत पाकिस्तान के खिलाफ 1971 के बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम में लड़ने वाले सेनानियों के परिवार के सदस्यों के लिए सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण का प्रावधान है। इसी आरक्षण के विरोध में इस वक्त बांग्लादेश में प्रदर्शन हो रहे हैं। पड़ोसी देश बांग्लादेश इन दिनों हिंसा की आग में झुलस रहा है। सरकारी नौकरियों में आरक्षण के मुद्दे शुरु हुआ विरोध प्रदर्शन देशभर में उग्र रुप ले चुका है। इस हिंसक आंदोलन के चलते 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। प्रदर्शन पर काबू पाने के लिए राजधानी ढाका में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। वहीं देशभर के शिक्षण संस्थानों में ताला लग गया और छात्र अपने घर वापस चले गए हैं। पड़ोसी देश बांग्लादेश इन दिनों हिंसा की आग में झुलस रहा है। सरकारी नौकरियों में आरक्षण के मुद्दे शुरु हुआ विरोध प्रदर्शन देशभर में उग्र रुप ले चुका है। इस हिंसक आंदोलन के चलते 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। प्रदर्शन पर काबू पाने के लिए राजधानी ढाका में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। वहीं देशभर के शिक्षण संस्थानों में ताला लग गया और छात्र अपने घर वापस चले गए हैं। आरक्षण आंदोलन के बीच सरकार ने कहा है कि वह मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार है। वहीं प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मुद्दे के समाधान तक उनका विरोध नहीं रुकेगा। इस विरोध में प्रदर्शनकारियों को विपक्षी दलों का भी साथ मिल गया है। बांग्लादेश में जारी हिंसा के चलते भारत, अमेरिका समेत कई देशों ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। उधर संयुक्त राष्ट्र संगठन ने भी हिंसा पर चिंता जताई है। आइये जानते हैं कि आखिर बांग्लादेश में जारी आरक्षण आंदोलन क्या है? यह आंदोलन कब और कैसे शुरु हुआ? बांग्लादेश की आरक्षण व्यवस्था क्या है जिसका विरोध हो रहा है? इस प्रदर्शन में अब तक क्या क्या हुआ? प्रदर्शनकारियों की मांग क्या है? अब आगे क्या होगा? कहानी 1971 से शुरु होती है। ये वो साल था जब मुक्ति संग्राम के बाद बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजादी मिली।

मनोज चतुर्वेदी
संपादक

शुभाशीष

नया कानून : बुजुर्गों को उन्नत एवं शांति देने के सराहनीय प्रयास किए गए...

भारतीय संस्कृति एवं सभी धार्मिक ग्रंथों में माता पिता को भगवान का रुप माना गया है और उनकी निःस्वार्थ सेवा करने की बात कही गयी है, लेकिन इसके बावजूद कई लोग अपने बुजुर्ग माता-पिता की सेवा करना तो दूर उल्टा उन्हें परेशान करते रहते हैं। देश में वृद्धों के साथ उपेक्षा, दुर्व्यवहार, प्रताड़ना बढ़ती जा रही है, बच्चे अपने माता-पिता के साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहते, वे उनके जीवन-निर्वाह की जिम्मेदारी भी नहीं उठाना चाहते हैं, जिससे भारत की बुजुर्ग पीढ़ी का जीवन नरकमय बना हुआ है, वृद्धजनों की पल-पल की घुटन, तनाव, जीवन-निर्वाह करने की जटिलता एवं उपेक्षा को लेकर समय-समय पर जहां न्यायालयों ने अपनी चिन्ता जतायी है, वहीं सरकार ने कानून बनाकर बुजुर्गों को उन्नत एवं शांति देने के प्रयास किये हैं, लेकिन इसके बावजूद वृद्ध लोगों का जीवन कष्टमय एवं जटिल बना हुआ है। वृद्ध माता-पिता की देखभाल एवं भरण-पोषण की जिम्मेदारी से मुंह मोड़ने की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। अदालतों में गुजारा-भत्ते से जुड़े विवाद बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। यही वजह है कि केंद्र सरकार वृद्ध माता-पिता की देखभाल के लिये बाध्य करने वाले 2007 के कानून में बदलाव लाकर, इसका दायरा बढ़ाने के मकसद से नये कानून लाने की तैयारी में है। माता-पिता और बुजुर्गों की देखभाल से जुड़े वर्षों पुराने कानून को प्रभावी व व्यावहारिक बनाने की कोशिश निश्चित रुप से सामाजिक एवं पारिवारिक ताने-बाने में वृद्धों को सम्मानजनक जीवन देने की सार्थक एवं सराहनीय कोशिश है। इस समय देश में करीब 10.5 करोड़ बुजुर्ग लोग हैं और 2050 तक इनकी संख्या 32.4 करोड़ तक पहुंच जाएगी। भारत सहित 64 ऐसे देश होंगे जहाँ 30 प्रतिशत आबादी 60 वर्ष से अधिक उम्र की होगी। एकल परिवार के दौर में बुजर्गों की देखभाल और भरण पोषण एक बड़ी समस्या के तौर पर उभर रही है ऐसे में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुजुर्गों की देखभाल के लिये मेंटिनेंस ऐंड वेलफेयर ऑफ पैरंट्स ऐंड सीनियर सिटिजन ऐक्ट 2007 में संशोधन की पहल की है, नये बिल के मुताबिक अब घर के बुजुर्गों की जिम्मेदारी सिर्फ बेटे ही नहीं, बल्कि बहू-दामाद, गोद लिए गए बच्चे, सौतेले बेटे और बेटियों की भी होगी।

डॉ. श्रीमन नारायण मिश्रा
संरक्षक

नये भारत में बदलाव के कानून...

जल्द मिलेगा न्याय...

सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था के अनुरूप राजद्रोह कानून को तो हटा दिया गया है लेकिन राष्ट्रीय एकता, अखंडता व संप्रभुता के अतिक्रमण को नये अपराध की श्रेणी में रखा गया है। संगठित अपराधों के लिये तीन साल की सजा का प्रावधान है।

भारतीय न्याय प्रणाली की कमियां को दूर करते हुए उसे अधिक चुस्त, त्वरित एवं सहज सुलभ बनाना नये भारत की अपेक्षा है। मतलब यह सुनिश्चित करने से है कि सभी नागरिकों के लिये न्याय सहज सुलभ महसूस हो, कानूनी प्रावधान न्यायसंगत एवं अपराध-नियंत्रण का माध्यम हो, वह आसानी से मिले, जटिल प्रक्रियाओं से मुक्त होकर सस्ता हो। निश्चित रूप से किसी भी कानून का मकसद नागरिकों के जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति व अधिकारों की रक्षा करना ही होता है। जिससे किसी सभ्य समाज में न्याय की अवधारणा पुष्ट हो सके। 1 जुलाई, 2024 से भारत आपराधिक न्याय के एक नए युग की शुरुआत होने जा रही है। न्याय का एक नया सूरज उदित हो रहा है, जब पूरे देश में लागू हुई भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तथा भारतीय साक्ष्य संहिता को लेकर उम्मीद करनी चाहिए कि यह बदलाव न्याय की कसौटी पर खरा उतरेंगे। इस दृष्टि से यह कानून से जुड़ी अकल्पित उपलब्धियों से भरा-पूरा अवसर भारत न्याय प्रक्रिया को एक नई शक्ति, नई ताजगी और नया परिवेश देने वाला साबित होगा। उल्लेखनीय है कि कानूनी बदलाव से जुड़े ये तीनों विधेयक बीते साल संसद में पारित किये गए थे।

अंग्रेजों के बनाये कानून क्या स्वतंत्र भारत में साढ़े सात दशक बाद भी लागू रहने चाहिए, यह लम्बे समय से विमर्श का विषय बना रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं उनकी सरकार द्वारा न्यायिक व्यवस्था को प्रभावी, आधुनिक, तकनीकी बनाने के लिये, अप्रासंगिक हो चुके कानूनों को बदलने एवं आधुनिक अपेक्षाओं के नये कानून बनाने का साहसिक एवं प्रासंगिक कदम उठाते हुए नए कानून लाने एवं उन्हें लागे करने का बड़ा कदम उठाया है, जो सुखद एवं स्वागतयोग्य है। विपक्षी दलों ने सांस्कृतिक, धार्मिक व भौगोलिक विविधता वाले देश के लिये बनाये गये कानूनों को भले ही व्यापक सार्वजनिक विमर्श के बाद ही लागू किया जाने की अपेक्षा व्यक्त की हो, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि जहां ब्रिटिश काल में बने कानूनों का मकसद दंड देना था, वहीं नये कानूनों का मकसद नागरिकों को न्याय देना है। मौजूदा चुनौतियों व जरूरतों के हिसाब से कानूनों को बनाया गया है।

इन कानूनों को बनाने का मूल उद्देश्य अपराधमुक्त समाज की संरचना करना है। इसीलिये अपराधियों को कड़े दण्ड देने का प्रावधान किया गया है। उल्लेखनीय है कि भारतीय न्याय संहिता में विवाह का प्रलोभन देकर छल के मामले में दस साल की सजा, किसी भी आधार पर मॉब लिंचिंग के मामले में आजीवन कारावास की सजा, लूटपाट व गिरोहबंदी के मामले में तीन साल की सजा का प्रावधान है। आतंकवाद पर नियंत्रण के लिये भी कानून है। किसी अपराध के मामले में तीन दिन में प्राथमिकी दर्ज की जाएगी तथा सुनवाई के बाद 45 दिन में फैसला देने की समय सीमा निर्धारित की गई है। वहीं प्राथमिकी अपराध व अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम के जरिये दर्ज की जाएगी। व्यवस्था की गई है कि लोग थाने जाए बिना

भी ऑनलाइन प्राथमिकी दर्ज कर सकें। यह कहने में कोई हर्ज नहीं है कि इन कानूनों के माध्यम से देश में पुलिस सुधार को भी बल मिलेगा। पुलिस कानून-कायदे के तहत काम करने को विवश या बाध्य होगी। अंततः अब पुलिस को अनुशासित बनाने के साथ-साथ कारगर बनाने की ओर देश ने अपने कदम बढ़ा दिए हैं। पुलिस प्रशासन की सफलता इसी में है कि तमाम लोगों को यह महसूस हो कि कानून न्यायपूर्ण ढंग से लागू किया जा रहा है। एक पहलू यह भी है कि पुलिस प्रशासन को कुशल और सक्षम बनाने के लिए संसाधनों की कमी आड़े नहीं आए। जिस स्तर की सेवा की उम्मीद लोग पुलिस से कर रहे हैं, उसके लिए सरकारों को पुलिस पर व्यय बढ़ाना होगा। सक्षम और सहयोगी पुलिस हमारे तेज विकास में कारगर होगी। पुलिस को प्रशिक्षित एवं सक्षम बनाने के तंत्र भी नये तरीके से विकसित करने होंगे। एक तरह से इन कानूनी प्रावधानों को सहज एवं सरल बनाने के प्रयास किये गये हैं।

ध्यान रहे, पिछले कानूनों में यह बड़ी कमी थी कि वे गरीबों को न्याय दिलाने में असमानता के द्योतक थे। उन कानूनों का इस्तेमाल गरीबों के खिलाफ जितनी आसानी से होता था, उससे कहीं ज्यादा कठिनाई से अमीरों के खिलाफ मामले दर्ज होते थे। आरोप सिद्ध होने या सजा के मामले में भी गरीबों को ही ज्यादा भुगतना पड़ता था। औपनिवेशिक युग के निर्मम या गरीब विरोधी कानूनों को समाप्त करने की मांग लंबे समय से हो रही थी। अब इन नये तीन कानूनों ने ब्रिटिश काल के तीन कानूनों की जगह ले ली है, इसका एहसास कराना होगा कि ब्रिटिश हिसाब से बने कानून अब देश में नहीं चल रहे हैं। नए कानूनों में यह ताकत है कि इनसे अपने यहां संपूर्ण न्याय प्रणाली में आम नागरिकों के अनुरूप आधुनिक बदलाव हो सकता है। केंद्र सरकार ने अपना काम कर दिया है और अब राज्यों को अपने स्तर पर इन अच्छे एवं प्रभावी कानूनों को लागू करने की पूरी तैयारी करनी पड़ेगी और देश के ज्यादातर राज्यों में पुलिस जिस तरह से प्रशिक्षित हो रही है, इससे जुड़ी खबरों का सामने आना भी सुखद है। सक्षम और सहयोगी पुलिस नये भारत-सशक्त भारत-विकसित भारत में कारगर होगी।

सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था के अनुरूप राजद्रोह कानून को तो हटा दिया गया है लेकिन राष्ट्रीय एकता, अखंडता व संप्रभुता के अतिक्रमण को नये अपराध की श्रेणी में रखा गया है। संगठित अपराधों के लिये तीन साल की सजा का प्रावधान है। इसके साथ ही अपराध की जांच-पड़ताल को आधुनिक तकनीक के जरिये न्यायसंगत बनाने का प्रयास किया गया है। जिसमें फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाना भी अनिवार्य है ताकि अपराधी संदेह का लाभ न उठा सकें। दूसरी ओर सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल अपराध नियंत्रण में बढ़ेगा। नये कानून के अनुसार मौत की सजा पाये अपराधी को खुद ही दया याचिका दायर करनी होगी, कोई संगठन या व्यक्ति ऐसा न कर सकेगा। निश्चित ही जहां सरकार वर्तमान संदर्भ के अनुरूप कानूनों का आधुनिकीकरण कर रही है वहीं उसे कानून व्यवस्था को सशक्त बनाने एवं पुलिस-व्यवस्था को सुधारने एवं सक्षम बनाने के लिये साधन-सुविधाओं को सुलभ कराने के लिये तत्पर होना होगा। नये कानून एवं नयी आधुनिक अदालतें कल के भारत को और मजबूत करेगी। नये भारत एवं सशक्त भारत को निर्मित करने में इनकी सर्वाधिक सार्थक भूमिका होगी। सरकार अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी या स्थानीय भाषाओं में न्याय-प्रक्रिया को संचालित करने के लिये भी प्रतिबद्ध है।

नए कानून से मुकदमे जल्दी निपटेंगे और तारीख पर तारीख के दिन लद जाएंगे। एक जुलाई से लागू हो रहे आपराधिक प्रक्रिया तय करने वाले तीन नये कानूनों में त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए एफआईआर से लेकर फैसले तक को समय सीमा में बांधा गया है। आपराधिक ट्रायल को गति देने के लिए नये कानून में 35 जगह टाइम लाइन जोड़ी गई है। शिकायत मिलने पर एफआईआर दर्ज करने, जांच पूरी करने, अदालत के संज्ञान लेने, दस्तावेज दाखिल करने और ट्रायल पूरा होने के बाद फैसला सुनाने तक की समय सीमा तय है। साथ ही आधुनिक तकनीक का भरपूर इस्तेमाल और इलेक्ट्रानिक साक्ष्यों को कानून का हिस्सा बनाने से मुकदमों के जल्दी निपटारे का रास्ता आसान होगा। शिकायत, सम्मन और गवाही की प्रक्रिया में इलेक्ट्रानिक माध्यमों के इस्तेमाल से न्याय की रफ्तार तेज होगी। उपर्युक्त सभी बातों को देखते हुए स्पष्ट है कि भारतीय न्याय तंत्र में विभिन्न स्तरों पर सुधार की दरकार को महसूस करते हुए वैसी व्यवस्थाएं की गयी है। लेकिन यह सुधार न सिर्फ न्यायपलिका के बाहर से बल्कि न्यायपालिका के भीतर भी होने चाहिये। ताकि किसी भी प्रकार के नवाचार को लागू करने में न्यायपालिका की स्वायत्तता बाधा न बन सकें। न्यायिक व्यवस्था में न्याय देने में विलंब न्याय के सिद्धांत से विमुखता है, अतः न्याय सिर्फ होना ही नहीं चाहिये बल्कि दिखना भी चाहिये। नये कानूनों एवं नयी कानूनी व्यवस्थाओं से ऐसा होता हुआ दिख रहा है जो नये भारत की ओर गति को दर्शा रहा है।

डब्ल्यूएचओ की चेतावनी, खत्म नहीं हुआ Covid-19

हर सप्ताह 1700 लोगों की हो रही मौत, दो वेरिएंट सबसे खतरनाक

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि कोविड-19 अभी भी दुनिया भर में प्रति सप्ताह लगभग 1,700 लोगों की जान ले रहा है। इसके साथ ही डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक टेड्रोस एडनोम घेब्येयियस ने वैक्सीन कवरेज में गिरावट पर चेतावनी दी।

बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार एक बार फिर से कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। इसके बाद कोरोना वायरस फिर सुर्खियों में है। जो लोग यह मन कर चल रहे थे कि कोरोना वायरस अब खत्म हो चुका है, उनकी चिंताएं भी बढ़ने लगी हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या कोरोना वायरस अभी खत्म नहीं हुआ है? आज हम आपको बताते है कि कोरोना वायरस को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन का लेटेस्ट अपडेट क्या है?

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि कोविड-19 अभी भी दुनिया भर में प्रति सप्ताह लगभग 1,700 लोगों की जान ले रहा है। इसके साथ ही डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक टेड्रोस एडनोम घेब्येयियस ने वैक्सीन कवरेज में गिरावट पर चेतावनी दी। संयुक्त राष्ट्र स्वास्थ्य एजेंसी के प्रमुख ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, 'मृत्यु की निरंतर संख्या के बावजूद, डेटा से पता चलता है कि स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और 60 से अधिक उम्र के लोगों के बीच टीका कवरेज में गिरावट आई है, जो सबसे अधिक जोखिम वाले समूहों में से दो हैं।'

डब्ल्यूएचओ की सिफारिश है कि उच्चतम जोखिम वाले समूहों के लोगों को उनकी आखिरी खुराक के 12 महीने के भीतर कोविड-19 वैक्सीन मिल जाए। डब्ल्यूएचओ को सात मिलियन से अधिक कोविड मौतों की सूचना दी गई है, हालांकि महामारी की वास्तविक संख्या कहीं अधिक मानी जाती है। कोविड-19 ने अर्थव्यवस्थाओं को भी तहस-नहस कर दिया और स्वास्थ्य प्रणालियों को पंगु बना दिया। टेड्रोस ने मई 2023 में अंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल के रूप में कोविड-19 की समाप्ति की घोषणा की, यह उस समय से तीन साल से अधिक समय बाद है जब 2019 के अंत में चीन के वुहान में पहली बार वायरस का पता चला था।

हाथरस हादसा...

उपजते सवालों के जवाब आखिर कौन देगा...?

पहला सवाल यही है कि हाथरस में जिस सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा के सत्संग में यह भगदड़ मची, जिसके बाद लोग हताहत हुए, उस बाबा का अब तक पता घटना के तत्काल बाद क्यों नहीं चला? जिस तरीके से एफआईआर में आरोपी बाबा का नाम नहीं डाला गया, वह भी चिंता की बात है।

भीड़ प्रबंधन (क्राउड मैनेजमेंट) में विफल सेवादारों और उनको 'बैक सपोर्ट' दे रहे प्रशासनिक हुक्मरानों की नादानी या लापरवाही या फिर दोनों से एक और जघन्य हादसा हो गया, जिसने 121 लोगों की इहलीला समाप्त कर डाली। वहीं, इस घटना में अन्य 38 लोग घायल भी हुए हैं। इस मामले की गम्भीरता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि मृतकों में उत्तरप्रदेश के 18 जिलों सहित हरियाणा, राजस्थान और मध्यप्रदेश के भी कई लोग शामिल हैं। इस घटना से सिविल और पुलिस प्रशासन की भूमिका भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि उनकी लापरवाही से एक बार फिर राजनीतिक नेतृत्व लांक्षित हुआ है। पहला सवाल यही है कि हाथरस में जिस सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा के सत्संग में यह भगदड़ मची, जिसके बाद लोग हताहत हुए, उस बाबा का अब तक पता घटना के तत्काल बाद क्यों नहीं चला? जिस तरीके से एफआईआर में आरोपी बाबा का नाम नहीं डाला गया, वह भी चिंता की बात है। आखिर क्या हुआ, उसको धरती खा गई या पाताल निगल गया, पुलिस प्रशासन को यह बताना होगा, या फिर उसे ढूंढकर कानून के कठघरे में लाना होगा, ताकि समुचित सजा मुकर्रर करवाई जा सके।

दूसरा सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में हाथरस जिले के थाना सिकंदराराऊ क्षेत्र के गांव रतीभानपुर में आयोजित भोले बाबा के सत्संग में अचानक भगदड़ मच गई, लेकिन उससे पहले भीड़ नियंत्रण यानी क्राउड मैनेजमेंट के बारे में सोचा तक नहीं गया। यह उस कथित बाबा और उनके सेवादारों की तो लापरवाही है ही, लेकिन स्थानीय अनुमण्डल और जिला प्रशासन भी इस हादसे के लिए कम जिम्मेदार नहीं है। क्योंकि किसी भी कार्यक्रम के आयोजन के लिए पूर्व प्रशासनिक स्वीकृति की आवश्यकता इसलिए पड़ती है ताकि समय रहते ही क्षेत्र विशेष में नागरिक सुविधाओं की आपूर्ति की जा सके, सुरक्षा के समुचित उपाय किये जा सके या फिर कोई आकस्मिक दुर्घटना होने पर लोगों को हताहत होने से बचाया जा सके।

तीसरा सवाल यह है कि इतनी बड़ी जुटान के बाद भी प्रशासन हाथ पर हाथ धरकर क्यों बैठा रहा? आखिर उसने एम्बुलेंस, अग्निशमन दस्ता, चिकित्सा सुविधाएं, आवागमन व्यवस्था, पेयजल, चलंत शौचालय आदि के लिए न तो कोई पूर्व उपाय किये और न ही तात्कालिक प्रबंध! क्योंकि यदि ऐसा किया गया होता तो इतनी बड़ी संख्या में लोग हताहत नहीं होते। वहीं, हादसे के बाद भी जो प्रशासनिक संवेदनशून्यता और व्यवस्थागत लाचारी/लापरवाही सामने आई, उसने भी अब तक हुए जनस्वास्थ्यगत विकास के तमाम दावों की कलई खोल दिए।

चतुर्थ सवाल यह है कि इस हादसे के लिए जिम्मेदार कौन है? अनुमण्डल प्रशासन, जिला प्रशासन, राज्य प्रशासन या फिर केंद्र की बैशाखी वाली गठबंधन सरकार? या फिर वह निजीकरण, जो सरकारी संस्थाओं को दीमक की तरह चाट चुका है अपने निजी लाभ के लिए! और इसकी हकीकत तब सामने आती है जब कोई बड़ी घटना-दुर्घटना या हादसे हो जाते हैं।

पांचवां सवाल यह है कि इस हादसे के मृतकों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं, जो दलित और ओबीसी वर्ग के हैं। बावजूद इसके, इतनी बड़ी लापरवाही के बाद भी मृतकों के लिए जो महज 2-2 लाख रुपये के मुआवजे घोषित किये गए हैं, वो ये जाहिर करते हैं कि हमारे देश-प्रदेश में गरीब लोगों के जान की कोई कीमत नहीं है। जबकि यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, जो प्रशासनिक विफलता का जीता-जागता उदाहरण है। इसलिए मुआवजे की राशि भी बढ़ाकर कम से कम 10-10 लाख रुपये किये जाने चाहिए। यही विपक्षी दलों की मांग भी है।

छठा सवाल यह है कि सरकारी व्यवस्था आखिर कब सुधरेगी? क्योंकि राहत विभाग की ओर से दी गई सूची के अनुसार, इस हादसे में अब तक 121 लोगों की मौत हो चुकी है और 28 लोग घायल हैं। सभी घायलों का अलग-अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। लेकिन सरकारी अस्पतालों की कुव्यवस्था किसी से छिपी हुई नहीं है, जहां बेड पर सफेद चादर और फल की टोकरी मुख्यमंत्री के आगमन के समय ही नजर आती है, अन्यथा नहीं। सातवां सवाल यह है कि पूर्व की घटनाओं की तरह इस हादसे की भी लीपापोती तो नहीं की जाएगी। क्योंकि इस घटना के मृतकों में सबसे ज्यादा लगभग 112 महिलाएं शामिल हैं। कहीं, आधी आबादी के खिलाफ यह कोई साजिश तो नहीं है। चूंकि हाथरस भगदड़ स्थल की जांच फोरेंसिक टीम ने की है। इसलिए इसे भी स्पष्ट करना होगा।लोगों को उम्मीद है कि सरकार और प्रशासन इस घटना पर लीपापोती से बाज आएगा और मृतकों के परिजनों को न्याय उपलब्ध करवाएगा। अन्यथा विपक्ष ने भी दो टूक कह दिया है कि यदि पीड़ितों को न्याय नहीं मिला वो चरणबद्ध आंदोलन करेंगे और दोषियों को सजा दिलाएंगे। क्योंकि इस घटना ने सभी बड़े नेताओं और अधिकारियों को एक बार फिर से विचलित कर दिया है।

आठवां सवाल यह है कि क्या यह घटना 'भोले बाबा' उर्फ नारायण साकार हरि द्वारा आयोजित सत्संग के दौरान उनकी चरण धुली लेने के क्रम में घटित हुई है, जैसी की चर्चा भी है। इसलिए फोरेंसिक टीम को अपने डॉग स्क्वॉड के साथ इस नजरिए से भी जांच करनी चाहिए।

नवम सवाल यह है कि जब पुलिस प्रशासन ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 105, 110, 126(2), 223 और 238 के तहत 'मुख्य सेवादार' कहे जाने वाले वेद प्रकाश मधुकर और इस धार्मिक कार्यक्रम के अन्य आयोजकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। तो फिर पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में बाबा का नाम गायब क्यों है? इतना ही नहीं, जब एफआईआर में कहा गया है कि ढाई लाख से अधिक श्रद्धालुओं की भीड इकट्ठी हो गई थी, जिसके कारण और आयोजक द्वारा अनुमति की शर्तों का पालन न किए जाने के कारण यातायात अवरुद्ध हो गया, तो फिर प्रशासन एक्टिव क्यों नहीं हुआ। आरोप तो यह भी है कि आयोजनकर्ताओं के द्वारा कार्यक्रम में जुटी भीड की संख्या छिपाकर और अधिक लोगों को बुलाया गया था। ऐसे में फिर वही सवाल कि तब प्रशासन क्या कर रहा था? वह सोया हुआ क्यों था? उसने एहतियाती उपाय समय रहते क्यों नहीं किये। यह जांच का विषय है। वहीं, जांच होने तक वहां के डीएम, एसएसपी और एसडीएम को अविलंब बदला जाना चाहिए।

सुकून की बात यह है कि इस हादसे को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो सख्त रुख अपनाया है, वह महज दिखावा नहीं है बल्कि राजनीतिक संवेदनशीलता का परिचायक है। इससे पता चलता है कि फायर ब्रांड हिन्दू मुख्यमंत्री और उनके मातहत प्रशासन ऐसे धार्मिक आयोजनों में हुई लापरवाही के प्रति संवेदनशील है। वहीं, प्रतिपक्ष का आरोप है कि ये हिंदुओं के हित चिंतक नहीं, बल्कि धर्म के धंधेबाज हैं। ये पूंजीवादी ताकतों के धार्मिक एजेंडे के मुखौटे हैं, ताकि वर्गीय अंतर्विरोधों को भुलावे में रखकर मजदूर क्रांति होने से रोका जाए।

भले ही सीएम योगी ने गत मंगलवार को कहा था कि हमारी सरकार इस घटना की तह में जाकर साजिशकर्ताओं और जिम्मेदारों को उचित सजा देने का काम करेगी। राज्य सरकार इस पूरी घटना की जांच करा रही है। हम इसकी तह में जाएंगे और देखेंगे कि यह हादसा है या साजिश? लेकिन घड़ियाली आंसू हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर कहा गया कि हाथरस में ग़रीब लोग अपनी तकलीफ़ों का हल पाने के लिए जिस ढोंगी बाबा के कथित सत्संग में गए थे, वह घटना के बाद से ही फ़रार है। दूसरों के गम दूर करने की डींगें हांकने वाला अपने भक्तों के सबसे दुखद क्षणों में ही नौ-दो ग्यारह हो गया। भगवान के नाम पर लाखों को लोगों को बेवक़ूफ़ बनाने वाला सूरज पाल अब इतनी हिम्मत भी नहीं जुटा पाया कि अपने भक्तों के बीच आकर दो शब्द कह सके। उसपर 5 मुक़दमे पहले से दर्ज हैं, कोरोना के टाईम पर भी इसने नियमों की अनदेखी की थी। इसलिए सवाल ये है कि इस पाखंडी का नाम एफआईआर में क्यों नहीं है?

समझा जाता है कि इस सार्वजनिक धिक्कार के बाद यानी घटना के एक दिन बाद कथित बाबा ने अपनी सफाई दी और कहा कि मैंने भगदड़ से बहुत पहले वह सत्संग स्थल छोड़ दिया था। इसलिए उन्होंने इस भगदड़ के लिए असामाजिक तत्वों को जिम्मेदार ठहराया। वहीं, उन्होंने ऐसे तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वकील डॉ ए पी सिंह को अधिकृत किया है। बाबा के शब्दों में.....मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना है, प्रभु से प्रार्थना है कि जल्द स्वस्थ करें।

बकौल मुख्यमंत्री योगी, सेवादार स्थानीय प्रशासन के अफसरों को ऐसे आयोजनों में अंदर नहीं जाने देते। ऐसे में अधिकारियों को लगा कि धार्मिक आयोजन है, इसलिए सेवादारों को ही जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। बड़े कार्यक्रम इसी तरह से होते हैं। पुलिस सुरक्षा के सबसे बाहरी घेरे में रहती है। लोग भी धार्मिक आयोजनों में अनुशासित रहते हैं। लेकिन आयोजन जब कुछ स्वार्थी लोगों के औजार बन जाते हैं तो यह अनुशासन भंग हो जाता है। इतना ही नहीं, घटना के बाद भी उन्होंने इसे छिपाने की कोशिश की। जब घायलों को अस्पताल ले जाया जा रहा था तो सेवादार भाग निकले।

यदि ऐसा है तो यह और भी गम्भीर बात है। इसलिए मुख्यमंत्री के मुताबिक, कुछ विशेष टीमें बनाई गई हैं, जो प्रारंभिक जांच के बाद आगे की कार्रवाई करेंगे। फिर भी लोग यहां तक कह चुके हैं कि जिस तरह से दवा घटिया होती है तो बीमारी बढ़ती है। उसी तरह से जब कानून घटिया होता है तो अराजकता बढ़ती है। लिहाजा, धर्म को नियंत्रित करने के लिए भी अब समावेशी कानून बनाने की जरूरत है। इसलिए योगी-मोदी सरकार को ही इस मामले में भी कुछ करना होगा।

निःसन्देह, हाथरस की घटना अत्यंत ही दुःखद और हृदयविदारक है। इसलिए योगी सरकार ने इस पूरे मामले के लिए एडिशनल डीजी आगरा की अध्यक्षता में मंडलायुक्त अलीगढ़ को शामिल करते हुए एक टीम बनाकर जांच शुरू की है। ताकि यह स्पष्ट हो सके कि यह हादसा है या कोई साजिश। वहीं, राज्य सरकार ने हाथरस की इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना की जांच माननीय उच्च न्यायालय के रिटायर्ड जज बृजेश कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय आयोग से ज्यूडिशियल इंक्वायरी भी करवाने की घोषणा की है। जिसमें पूर्व आईएएस अधिकारी हेमंत राव और पूर्व आईपीएस अधिकारी भवेश कुमार सिंह को भी शामिल किया गया है।

बहरहाल, सरकार को चाहिए कि वह ऐसी घटनाओं की हुई जांच के मद्देनजर एक श्वेत पत्र जारी करे, ताकि आमलोगों को पता चल सके कि अब तक के उसके जांच आयोगों की उपलब्धि क्या है और अबतक कितने लोगों को सजा हुई है। यदि ऐसा संभव नहीं है तो इस हृदयविदारक हादसे की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए न केवल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बल्कि उनके तमाम विभागीय मंत्रियों व उनके मातहत कार्यरत वरिष्ठ अधिकारियों को अपने अपने पद से अविलंब इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि अब यह तय हो चुका है कि मौजूदा राजनीतिक व प्रशासनिक टीम आमलोगों के जान-माल की हिफाजत के योग्य नहीं है।

एशिया का पहला नवग्रह शक्ति पीठ मंदिर बनकर तैयार...

बसंत जैन

राकेश कुचिया

अनिल जैन

अर्चना बाजपेई

गिरिजा परिहार

विकास चतुर्वेदी

मंगला चतुर्वेदी

सुनीता कुशवाह

रुचि चतुर्वेदी

मनोज भारद्वाज

मध्य प्रदेश के पूर्व गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के गृहनगर डबरा, जिला ग्वालियर में एशिया का पहला नवग्रह शक्ति पीठ मंदिर बनकर तैयार हो गया है। जल्द ही देश-विदेश के भक्त इस अद्वितीय पूजा स्थल का दर्शन कर सकेंगे। इस मंदिर का निर्माण परशुराम लोक न्यास के अथक प्रयासों से हुआ है। यह मंदिर चारों दिशाओं में धर्म और ज्ञान की अलग ध्वनि के साथ धर्म की ध्वजा फैलाएगा। इसी परिसर में लक्ष्मीनारायण मंदिर भी स्थित है। डबरा को धर्मस्थली बनाने में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की सनातन धर्म के प्रति भक्ति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 'हमारा देश हमारा अभिमान' पत्रिका के संरक्षक, डॉक्टर श्रीमन नारायण मिश्रा ने पत्रिका के संपादक मनोज चतुर्वेदी से विशेष चर्चा में यह जानकारी दी।

स्थानीय निवासी वसंत जैन ने बताया कि इस शक्ति पीठ के बनने से अब हमें नवग्रह दर्शन और पूजा के लिए कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं होगी। डबरा के प्रतिष्ठित व्यापारी राकेश कुचिया का मानना है कि इस शक्तिपीठ के बनने से न केवल दर्शन की सुविधा मिलेगी, बल्कि पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे व्यापार और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। सूरज होटल के मालिक अनिल जैन ने कहा कि यह मंदिर न केवल हमारे लिए, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी धर्म की ऊर्जा और सद्मार्ग पर चलने का मार्ग प्रशस्त करेगा। समाजसेवी और पंडित लक्ष्मीनारायण शिक्षा प्रसार एवं सामाजिक कल्याण समिति की सह सचिव अर्चना बाजपेई ने बताया कि यह शक्ति पीठ सभी लोगों के लिए धर्म और राष्ट्र की भावना को और सुदृढ़ करेगा।

डबरा एसडीओपी विवेक शर्मा ने कहा कि नवग्रह शक्ति पीठ मंदिर सभी लोगों को सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देगा। सामाजिक संस्था की सदस्य गिरिजा परिहार ने बताया कि नवग्रह शक्ति पीठ मंदिर के दर्शन शुरू होते ही हमें जीवन के लिए ऊर्जा प्रदान करने वाले क्षण मिलेंगे। 'हमारा देश हमारा अभिमान' पत्रिका के सलाहकार सदस्य एवं एलएन इन्वेस्टमेंट कंपनी के संस्थापक एवं मैनेजिंग डायरेक्टर विकाश चतुर्वेदी ने कहा कि नवग्रह शक्ति पीठ न केवल हमारे लिए, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी धर्म का संदेश और धरोहर बनेगा। डबरा को धार्मिक पर्यटन स्थल और सनातन धर्म का मुख्य केंद्र बनाने में नवग्रह शक्ति पीठ की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। पंडित लक्ष्मीनारायण सामाजिक कल्याण समिति के सदस्य मंगला चतुर्वेदी ने यह बात कही। डबरा में नवग्रह शक्ति पीठ का निर्माण देश के लिए एक सौभाग्य की बात है। समाजसेवी और श्री पंडित लक्ष्मीनारायण समिति की उपाध्यक्ष ने कहा कि यह हमारे जीवनकाल में देखने को मिलने वाला एक अनोखा अवसर है। समाज सेवी सुनीता कुशवाह ने बताया कि नवग्रह शक्ति पीठ डबरा को धार्मिक मानचित्र पर एक अलग पहचान दिलाएगा। जहां एक ओर पीतांबरा माई शक्ति पीठ है, वहीं दूसरी ओर प्राचीन धूमेस्वर शिव मंदिर और डबरा में नवग्रह शक्ति पीठ का निर्माण समाज के लिए शुभ संकेत है। रुचि चतुर्वेदी, पंडित श्री लक्ष्मीनारायण शिक्षा प्रसार समिति की सदस्य, ने कहा कि नवग्रह शक्ति पीठ मंदिर डबरा में धर्म की ध्वजा के नीचे समाज को सद्मार्ग पर चलने का महत्वपूर्ण आशीर्वाद प्रदान करेगा। मनोज भारद्वाज, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय हिंदू सेवा दल एवं संरक्षक सदस्य 'हमारा देश हमारा अभिमान' ने इसे सनातन धर्म के लिए अद्वितीय आशीर्वाद बताया।

एशिया का पहला नवग्रह शक्ति पीठ मंदिर डबरा जिला ग्वालियर मैं बनकर तैयार, डबरा मैं जल्दी दर्शन कर सकेगे भक्त गण...

पौधारोपण विषय पर मानस भवन जबलपुर में कार्यशाला संपन्न

पौधारोपण विषय पर मानस भवन जबलपुर में आयोजित कार्यशाला में विषय विशेषज्ञों द्वारा बताई गई पौधारोपण की तकनीक/परमाकल्चर एवं फूड फॉरेस्ट को धरातल पर उतारने हेतु जिला पंचायत जबलपुर द्वारा जनपद पंचायत जबलपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत बल्हवारा के ग्राम जमुनिया, ग्राम पंचायत पड़वार एवं सिहोरा, ग्राम पंचायत सिलुआ पड़रिया तथा ग्राम पंचायत मुकुनवारा में भ्रमण के दौरान पौधारोपण हेतु स्थल निरीक्षण किया।

उद्योगपतियों से बोले सीएम यादव

उद्योगों को सब्सिडी देने वाला मप्र, देश का पहला राज्य

एमपी में जबलपुर में 20 जुलाई कसे होने वाले रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में उद्योग की संभावना तलाशी जा रही है। मुख्यमंत्री ने जबलपुर के अलावा कटनी, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडौरी के उद्योगपतियों से कहा कि प्रदेश में रोजगार और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योगपतियों से संवाद के पीछे और इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के आयोजन का उद्देश्य यह है कि प्रदेश में उद्योग, व्यवसाय व कारोबार दोगुना हो जाए। सीएम ने कहा कि यहां चल रहे उद्योगों की कठिनाईयों को दूर करने की दिशा में सरकार तेजी से काम कर रही है।

मुख्यमंत्री ने रोजगारपरक औद्योगिक इकाईयों की संख्या बढ़ानें की बात उद्योगपतियों से करते हुए कहा कि राज्य सरकार उद्योगपतियों को जमीन, पानी और बिजली सहित अन्य जरूरी सहूलियतें मुहैया करा रही हैं। रोजगारपरक उद्योगों में काम कर रहे श्रमिकों के लिए पांच हजार रुपये प्रति श्रमिक के मान से सहायता राशि भी प्रदान करने जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीय उद्यमियों के साथ बाहर के उद्यमियों को जोड़कर प्रदेश के सभी अंचल में सरकार समान रूप से विकास करना चाहती है, जिसमें कृषि, रोजगार, व्यापार, पर्यटन आदि की दिशा में एक नए उपलब्धि को हासिल होगी। इसमें कई सारी कठिनाईयाँ आती है, लेकिन सकारात्मक सोच से आगे बढ़कर उनका निराकरण करें। छोटे-बड़े, मझौले सभी

उद्यमी सरकार के साथ कदम-कदम से मिलाकर चलेंगे तो विकास की एक नई धारा प्रवाहित होगी। जबलपुर से महाकौशल इंडस्ट्री के प्रेसीडेंट रवि गुप्ता ने कहा कि वे सरकार के प्रयासों के साथ तत्परता से जुड़ने को तैयार हैं। चेम्बर के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हिमांशु खरे ने सिंगल विंडो सिस्टम लागू करने की मांग की ताकि औद्योगिक समस्याओं का निराकरण आसानी से हो सके। साथ ही निवेश को आकर्षित करने के लिये फ्लाईट कनेक्टीविटी पर जोर दिया। उद्यमी वीके नेमा, डीआर जेसवानी, डा. अर्चना भटनाकर ने भी सकारात्मक सोच से औद्योगिक विकास को आगे बढ़ाने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कटनी रेल्वे का बहुत बड़ा जंक्शन है, कटनी जिले में रेल्वे से संबंधित औद्योगिक इकाईयों की अपार संभावनाए है, यहां उद्योगपति रेल्वे से संबंधित इंडस्ट्री लगाने आगे आएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कटनी को केवल खनिज, पत्थर, चूना और सीमेंट के लिए न जाना जाए, बल्कि रेल्वे ट्रेक और रेल से संबंधित विनिर्माण उद्योग स्थापित करने की दिशा में भी उद्योगपति पहल करें।

मध्यप्रदेश लघु उद्योग संघ के सचिव और मैसर्स जयंत सिरेमिक औद्योगिक क्षेत्र बरगवां के उद्योगपति सुधीर कुमार मिश्रा ने कहा कि 20 जुलाई को आयोजित जबलपुर के कान्क्लेव में बड़ा पूंजी निवेश आनें की संभावना है लेकिन पूर्व से स्थापित उद्योगों पर भी सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता की बात कही। वर्चुअल संवाद के दौरान मध्यप्रदेश रिफैक्ट्रीज मैनिफैक्चर्स एसोसिएसन के अध्यक्ष अरविंद गुगलिया ने कहा कि मध्यप्रदेश मे उद्योगों को 40 प्रतिशत सब्सिडी मिल रही है जो पूरे देश में और कहीं नही मिलती है। इससे प्रदेश मे उद्योग धंधे काफी फल- फूल रहे है। उन्होंने बताया कि मिनरल इंडस्ट्रियों के लिए और अधिक सुविधाएं शासन स्तर से प्रदाय करने का आग्रह किया।

योग दिवस पर एक ही दिन में बने कई विश्व रिकॉर्ड

2023 में दुनियाभर से कुल 23.4 करोड़ लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में भाग लेकर भी विश्व रिकॉर्ड कायम किया था, वहीं 2023 में ही गुजरात के सूरत में योग दिवस कार्यक्रम में योग सत्र में 1.53 लाख लोगों ने एक साथ हिस्सा लेकर नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था।

योग का भारत में संस्कृति के साथ सदियों पुराना जुड़ाव है बल्कि यूं भी कह सकते हैं कि भारत में योग की शुरूआत भारतीय संस्कृति के साथ ही जुड़ी है। भारत ने पूरी दुनिया को योग करना सिखाया है और भारत के कारण ही दुनिया के तमाम देश अब योग की महत्ता को समझने लगे हैं। करीब 5000 वर्ष पहले भारत से शुरू हुई योग की परंपरा शरीर और मन के बीच सामंजस्यपूर्ण संतुलन प्राप्त करने के लिए शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अनुशासन को जोड़ती है। 'योग' शब्द संस्कृत से लिया गया है, जिसका अर्थ है 'जुड़ना' अथवा 'एकजुट होना', जो शरीर और चेतना के मिलन का प्रतीक है। भारत की प्राचीन परंपराओं में गहराई से निहित योग वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य और आध्यात्मिक कल्याण के प्रतीक के रूप में कार्य करता है। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में योग को वैश्विक मान्यता मिलने के बाद से पिछले 10 वर्षों में योग दिवस पर कई रिकॉर्ड बने हैं।

2015 से लेकर अब तक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के नाम कई रिकॉर्ड 'गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स' में दर्ज हो चुके हैं। 2015 में पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर दिल्ली में राजपथ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कुल 35985 भारतीयों ने एक साथ योग करके सबसे बड़े योग सत्र का पहला विश्व रिकॉर्ड बनाया था जबकि दूसरा रिकॉर्ड एक ही स्थान पर योग सत्र में कुल 84 देशों के भाग लेने पर बना था। योग को लेकर एक विश्व रिकॉर्ड तब बना था, जब 2018 में राजस्थान के कोटा में करीब 1.05 लाख लोगों ने एक साथ योगाभ्यास किया था। 2023 में दुनियाभर से कुल 23.4 करोड़ लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में भाग लेकर भी विश्व रिकॉर्ड कायम किया था, वहीं 2023 में ही गुजरात के सूरत में योग दिवस कार्यक्रम में योग सत्र में 1.53 लाख लोगों ने एक साथ हिस्सा लेकर नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। उस योग कार्यक्रम के लिए करीब 300 मीटर चौड़ी दो सड़कों के 4 किलोमीटर लंबे हिस्से को योग प्रतिभागियों कालीन से ढ़का गया था। उससे पहले यह रिकॉर्ड 2018 में राजस्थान के कोटा शहर के नाम दर्ज था, जहां योग सत्र में करीब एक लाख लोग जुटे थे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर इस वर्ष तो कई रिकॉर्ड बने। देश-विदेश में फैली आध्यात्मिक संस्था ब्रह्माकुमारीज ने भी इस अवसर पर एक नया रिकॉर्ड कायम किया। ब्रह्माकुमारीज के आबूरोड़ स्थित अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय के साथ 140 देशों में फैले इसके 9000 केंद्रों पर करीब एक करोड़ लोगों ने एक साथ योग किया जबकि आबूरोड़ स्थित मुख्यालय पर 10 हजार लोगों ने एक साथ योगाभ्यास किया। वहीं, हिमालयन सिद्ध योग गुरु अक्षर के दूरदर्शी नेतृत्व में तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर एक नया इतिहास रचा गया। 'अक्षर योग केंद्र' ने 5 विशिष्ट योगासनों का वैश्विक मानकों पर सफलतापूर्वक प्रदर्शन करके 5 नए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए और 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव कार्यक्रमों की श्रृंखला में आयोजित इस स्पर्धा के जरिये योग की सार्वभौमिक अपील यानी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कल्याण के लिए इसके गहन लाभों का संदेश पूरी दुनिया देने का प्रयास किया गया। इन पांच वैश्विक कीर्तिमान स्थापित करने वाले आसनों में नौकासन, कौंडिन्य आसन (ऋषि कौंडिन्य मुद्रा), चक्रासन, भगवान शिव की एक मुद्रा नटराजासन, पांच मिनट तक लगातार सूर्य नमस्कार का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया गया।

हालांकि अक्षर योग केंद्र ने त्रिपुरा वासिनी, पैलेस ग्राउंड, बेंगलुरु में प्रभावशाली वैश्विक भागीदारी में सांस्कृतिक और भौगोलिक सीमाओं को पार करने की योग की क्षमता को प्रदर्शित करते हुए कुल सात आसनों के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए प्रयास किया था लेकिन गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की अंतर्राष्ट्रीय टीम ने सभी मानकों का अध्ययन करने के बाद इनमें से पांच आसनों में रिकॉर्डों को मान्यता प्रदान की जबकि दो आसनों पर रिकॉर्ड की मान्यता अभी समीक्षाधीन

है, जिन्हें विचार के लिए लंदन भेजा जाएगा। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के वरिष्ठ निर्णायक स्वप्निल डांगरीकर और ऋषिनाथ के मुताबिक 5 रिकॉर्ड सफलतापूर्वक पूरे किए गए थे। इसकी पुष्टि करते हुए स्वप्निल डांगरीकर का कहना था, ''मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि टीम अक्षर योग केंद्र ने सफलतापूर्वक 5 नए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड खिताब स्थापित किए हैं और मुझे याद नहीं आता कि मैंने एक ही दिन में इतने सारे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के प्रमाणपत्र दिए हैं।''

अक्षर योग केंद्र द्वारा ये विश्व रिकार्ड बनाने के लिए आयोजित कार्यक्रम में सभी क्षेत्रों से प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था, जिनमें छात्र, अनाथालयों के बच्चे, व्यापारिक समुदाय के सदस्य और कॉरपोरेट घराने भी शामिल थे। इसमें भाग लेने वाले एनसीसी ग्रुप 'ए' बेंगलुरू के 1200 से अधिक एनसीसी कैडेटों का भी विशेष योगदान रहा। उनके साथ उप महानिदेशक, एनसीसी डीटीई कर्नाटक और गोवा, ग्रुप कमांडर, एनसीसी ग्रुप मुख्यालय 'ए' बेंगलुरु, कमांडिंग ऑफिसर, एसोसिएट एनसीसी अधिकारी, ग्रुप 'ए' एनसीसी बटालियन के स्थायी प्रशिक्षक भी इस भव्य आयोजन का हिस्सा थे। इस गरिमामय समारोह में 20 से अधिक विभिन्न देशों के प्रतिभागी शामिल हुए थे। हिमालयन सिद्ध योग गुरु अक्षर के अनुसार योग दिवस के मौके पर ये रिकॉर्ड बनाने का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर योग के असंख्य लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, दुनियाभर के लोगों को समग्र स्वास्थ्य और आंतरिक शांति के लिए इस अभ्यास को एकीकृत करने के लिए प्रोत्साहित करना है। हिमालयन सिद्ध अक्षर के नेतृत्व में इस अवसर पर योग के गहन प्रभावों पर भी प्रकाश डाला गया, साथ ही समर्पित अभ्यास के माध्यम से अनुशासन का प्रदर्शन किया गया।

उल्लेखनीय है कि शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्पष्टता और आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देने के लिए समर्पित अक्षर योग केंद्र इसके विविध लाभों को प्रदर्शित करने के लिए नियमित रूप से फिटनेस शिविर, मुद्रा कार्यशालाएं और ध्यान सत्र आयोजित करता है। हिमालयन सिद्ध अक्षर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित एक आध्यात्मिक योग गुरु हैं, जो अक्षर योग केंद्र के संस्थापक, अध्यक्ष, पाठ्यक्रम निदेशक, विश्व योग संगठन के अध्यक्ष तथा अंतरराष्ट्रीय सिद्ध फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं। योग गुरु अक्षर का कहना है कि योग शरीर, मन और आत्मा का एक अभिन्न अंग है। योग इन तत्वों को एकजुट करता है और मानवता के लिए एक अनमोल उपहार के रूप में कार्य करता है। एक साथ पांच विश्व रिकॉर्ड कायम करने की उपलब्धि को लेकर उनका कहना है कि यह अविस्मरणीय घटना वास्तव में लोगों के लिए एक आशीर्वाद है, जो उन्हें योग के अभ्यास को अपनाने के लिए प्रेरित करती है। यह दुनियाभर में एक शक्तिशाली संदेश भेजती है, जिससे हर किसी को योग के गहन महत्व और इसके लाभों का अहसास होता है। इसके अलावा यह उपलब्धि हमारे देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को उजागर करती है, साथ ही समग्र स्वास्थ्य और आध्यात्मिक कल्याण को बढ़ावा देने में वैश्विक नेता के रूप में भारत की स्थिति को भी मजबूत करती है।

अक्षर योग केंद्र द्वारा एक साथ बनाए गए पांच विश्व रिकॉर्ड के अलावा एशियन योग चैंपियनशिप की स्वर्ण पदक विजेता 20 वर्षीया भूमि तिवारी ने भी जश्न-ए-आजादी ट्रस्ट और भारतीय आदर्श योग संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में मोती महल के लॉन में आयोजित 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम के दौरान 'रामदूत आसन' की मुद्रा को निरंतर 35 मिनट और 27 सैकेंड तक बनाए रखते हुए नया कीर्तिमान स्थापित किया। भूमि के मुताबिक 'रामदूत आसन' में पैरों को विपरीत दिशाओं में सबसे ज्यादा फैलाना और फिर सामने वाले पैर की उंगलियों को छूने के लिए झुकना होता है और यह सबसे कठिन, 'डी' श्रेणी का आसन है, जिसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में 0.9 अंक प्राप्त हुआ है। भूमि तिवारी द्वारा बनाए गए इस नए रिकॉर्ड की सूचना 'योगासन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड काउंसिल' को दी गई है।

नए कानून : एक पीसीआर कॉल पर जाते हैं 3 पुलिसकर्मी; अपराधी का बचना मुश्किल

अब कैदी को हथकड़ी लगा सकेगी पुलिस

दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अब पीसीआर कॉल होने पर तीन पुलिसकर्मी मौके पर भेजे जाते हैं। जांच अधिकारी हवलदार व उससे ऊपरी रेंक का पुलिस अधिकारी होता है। इसके बाद दूसरा पुलिसकर्मी आईओ किट वाला होता है। पुलिस अब कैदियों को हथकड़ी लगा सकेगी और हथकड़ी में ही कोर्ट में पेश कर सकेगी। नए कानून लागू होने के बाद यह सब संभव हो सकेगा। अब किसी घटना की पीसीआर कॉल होने पर एक नहीं बल्कि तीन पुलिसकर्मी जाते हैं। ये तीनों पुलिसकमी पूरे माहौल को कवर करने के अलावा वीडियोग्राफी करते हैं। ऐसे में अब सबूतों के साथ न छेड़छाड़ हो सकेगी और न ही सबूतों को बदला जा सकेगा। इससे पीडितों को न्याय मिल सकेगा।

दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अब पीसीआर कॉल होने पर तीन पुलिसकर्मी मौके पर भेजे जाते हैं। जांच अधिकारी हवलदार व उससे ऊपरी रेंक का पुलिस अधिकारी होता है। इसके बाद दूसरा पुलिसकर्मी आईओ किट वाला होता है। उसके पास आईओ जांच की पूरी किट होती है। इस किट में आपराधिक घटना के कवर या फिर काम आने वाले सभी उपकरण टेप, पेचकश, कैमरा समेत अन्य सामान होता है। इसके अलावा एक तीसरा पुलिसकर्मी भी होगा। यह पुलिसकर्मी वीडियोग्राफी बनाने व फोटो खींचने आदि में मदद करेगा।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार पहले पीसीआर कॉल पर एक ही पुलिसकर्मी चला जाता था। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, घटना व अपराधी के बयानों की वीडियोग्राफी होगी, जो एक महत्वपूर्ण व पुख्ता सबूत होगा। साथ में मौके पर मौजूद लोगों के बयान भी दर्ज किए जा सकेंगे।

एक जुलाई से लागू किए गए तीन नए कानूनों को लाने का खास मकसद अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे आउटडेटेड नियम कायदों को हटाना और उनकी जगह आज की जरूरत के मुताबिक कानून लागू करना है। इसके अलावा पुलिस कुछ आरोपियों को हथकड़ी लगाकर भी गिरफ्तार कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने 1980 में प्रेम शंकर शुक्ला बनाम दिल्ली सरकार मामले में फैसला सुनाते हुए हथकड़ी के इस्तेमाल को अनुच्छेद 21 के तहत असंवैधानिक करार दिया था। अपने फैसले में कोर्ट ने कहा था कि यदि किसी कैदी को हथकड़ी लगाने की जरूरत महसूस होती है तो उसका कारण दर्ज करना होगा और मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी होगी। अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 43 (3) में गिरफ्तारी या अदालत में पेश करते समय कैदी को हथकड़ी लगाने का प्रावधान किया गया है।

नियम : इनको लगाई जा सकती है हथकड़ी

- यदि कोई कैदी आदतन अपराधी है।
- या फिर पहले हिरासत से भाग चुका है।
- संगठित अपराध में शमिल रहा हो।
- आतंकवादी गतिविधि में शामिल रहा हो।
- मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़ा हुआ हो।
- हथियार या गोला बारूद सप्लाई करता हो।
- हत्या, दुष्कर्म, एसिड अटैक।
- नकली करेंसी की सप्लाई में शामिल हो।
- मानव तस्करी में शामिल हो।
- बच्चों के खिलाफ यौन अपराध या फिर राज्य के खिलाफ अपराध में शामिल रहा हो।

इंदौर में नाइट कल्चर बंद

मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश : 2 साल पुराना आदेश तत्काल प्रभाव से निरस्त, नई व्यवस्था लागू होगी

इंदौर में नाइट कल्चर पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंदौर संभाग के मंत्रियों, विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की थी। इस बैठक में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने ड्रग के अवैध कारोबार पर प्रभावी रोक लगाने और इंदौर में नाइट कल्चर एवं व्यवसायिक संस्थानों के संचालन का विषय रखा था। इस पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने तत्काल निर्देश दिए कि शीघ्र ही विस्तृत कार्ययोजना बनाकर रात्रिकालीन बाजार, औद्योगिक संस्थान, कार्यालय संचालन आदि के संबंध में नई व्यवस्था लागू की जाएगी। ड्रग के अवैध कारोबार पर भी प्रभावी रूप से रोक लगाई जाएगी। दोषियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही होगी। इस संबंध में शीघ्र ही नई कार्ययोजना बनाकर बाजार एवं व्यवसायिक संस्थाओं का संचालन रात्रि में होगा। लेकिन तब तक पुरानी व्यवस्था भंग की जाती है। इसके बाद कलेक्टर आशीष सिंह ने पूर्व में इन्दौर शहर में निरंजनपुर चौराहे से राजीव गांधी चौराहे तक, बी.आर.टी.एस कॉरिडोर में विभिन्न व्यवसायिक/औद्योगिक/कार्यालय आदि संस्थानों के लिए 24 घंटे संचालन संबंधी आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया।

2022 में जारी हुआ था नाइट कल्चर लागू करने आदेश : इंदौर में नाइट कल्चर लागू करने संबंधी आदेश 13 सितम्बर 2022 को जारी हुआ था। इसमें म.प्र. दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144, म.प्र. दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958, म.प्र. श्रम विधियां (संशोधन) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 2015 संशोधित कारखाना अधिनियम 1948 तथा मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के अन्तर्गत इन्दौर शहर में निरंजनपुर चौराहे से राजीव गांधी चौराहे तक 11.45 किलोमीटर, बी.आर.टी.एस. कॉरिडोर में विभिन्न व्यवसायिक/औद्योगिक/कार्यालय आदि संस्थानों को 24x7 अर्थात रात्रिकालीन सेवाओं (24 घण्टे) संचालन की अनुमति दी गई थी।

आईडीए बनाएगा इंदौर की सबसे बड़ी सडक

इंदौर विकास प्राधिकरण के द्वारा अहिल्या पथ के रूप में इंदौर की सबसे सुंदर सडक बनाने की तैयारी की जा रही है। इस सडक के सामने नगर निगम के द्वारा आदर्श सहक के रूप में विकसित की गई सडक कही नहीं टिक पाएगी। इस नई सडक के साथ ही प्राधिकरण शहर को सैटेलाइट टाउन की सौगात भी देने जा रहा है। इंदौर विकास प्राधिकरण के संचालक मंडल की बैठक आयोजित की गई है। 15 किलोमीटर की सडक बनाने हेतु कुल 8 गांवों की लगभग 1400 हेक्टेयर भूमि पर कुल 5 स्कीम प्रस्तावित है। परियोजना के प्रथम चरण में लागत 400 करोड़ रुपये होगी।

अचानक आयोजित की गई इस बैठक में मुख्य रूप से अहिल्या पथ का प्रस्ताव रखा गया। यह अहिल्या पथ इंदौर एयरपोर्ट के सामने से लेकर ग्राम रेखती तक बनाया जाएगा। इंदौर के मास्टर प्लान में किए गए प्रावधान के अनुसार यह सडक 90 मीटर चौड़ी और 15 किलोमीटर लंबी होगी। यह पहली ऐसी सडक होगी जो की इतनी बड़ी होगी और प्राधिकरण के द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा।

इस बारे में पूछे जाने पर प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी राम प्रकाश अहिरवार ने बताया कि बैठक में तो इस सडक के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी के लिए रखा गया है। इस सडक के दोनों तरफ प्राधिकरण को अपनी योजना 300 मीटर के क्षेत्र में या 500 मीटर के क्षेत्र में लाना है। अभी जो विचार सामने है उसके अनुसार इस योजना में सभी प्लांट को आवासीय कम व्यवसायिक उपयोग बाले प्लाट के रूप में विकसित किया जाएगा। इससे इस क्षेत्र में मॉल थिएटर आदि का भी निर्माण हो सकेगा।

आवासीय-व्यवसायिक व अन्य गतिविधियां शुरू होंगी : अहिल्या पथ के बनने से जहां धार-देपालपुर से आने वाले भारी और माल वाहनों का इंदौर शहर में बिना प्रवेश हुए उज्जैन और पीथमपुर की तरफ सीधा आवागमन होगा, वहीं रेवती से ग्राम रिजलाय तक 15 किलोमीटर लम्बे मार्ग पर नगर विकास योजनाओं से आवासीय-व्यवसायिक व अन्य गतिविधियां शुरू होंगी। अहिल्या पथ क्र। 1 से लेकर क्र। 5 तक टीपीएस के प्रारम्भिक प्रस्ताव तैयार किए गए हैं।

ऐसी होगी सडक़ की तस्वीर...

- इंदौर की सबसे अच्छी और सबसे सुंदर सडक़ के रूप में विकसित करने की योजना बनाई जाएगी।
- अहिल्या पथ का निर्माण कार्बन न्यूट्रल सडक के रूप में किया जायेगा।
- यह सडक रेवती गांव से रिजलाया तक बनाई जाएंगी।
- यह सडक कुल सिक्स लेन की होगी।
- इसके साथ ही इसके मीडियम में अच्छी हरियाली विकसित की जाएगी।
- सडक के दोनों तरफ अलग से साइकिल ट्रैक, पाथवे और सर्विस रोड होगी।
- अहिल्या पथ के नाम से विकसित होने वाली यह सडक , सुपर कॉरिडोर से भी अधिक चौड़ी नजर आएगी।
- सडक के दोनों तरफ ग्रीन बेल्ट के अलावा साइकिल ट्रैक सहित अन्य सुविधाएं रहेंगी।
- इस अहिल्या पथ के दोनों तरफ 500-500 मीटर की चौड़ाई में प्राधिकरण अपनी टीपीएस योजनाएं लाएगा।
- खुले हरित क्षेत्र को 5त्न से बढ़ाकर 7त्न तक किया जाएगा

डब्ल्यूएचओ ने दी चेतावनी, अभी खत्म नहीं हुआ Covid-19

हर सप्ताह 1700 लोगों की हो रही मौत, दो वेरिएंट सबसे खतरनाक

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि कोविड-19 अभी भी दुनिया भर में प्रति सप्ताह लगभग 1,700 लोगों की जान ले रहा है। इसके साथ ही डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक टेड्रोस एडनोम घेब्येयियस ने वैक्सीन कवरेज में गिरावट पर चेतावनी दी।

बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार एक बार फिर से कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। इसके बाद कोरोना वायरस फिर सुर्खियों में है। जो लोग यह मन कर चल रहे थे कि कोरोना वायरस अब खत्म हो चुका है, उनकी चिंताएं भी बढ़ने लगी हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या कोरोना वायरस अभी खत्म नहीं हुआ है? आज हम आपको बताते है कि कोरोना वायरस को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन का लेटेस्ट अपडेट क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि कोविड-19 अभी भी दुनिया भर में प्रति सप्ताह लगभग 1,700 लोगों की जान ले रहा है। इसके साथ ही डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक टेड्रोस एडनोम घेब्येयियस ने वैक्सीन कवरेज में गिरावट पर चेतावनी दी। संयुक्त राष्ट्र स्वास्थ्य एजेंसी के प्रमुख ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, 'मृत्यु की निरंतर संख्या के बावजूद, डेटा से पता चलता है कि स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और 60 से अधिक उम्र के लोगों के बीच टीका कवरेज में गिरावट आई है, जो सबसे अधिक जोखिम वाले समूहों में से दो हैं।'

डब्ल्यूएचओ की सिफारिश है कि उच्चतम जोखिम वाले समूहों के लोगों को उनकी आखिरी खुराक के 12 महीने के भीतर कोविड-19 वैक्सीन मिल जाए। डब्ल्यूएचओ को सात मिलियन से अधिक कोविड मौतों की सूचना दी गई है, हालांकि महामारी की वास्तविक संख्या कहीं अधिक मानी जाती है। कोविड-19 ने अर्थव्यवस्थाओं को भी तहस-नहस कर दिया और स्वास्थ्य प्रणालियों को पंगु बना दिया। टेड्रोस ने मई 2023 में अंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल के रूप में कोविड-19 की समाप्ति की घोषणा की, यह उस समय से तीन साल से अधिक समय बाद है जब 2019 के अंत में चीन के वुहान में पहली बार वायरस का पता चला था।

अब मनमर्जी नहीं, जनमर्जी चलेगी', संसद में बोले अखिलेश, जोड़ने वाली राजनीति की जीत हुई..

सपा नेता ने कहा कि हम जाति जनगणना के पक्ष में हैं। हम अग्निवीर योजना को कभी स्वीकार नहीं कर सकते। जब इंडिया गठबंधन सत्ता में आएगा तो अग्निवीर योजना खत्म कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि फसलों पर एमएसपी की कानूनी गारंटी लागू नहीं की गई है। बागवानी फसलों को भी एमएसपी दिया जाना चाहिए।

नीट-यूजी परीक्षा विवाद पर केंद्र पर तीखा हमला करते हुए, समाजवादी पार्टी के सांसद और प्रमुख अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि युवाओं को नौकरियों से वंचित करने के लिए सरकार द्वारा इस तरह के पेपर लीक किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए अखिलेश ने कहा, 'पेपर लीक क्यों हो रहे हैं? सच तो यह है कि सरकार ऐसा इसलिए कर रही है ताकि उसे युवाओं को नौकरी न देनी पड़े।' उन्होंने कहा कि युवाओं को नौकरी नहीं दी गई, बल्कि सरकार ने नौकरियां छीन ली

हैं। आरक्षण देने के नाम पर सरकारी नौकरियाँ नहीं दी जा रही हैं।

सपा नेता ने कहा कि हम जाति जनगणना के पक्ष में हैं। हम अग्निवीर योजना को कभी स्वीकार नहीं कर सकते। जब इंडिया गठबंधन सत्ता में आएगा तो अग्निवीर योजना खत्म कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि फसलों पर एमएसपी की कानूनी गारंटी लागू नहीं की गई है। बागवानी फसलों को भी एमएसपी दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अयोध्या की जीत भारत के परिपक्व मतदाता की लोकतांत्रिक जीत है। इसके साथ ही उन्होंने दम भरते हुए कहा कि ईवीएम पर मुझे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी नहीं है भरोसा, 80/80 सीटों में जीत जब तब भी भरोसा नहीं...ईवीएम का मुद्दा खत्म नहीं हुआ है।

उन्होंने कहा कि हर बात को जुमला बना देने वालों से जनता का भरोसा उठ गया है, इसीलिए बहुमत की सरकार नहीं है, यह सहयोग से चलने वाली सरकार है।

नए नेतृत्व होंगे तैयार, बनी रणनीति...

पार्टी छोड़कर गए नेताओं के लिए कांग्रेस ने बंद किए दरवाजे...

मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए नेताओं के लिए वापसी के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। कांग्रेस नए नेतृत्व तैयार करेगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी जहां विधानसभा और लोकसभा चुनाव में लगातार हार का सामना करना पड़ा है वही पार्टी छोड़ने वाले नेताओं की भी झड़ी लगी हुई कुछ नेता भाजपा में सही जगह नहीं मिलने से कांग्रेस में वापसी करना चाहते हैं लेकिन कांग्रेस एक बार पार्टी छोड़कर गए नेताओं के लिए रास्ते बंद कर दिए। निचले स्तर तक कांग्रेस अब नए नेतृत्व तैयार करेगी। कांग्रेस एक बार फिर संगठन में जान फूंकने की कोशिश कर रही है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में शनिवार और रविवार को चली मैराथन बैठक के बाद संगठन की मजबूती और जनता के बीच पकड़ बनाने के लिए रणनीति बनी है।

प्रदेश में अलग-अलग विभागों से भ्रष्टाचार की जानकारी सामने आ रही है, इसे लेकर कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। अब पार्टी ने तय किया है कि इन मुद्दों को ग्रामीण स्तर तक ले जाकर जनता को बताया जाएगा।पार्टी के सभी नेता अब भ्रष्टाचार पर सबसे अधिक ध्यान देंगे। कांग्रेस विभागवार गड़बड़ी का तथ्यात्मक चिट्ठा तैयार कर रही है । सभी विभाग का प्रजेंटेशन तैयार कर जनता को दिखाया और बताया जाएगा।

सदस्यता अभियान पर जोर : बैठक में तय किया गया है कि प्रदेश में पार्टी का विस्तार किया जाएगा। इसके लिए ग्रामीण स्तर तक सदस्यता अभियान चलाया जाएगा और युवाओं को पार्टी के साथ जोड़ने का काम किया जाएगा। प्रदेश में लगातार सदस्यता अभियान चलेगा। पार्टी का जोर नया नेतृत्व विकसित करने पर रहेगा। हर अंचल में अलग-अलग वर्ग का नया नेतृत्व तैयार किया जाएगा। इसमें अधिक से अधिक युवाओं को मौका दिया जाएगा।

पार्टी को मजबूत करने प्रत्याशियों ने दिए कई सुझाव : विधानसभा चुनाव हारे प्रत्याशियों और विधायकों ने कई पार्टी को मजबूत बनने के लिए कई सुझाव दिए हैं। जिसके बाद बैठक में तय किया गया है कि पार्टी पूरे जज्बे और मजबूती के साथ एक बार फिर जनता की आवाज बनेगी। राजनीतिक मामले की समिति में शामिल सदस्यों ने सभी सुझाव दिए हैं। इस आधार पर संगठन में बदलाव किया जाएगा। जनता के बीच पहुंचने के लिए अभियान चलाए जाएंगे। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भितरघात करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

कांग्रेस के संविधान के अनुसार बनेगी नई कार्यकारिणी: मध्य प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि 15 से 20 दिन के अंदर नई कार्यकारिणी घोषित कर दी जाएगी। खास बातें हैं कि प्रदेश की नई कार्यकारिणी कांग्रेस के संविधान के अनुसार बनेगी। यह पहले की तरह बहुत बड़ी नहीं होगी। जो पद जितनी संख्या में निर्धारित हैं, उतने पदाधिकारियों को ही मौका दिया जाएगा। साथ ही अब राज्य स्तर के पदाधिकारियों के दौरा कार्यक्रम पीसीसी से बनाए जाएंगे। जिला इकाइयों को अपना अधिक ध्यान ग्रामीण क्षेत्रों में लगाना होगा। चार वर्ष तक सशक्त विपक्ष की भूमिका पार्टी निभाएगी हर स्तर पर सामंजस्य बनाकर काम करना है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने बैठक में सुझाव दिया है कि जो लोग पार्टी से चले गए वह विचारधारा से अलग हो चुके हैं, उन्हें लेने की आवश्यकता नहीं है।

कम उम्र लड़कों के साथ लड़कियां भी करती है डेट, तो अकेले लड़के ही क्यों हो गिरफ्तार : हाईकोर्ट

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कम उम्र लड़के-लड़कियों की डेटिंग के मामले में शानदार तर्क दिया है। हाईकोर्ट ने डेटिंग मामले में दायर एक जनहित याचिका (PIL) में पुलिस कार्रवाई को लेकर भेदभाव पर सवाल खड़े किये हैं। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से सवाल करते हुए कहा कि, ''अगर कम उम्र की लड़के-लड़कियां साथ में डेट करते हैं और लड़की के माता-पिता शिकायत करते हैं तो क्या सिर्फ नाबालिग लड़के को ही गिरफ्तार किया जाना चाहिए?

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तराखंड हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस ऋतु बहारी और जस्टिस राकेश थपलियाल की बेंच ने उत्तराखंड सरकार से यह जांच करने को कहा कि क्या सीआरपीसी (CRPC) की धारा 161 के तहत बयान दर्ज करना लड़के को गिरफ्तार नहीं करने के लिए पर्याप्त है?

कोर्ट ने एक वकील मनीषा भंडारी की तरफ से दायर

PIL पर उत्तराखंड सरकार से सवाल किया है कि, क्या लड़के को गिरफ्तार करना जरूरी है? ऐसे मामले में उस लड़के को थाने बुलाकर यह सलाह देकर छोड़ दिया जा सकता है, जिससे वह भविष्य में ऐसा दोबारा न करें, लेकिन उसे गिरफ्तार करना गलत है।

साथ ही हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार ऐसे मामलों की जांच कर सकता है और पुलिस विभाग को सामान्य निर्देश जारी कर सकता है। वकील मनीषा भंडारी की इस दलील पर हाईकोर्ट ने सवाल किया है कि, सिर्फ लड़कों को ही क्यों हिरासत में लिया जाए और ऐसे मामले में तो उन्हें सिर्फ सलाह के लिए ही बुलाना पर्याप्त होना चाहिए। इस मामले में अगली सुनवाई 6 अगस्त को होगी। हाईकोर्ट में वकील मनीषा भंडारी ने PIL में लैंगिक असमानता पर कहा है कि, जहां लड़कियों को अक्सर सहमति से बने संबंधों में भी पीड़ित के रूप में देखा जाता है, तो दूसरी तरफ कम उम्र लड़कों को ऐसी चीज़ों के लिए अपराधी बताकर जेल भेज दिया जाता है। वकील भंडारी ने चीफ जस्टिस के सामने दावा किया कि हाल में उन्हें हलद्वानी जेल में 20 ऐसे लड़के मिले थे।

सांवेर रोड पर बन रही खुली जेल में बनेगा ओपन थिएटर और स्कूल...

कठोर सजा वालों के लिए बनेगी अंडा सेल

सांवेर रोड पर बन रही नई खुली केंद्रीय जेल के निर्माण को अब रफ्तार मिलने जा रही है। करीब 22 वर्ष पहले शुरू हुए इस प्रोजेक्ट के लिए कैबिनेट ने हाल ही में 217 करोड़ रुपए स्वीकृत किए है। यह जेल अन्य जेलों के मुकाबले खास है। यहां पर ओपन थिएटर से लेकर स्कूल तक बनेगा। इसके साथ कठोर सजा देने के लिए अंडा सेल भी बनाई जाएगी। फिलहाल यहां बाउंड्री वाल, वॉच टावर, किचन आदि का निर्माण कार्य किया जा चुका है। अफसरों के अनुसार, इस प्रोजेक्ट आगामी वर्ष तक पूरा कर लिया जाएगा। प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी खुली केंद्रीय जेल का प्रोजेक्ट 2002 में तैयार किया गया था। 51 एकड़ में फैले इस प्रोजेक्ट के लिए पुनर्धनत्चीकरण योजना के तहत कलेक्टर और गृह निर्माण मण्डल के बीच एमओयू हुआ था। जिसमें मप्र गृह निर्माण मंडल द्वारा नई जेल का निर्माण कराया जाना था।

बीते 11 साल से बंद था काम : 2008 तक 8.83 करोड़ रुपए की लागत से प्रशासनिक भवन, बाउंड्रीवाल और 21 आवास का निर्माण किया गया। इसके बाद राज्य शासन ने अनुबंध निरस्त कर दिया। करीब 11 वर्ष तक काम बंद रहने के बाद मार्च 2019 में राज्य मंत्री परिषद द्वारा केन्द्रीय जेल इंदौर के शेष निर्माण कार्य के लोक निर्माण विभाग के पीआईयू सेल का काम सौंपा गया। तब यहां 2000 बंदियों की क्षमता के लिहाज से 167.30 करोड़ रुपए की लागत निर्माण करने पर सहमति हुई।

मई 2019 को परियोजना परीक्षण समिति की बैठक में प्रस्तावित जेल की क्षमता बढ़ाकर 3041 बंदियों की गई।

20 बेड का अस्पताल : इसके बाद राज्य शासन ने जेल के कार्य को तीन चरणों में बांट दिया गया और लागत बढ़ाकर 208 करोड़ रुपए कर दी गई। 2020 में प्रथम चरण में 60 करोड़ रुपए जारी किए गए। जिससे जिसमें से 760 बंदियों के लिए दो बैरक, किचन शेड, वॉच टावर, 20 बेड का अस्पताल आदि कार्य का निर्माण कार्य किया गया।

अब होगा तेजी से काम : जानकारी के अनुसार कुछ माह पहले इस प्रोजेक्ट को लेकर हुई बैठक में खुली जेल में ओपन थिएटर, स्कूल, लांड्री और 102 आवास निर्माण का प्रस्ताव तैयार किया गया। दूसरे और तीसरे चरण का प्रस्तावित बजट 217.73 करोड़ रखा गया। जिसे हाल ही में कैबिनेट ने स्वीकृत कर दिया है।

▶ राशि जारी होते ही यहां 3041 बंदियों के लिहाज से निर्माण कार्य होंगे। जिसमें ओपन थिएटर, स्कूल, लांड्री, चार नए बैरक, महिला बैरक, दो अंडा सेल बनेगी। प्रोजेक्ट को पूरा के लिए मार्च 2026 तक लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

- अजय कुमार यादव, कार्यपालन यंत्री

मप्र में पहली बार शासकीय कॉलेज में एक साथ चार स्पेशलाइजेशन कोर्स

होलकर साइंस कॉलेज में छात्रों को मिलेगी सौगात

प्रदेश में ऐसा पहली बार हो रहा है, जब किसी शासकीय कॉलेज में पहली बार एक साथ चार स्पेशलाइजेशन कोर्स शुरू किए जा रहे है। छात्रों को इन कोर्स की सौगात इंदौर के होलकर साइंस कॉलेज में मिलेगी, जहां एआई(आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस), बीएससी इन नैनो टेक्नोलॉजी, बीएससी इन डेटा साइंस और बीएससी इन केमिस्ट्री इंफोर्मेटिक्स कोर्स शुरू होंगे।

चुनिंदा लैब करेंगे अपग्रेड : कॉलेज के प्रशासनिक अधिकारी डॉ। आरसी दीक्षित के अनुसार बीएससी के इन कोर्स में 80-80 सीटें रहेंगी। रिसर्च के लिए हम अपनी 50 में से कुछ चुनिंदा लैब को अपग्रेड भी करेंगे। कम से कम चार लैब ऐसी होंगी, जिनमें सिर्फ इन चारों स्पेशलाइजेशन से जुड़ी रिसर्च हो सकेंगी।

2025 में होगी शुरूआत :' डॉ. दीक्षित के मुताबिक हमारा प्रयास था कि इस सत्र से प्रवेश शुरू हो जाएं, लेकिन अभी तकनीकी व कागजी प्रक्रिया बाकी हैं और कॉलेजों में एडमिशन शुरू भी हो चुके हैं। इसलिए 2025 में इसकी शुरुआत होगी। ऑटोनॉमस होलकर कॉलेज को इसी साल फरवरी में नैक (नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन

काउंसिल) ए डबल प्लस ग्रेड मिली है। ऐसे में कॉलेज एकेडमिक विस्तार पर काम कर रहा है। उसी दिशा में यह चार नए कोर्स शुरू किए जाएंगे। कॉलेज ने इन कोर्स के सिलेबस, डिजाइन व सीटों को लेकर विस्तृत ब्योरा तैयार कर लिया है।

वर्तमान में हैं ये कोर्स : अभी कॉलेज में बीएससी कम्प्यूटर साइंस, बॉयोटेक्नोलॉजी, पीसीएम, बॉटनी सहित कुछ स्पेशलाइजेशन कोर्स हैं, लेकिन बीटेक में चलने वाले स्पेशलाइजेशन इक्का -दुक्का ही हैं।

क्वालिटी विजिटिंग फैकल्टी नियुक्त करेंगे : प्राचार्य डॉ. सुरेश सिलावट का कहना है कि इन कोर्स के लिए क्वालिटी विजिटिंग फैकल्टी की नियुक्ति भी करेंगे। कॉलेज के 100 स्थायी फैकल्टी में से दस डेटा साइंस, नैनो टेक्नोलॉजी व एआई से जुड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं।

क्या भविष्य की चिंता से हैं परेशान

क्यों खुदकुशी करने के लिए मजबूर हो रहे अग्निवीर..?

रिटायर्ड कर्नल रोहित चौधरी कहते हैं कि यह बहुत भयावह है कि एक साल के अंदर कई अग्निवीर शहीद हो चुके हैं। इनमें से ज्यादातर केस संदिग्ध हालात में मौत के हैं। वह सरकार से सवाल पूछते हैं कि अग्निपथ स्कीम के तहत भर्ती हुए अग्निवीर जवान लगातार सुसाइड क्यों कर रहे हैं? देश में इन दिनों सेना की अग्निपथ स्कीम जबरदस्त चर्चा में है। संसद से लेकर सोशल मीडिया तक अग्निवीरों का मुद्दा जम कर उठाया जा रहा है। अभी हाल में पंजाब के अग्निवीर अजय सिंह की शहादत के बाद उनके नेक्स्ट टू किन यानी परिजनों को मुआवजा राशि देने को लेकर संसद में खूब बवाल मचा। इसी बीच दो और अग्निवीरों की मौत की खबरें आ गईं। अभी एक साल में ही तकरीबन 20 अग्निवीरों की मौत हो चुकी है। हाल ही में आगरा में एयरफोर्स परिसर में अग्निवीर ने गोली मारकर खुदकुशी कर ली।

छुट्टी न मिलने से परेशान थे श्रीकांत : तीन जुलाई को आगरा एयरफोर्स परिसर के तकनीकी क्षेत्र में अग्निवीर वायु श्रीकांत कुमार चौधरी (22) ने सरकारी इंसास से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। हालांकि अभी तक आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है। श्रीकांत कुमार चौधरी पुत्र मनजी के पास सरकारी इंसास राइफल थी। जवान ने राइफल से आंख के पास गोली मारी थी। गोली सिर के ऊपरी हिस्से से निकल गई। हालांकि खुदकुशी की वजह एयरफोर्स की आंतरिक जांच में साफ होगी। सूत्रों ने सेना में लगभग 18 अग्निवीरों की मौत की पुष्टि की है। वहीं भारतीय वायुसेना में यह किसी अग्निवीर की पहली मौत है। वायुसेना सूत्रों ने बताया कि उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के रहने वाले 22 वर्षीय श्रीकांत कुमार चौधरी 2022 में अग्निवीर के तौर पर भारतीय वायुसेना में शामिल हुए थे। उनकी मौत के कारणों का पता लगाने के लिए कथित तौर पर एक जांच बोर्ड का गठन किया गया है। सूत्रों ने बताया कि श्रीकांत आगरा के वायुसेना स्टेशन पर मैनपावर की कमी के चलते छुट्टी न मिलने से परेशान थे।

अनिश्चित भविष्य से हैं दुखी : सेना से रिटायर्ड मेजर जनरल डॉ. यश मोर कहते हैं कि सेना को बैरकों में अग्निवीरों के जीवन की जमीनी हकीकत पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। वे दुखी हैं क्योंकि उनका भविष्य अनिश्चित है। लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। वह कहते हैं कि रेगुलर सैनिक के मुकाबले अग्निवीरों को साल में सिर्फ 30 दिन की छुट्टी मिलती है, जो बहुत गलत है। ऐसे हालात में कोई सेना में कैसे काम करेगा। हमें उनके प्रति सहानुभूति दिखानी चाहिए, ताकि वे खुदकुशी जैसा आत्मघाती कदम न उठाएं।

ठीक से नहीं हो रही है ट्रेनिंग

वहीं, रिटायर्ड कर्नल रोहित चौधरी कहते हैं कि यह बहुत भयावह है कि एक साल के अंदर कई अग्निवीर शहीद हो चुके हैं। इनमें से ज्यादातर केस संदिग्ध हालात में मौत के हैं। वह सरकार से सवाल पूछते हैं कि अग्निपथ स्कीम के तहत भर्ती हुए अग्निवीर जवान लगातार सुसाइड क्यों कर रहे हैं? सरकार बताए कि पिछले एक साल में कितने रेगुलर सैनिक शहीद हुए और जून 2023 से लेकर अभी तक सेना में कितने अग्निवीरों की शहादत हुई है? साथ ही सरकार ये बताए कि उन अग्निवीरों की मौत के पीछे क्या वजह रही है। उन्होंने ये आत्मघाती कदम क्यों उठाया। क्या उनकी ट्रेनिंग सही थी। क्या उनकी मैंटल कंडीशन ठीक थी? वह कहते हैं कि अग्निवीरों को मात्र छह महीने की ट्रेनिंग दे कर मोर्चे पर भेजा जा रहा है। वह कहते हैं ट्रेन सोल्जर कभी सुसाइड नहीं करता है। अगर अग्निवीर सुसाइड कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उनकी ट्रेनिंग ठीक से नहीं हो रही है। क्योंकि ट्रेनिंग उन्हें मजबूत बनाती है और हर तरह के हालात को झेलने की क्षमता देती है। वह कहते हैं कि अग्निवीरों का सुसाइड करना यह दिखाता है कि देश को कमजोर सैनिक दिए जा रहे हैं।

अग्निवीर अमृतपाल ने की थी सबसे पहले खुदकुशी

संयोगवश सेना में अग्निवीर की पहली मौत भी आत्महत्या से हुई थी, जिससे बड़ा विवाद खड़ा हो गया था। 11 अक्तूबर 2023 को पंजाब के रहने वाले अग्निवीर अमृतपाल सिंह की जम्मू-कश्मीर में ड्यूटी के दौरान मौत हो गई थी। पहले इसे संदिग्ध हालात में मौत बताया गया था, बाद में जांच से सामने आया कि अमृतपाल ने राजौरी सेक्टर में संतरी ड्यूटी के दौरान खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। वहीं उसे सेना की तरफ से गार्ड ऑफ ऑनर न मिलने को लेकर सवाल खड़े हुए थे। जिसके बाद सेना ने बताया था कि मृत्यु का कारण खुद को पहुंचाई गई चोट है, मौजूदा नीति के अनुसार कोई गार्ड ऑफ ऑनर या सैन्य अंतिम संस्कार प्रदान नहीं किया जाता है। सेना का स्पष्ट कहना है कि अगर कोई अग्निवीर सुसाइड कर लेता है, तो गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया जाएगा।

नियंत्रण से बाहर होती हमारी व्यवस्था

टूटी-फूटी सड़कों पर टोल टैक्स लेना ज्यादती है...

नियंत्रण से बाहर होती हमारी व्यवस्था हमारे लोक-जीवन को न केवल अस्त-व्यस्त कर रही है, बल्कि आहत, पीड़ित एवं परेशान भी कर रही है। ऐसी अनेक सुविधाएं हैं जो सरकार के द्वारा जनता के लिये उपलब्ध कराई जाती है, इसके लिये सरकार टैक्स वसूलती है।

बेहतर सेवाओं के नाम पर सरकारें कई तरह के शुल्क वसूलती है, इसमें कोई आपत्ति एवं अतिश्योक्ति नहीं है। लेकिन सेवाएं बेहतर न हो फिर भी उनके नाम पर शुल्क या कर वसूलना आपत्तिजनक एवं गैरकानूनी है। यह एक तरह से आम जनता का शोषण है, धोखाधड़ी है। राजमार्ग एवं अन्य मार्गों पर बेहतर एवं सुविधाजनक सड़कों के नाम पर एजेंसियों द्वारा टोल टैक्स वसूला जाता है, लेकिन विडम्बना एवं त्रासदी यह है कि टूटी-फूटी सड़कों के नाम पर भी टोल वसूला जाता है, जो अन्यायपूर्ण एवं आपत्तिजनक है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के हालिया बयान में जनता के इस बड़े होते दुःख, धोखाधड़ी एवं शोषण पर न केवल दुःख जताया बल्कि ऐसी जबरन की जा रही वसूली को रोकने के लिये अधिकारियों को चेताया है। अपनी बात को बेबाकी से कहने वाले नितिन गडकरी ने अधिकारियों को दो टूक शब्दों में कहा कि यदि सड़कें अच्छी हालत में न हों और लोगों को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हो, तो राजमार्ग पर एजेंसियों द्वारा टोल टैक्स वसूलने का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने कहा कि टोल टैक्स वसूलने से पहले हमें अच्छी सेवाएं देनी चाहिए। लेकिन हम अपने आर्थिक हितों की रक्षा के लिये टोल टैक्स वसूलने की जल्दी में रहते हैं। रोड टैक्स का उपयोग राज्य के भीतर सड़कों के रखरखाव और विकास के लिए किया जाना चाहिए न कि सरकार की आमद को बढ़ाने के लिये। ऐसे अनेक उदाहरण है कि बिना सुविधा एवं आवश्यकता के भी टोल टैक्स वसूला जा रहा है। राज्य सरकारें भी स्वतंत्र रूप से टोल वसूलती है। दूसरी ओर, टोल टैक्स एक उपयोगकर्ता शुल्क है जिसे वाहन मालिकों को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण या निजी ठेकेदारों को कुछ टोल सड़कों, जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, एक्सप्रेसवे, पुल और सुरंगों का उपयोग करने के लिए देना पड़ता है। जो अन्य सड़कों की तुलना में इन सड़कों को उच्च गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों की माना जाता है। निश्चित रूप से केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सड़क-क्रांति की है बल्कि व्यवस्था की खामियों को सुधारने के भी सराहनीय प्रयास किये हैं।

किसी देश को विवेकपूर्ण, बेहतर सुविधाओं एवं विकास के नये मानकों के साथ चलाने के लिए सरकार को पात्र नागरिकों से बेहतर सुविधाओं के लिये कर एकत्र में कोई ऐतराज नहीं है; लेकिन सड़कें हो या अन्य सुविधाएं, अच्छी नहीं होने पर भी टोल टैक्स या अन्य टैक्स वसूलने पर उपभोक्ता स्वयं को ठगा हुआ एवं शोषित महसूस करता है, जिसके कारण टोल टैक्स या अन्य टैक्स वसूलने वाली एजेन्सियों के खिलाफ शिकायतें बढ़ती जा रही है। टोल टैक्स प्रणाली सरकार या निजी ठेकेदारों के लिए राजस्व सृजन का स्रोत नहीं होनी चाहिए, बल्कि जनता के लिए बेहतर और सुरक्षित सड़कें उपलब्ध कराने का साधन होनी चाहिए। निश्चित तौर पर गुणवत्ता की सेवा दिए बिना कोई टैक्स वसूलना उपभोक्ता के साथ धोखाधड़ी एवं अन्याय है। यह बात हर सरकारी व निजी महकमे पर भी लागू होती है। लेकिन यथार्थ में ऐसा होता नहीं है और बेहतर सेवा के बिना टैक्स वसूलने की स्थितियां लगातार बढ़ती जा रही है। इन स्थितियों को लेकर आम जनता एवं उपभोक्ताओं में विरोध एवं विद्रोह पनप रहा है, इसलिये सरकार एवं ऐसी एजेन्सियों के खिलाफ लोग लोक अदालतों से लेकर विभिन्न अदालतों के दरवाजे खटखटाते रहते हैं। किसी भी विभाग को अपनी खामियों पर पर्दा डालने के बजाय सेवा में सुधार की पहल करनी चाहिए। अब चाहे मामला राष्ट्रीय राजमार्गों पर कार्यरत एजेंसियों का हो या फिर बिजली-पानी जैसे मूलभूत जरूरतों वाले विभागों का, अधिकारियों को उपभोक्ताओं के प्रति संवेदनशील एवं जिम्मेदार होना चाहिए।

नियंत्रण से बाहर होती हमारी व्यवस्था हमारे लोक-जीवन को न केवल अस्त-व्यस्त कर रही है, बल्कि आहत, पीड़ित एवं परेशान भी कर रही है। ऐसी अनेक सुविधाएं हैं जो सरकार के द्वारा जनता के लिये उपलब्ध कराई जाती है, इसके लिये सरकार टैक्स वसूलती है। लेकिन बिना सुविधा के भी टैक्स वसूलने की स्थितियां सरकार पर बदनुमा दाग है और ऐसे दाग लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बहरहाल बात राजमार्गों पर वसूले जा रहे गैर वाजिब टोल टैक्स के बढ़ने की चिन्ता का है, जो एक त्रासदी है। इसी त्रासदी को केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री ने स्वीकारा और कहा कि सड़कें अच्छी नहीं होने पर तमाम शिकायतें हमें मिलती हैं। दूसरी ओर सोशल मीडिया पर लोग अपना गुस्सा जाहिर करते हैं। सही मायनों में गुणवत्ता की सड़क प्रदान करने पर ही हमसे टोल वसूलने का अधिकार मिलता है। जाहिर सी बात है कि गड्ढों व कीचड़ वाली सड़कों पर टैक्स वसूलने पर पब्लिक की नाराजगी स्वाभाविक रूप से सामने आएगी।

आखिर कब सुधरेगी देश की डाक व्यवस्था...?

भारत में डाक सेवाओं की स्थापना 1774 में हुई। पहली बार भारतीय डाकघर को राष्ट्रीय महत्व के एक अलग संगठन के रूप में स्वीकार किया गया और उसे एक अक्टूबर 1854 को डाकघर महानिदेशक के सीधे नियंत्रण में सौंप दिया गया।

आजादी के 75 साल बाद भी भारत की डाक व्यवस्था में सुधार न होकर पतन ही हुआ। भारत में डाक विभाग 250 साल से पुराना है। आज गांव-गांव तक इसकी ब्रांच हैं। पूरे भारत में 155531 डाकघर हैं। इतना बडा नेटवर्क होने के बाद भी यह सरकारी विभाग प्राइवेट कोरियर कंपनियों से प्रतिस्पर्धा में पिछड़ती जा रही है। भारतीय डाक की सेवा में सुधार हो, इसमें न विभागीय अधिकारियों की रूचि है, न सरकार की। इसी का परिणाम है कि इसका अपने व्यवसाय से एकाधिकार टूटता जा रहा है। प्राइवेट कंपनी इसके व्यवसाय को कब्जाती जा रही हैं।

भारत में डाक सेवाओं की स्थापना 1774 में हुई। पहली बार भारतीय डाकघर को राष्ट्रीय महत्व के एक अलग संगठन के रूप में स्वीकार किया गया और उसे एक अक्टूबर 1854 को डाकघर महानिदेशक के सीधे नियंत्रण में सौंप दिया गया। भारतीय डाक व्यवस्था कई व्यवस्थाओं को जोड़कर बनी हैं। 650 से ज्यादा रजवाड़ों की डाक प्रणालियों, जिला डाक प्रणाली और जमींदारी डाक व्यवस्था को प्रमुख ब्रिटिश डाक व्यवस्था में शामिल किया गया था। इन टुकड़ों को इतनी खूबसूरती से जोड़ा गया है कि ऐसा प्रतीत होता है कि यह एक संपूर्ण अखंडित संगठन है।

1766 में लार्ड क्लाइव ने देश में पहली डाक व्यवस्था स्थापित की थी। इसके बाद 1774 में वारेन हेस्टिंग्ज ने इस व्यवस्था को और मजबूत किया। उन्होंने एक महा डाकपाल के अधीन कलकत्ता प्रधान डाकघर स्थापित किया। मद्रास और बंबई प्रेसीडेंसी में क्रमशः 1786 और 1793 में डाक व्यवस्था शुरू की गई। 1837 में डाक अधिनियम लागू किया गया ताकि तीनों प्रेसीडेन्सी में सभी डाक संगठनों को आपस में मिलाकर देशस्तर पर एक अखिल भारतीय डाक सेवा बनाई जा सके। 1854 में डाकघर अधिनियम के जरिए एक अक्टूबर 1854 को मौजूदा प्रशासनिक आधार पर भारतीय डाक घर को पूरी तरह सुधारा गया।

1854 में डाक और तार दोनों ही विभाग अस्तित्व में आए। शुरू से ही दोनों विभाग जन कल्याण को ध्यान में रख कर चलाए गए। लाभ कमाना उद्देश्य नहीं था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सरकार ने फैसला किया कि विभाग को अपने खर्चे निकाल लेने चाहिए। उतना ही काफी होगा। 20वीं सदी में भी यही क्रम बना रहा। डाकघर और तार विभाग के क्रियाकलापों में एक साथ विकास होता रहा। 1914 के प्रथम विश्व युध्द की शुरूआत में दोनों विभागों को मिला दिया गया।

भारतीय राज्यों के वित्तीय और राजनीतिक एकीकरण के चलते यह आवश्यक और अपरिहार्य हो गया कि भारत सरकार भारतीय राज्यों की डाक व्यवस्था को एक विस्तृत डाक व्यवस्था के अधीन लाए। ऐसे कई राज्य थे जिनके अपने जिला और स्वतंत्र डाक संगठन थे और उनके अपने डाक टिकट चलते थे। इन राज्यों के लैटर बाक्स हरे रंग में रंगे जाते थे ताकि वे भारतीय डाकघरों के लाल लैटर बाक्सों से अलग नज़र आएं।

1908 में भारत के 652 देशी राज्यों में से 635 राज्यों ने भारतीय डाक घर में शामिल होना स्वीकार किया। केवल 15 राज्य बाहर रहे, जिनमें हैदराबाद, ग्वालियर, जयपुर और ट्रावनकोर प्रमुख हैं।

1925 में डाक और तार विभाग का बड़े पैमाने पर पुनर्गठन किया गया। विभाग की वित्तीय स्थिति का जायजा लेने के लिए उसके खातों को दोबारा व्यवस्थित किया गया। उद्देश्य यह पता लगाना था कि विभाग करदाताओं पर कितना बोझ डाल रहा है या सरकार का राजस्व कितना बढा रहा है और इस दिशा में विभाग की चारों शाखाएं यानी डाक, तार, टेलीफोन और बेतार कितनी भूमिका निभा रहे हैं।

भारतीय डाक सेवा का क्षेत्र चिट्ठियां बांटने और संचार का कारगर साधन बने रहने तक ही सीमित नहीं है। शुरूआती दिनों में डाकघर विभाग, डाक बंगलों और सरायों का रख रखाव भी करता था। 1830 से लगभग तीस सालों से भी ज्यादा तक यह विभाग यात्रियों के लिए सड़क यात्रा को भी सुविधाजनक बनाते थे। कोई भी यात्री एक निश्चित राशि के अग्रिम पर पालकी, नाव, घोड़े, घोड़ागाड़ी और डाक ले जाने वाली गाड़ी में अपनी जगह आरक्षित करवा सकता था। वह रास्ते में पड़ने वाली डाक चौकियों में आराम भी कर सकता था। यही डाक चौकियां बाद में डाक बंगला कहलाईं। 19वीं सदी के आखिर में प्लेग की महामारी फैलने के दौरान, डाकघरों को कुनैन की गोलियों के पैकेट बेचने का काम भी सौंपा गया था। भारत संयुक्त परिवारों और छोटी आमदनी वाले लोगों का देश है, जहां लोगों को छोटी रकमों की सूरत में लाखों रूपए भेजने पड़ते हैं। रूपयों के लेन-देन का काम जिला मुख्यालयों में स्थित 321 सरकारी खजानों द्वारा किया जाता था।

मिलावट के लिए कंपनियां है जिम्मेदार, किसान नहीं...

खाद्य या आहार को किसी व्यक्ति के भरण-पोषण, विकास और वृद्धि के लिए मूलभूत आवश्यकता माना जाता है। हाल ही में राजस्थान के स् वास्थ्य विभाग द्वारा खाद्य पदार्थों में मिलावट के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत गुणवत्ता परीक्षणों में कई प्रमुख मसाला ब्रांड विफल रहे, जिसमें एमडीएच, एवरेस्ट, गजानंद, श्याम और शीबा ताजा जैसी प्रतिष्ठित कंपनियों के नमूने उपभोग के लिए अनुपयुक्त पाए गए। इनमें कीटनाशक के अवशेष और अन्य हानिकारक रसायन मिले हैं। यह पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी मिलावट की घटनाएं पाई गई हैं। ऐसी घटनाएं खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता के प्रति गंभीर चिंताओं को उजागर करती हैं, जो उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और वैश्विक व्यापार में भारत की साख पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं।

ऐसी समस्या के लिए अब किसानों को जिम्मेदार ठहराया जाने लगा है, क्योंकि वे अपनी फसल सुरक्षा और उत्पादन बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर रासायनिक का उपयोग करते हैं। लेकिन किसानों को दोषी ठहराना अनुचित है। यह एक जटिल और बहुआयामी समस्या है, जिसमें किसानों की भूमिका बहुत कम है। कई छोटे और सीमांत किसानों के पास आधुनिक कृषि पद्धतियों और सुरक्षित रसायनों के बारे में जानकारी की कमी होती है। ज्ञान और जागरूकता की कमी उन्हें अनजाने में हानिकारक रसायनों का उपयोग करने के लिए मजबूर करती है।

गंभीर आर्थिक दबाव में फंसे किसान अधिकतम उत्पादन के लिए तेजी से परिणाम देने वाले रसायनों का उपयोग करने के लिए मजबूर होते हैं। पर्याप्त निगरानी और प्रवर्तन की कमी के कारण, बाजार में हानिकारक और प्रतिबंधित रसायन आसानी से मिलते हैं। किसानों को अक्सर इन रसायनों की सुरक्षा और कानूनी स्थिति के बारे में नहीं बताया जाता है। निस्संदेह आज कृषि क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता है, जिसमें सरकार की नीतियों और संरचनात्मक बदलावों का महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। किसानों को सुरक्षित कृषि पद्धतियों की ओर प्रोत्साहित करने के लिए नीतिगत समर्थन, वित्तीय सहायता और उचित बाजार पहुंच आवश्यक है। इसके बिना, किसानों को दोषी ठहराना समाधान की दिशा में सही कदम नहीं माना जा सकता।

एक मजबूत ट्रेसिबिलिटी सिस्टम की कमी खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में मिलावट, संदूषण और अनैतिक प्रथाओं के लिए गुंजाइश बनाती है। सब्जियों और फलों में कीटनाशक अवशेषों की अधिक मात्रा, दूध उत्पादों में हानिकारक रसायनों की मौजूदगी और मसालों में मिलावट की घटनाएं स्थिति की गंभीरता को उजागर करती हैं। हालांकि इन चिंताओं को दूर करने के लिए फूड सेफ्टी ऐंड स्टैंडर्ड रूल्स, 2011 के संशोधन से ट्रेसिबिलिटी को अनिवार्य कर आपूर्ति श्रृंखला में खाद्य की उत्पत्ति और आवाजाही को ट्रैक करने की क्षमता पर जोर दिया गया है। यदि यह प्रणाली प्रभावी ढंग से लागू की जाती है, तो हर हितधारक को जवाबदेह बनाया जाएगा और यह प्रणाली मिलावट की प्रथाओं को रोकेगी और अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारत की साख बढ़ाएगी।

हालांकि, संभावित लाभों के बावजूद, 2011 का संशोधन काफी हद तक लागू नहीं हो पाया है, जिसके कारणों में बुनियादी ढांचे की कमी, लॉजिस्टिक चुनौतियां और छोटे व सीमांत किसानों को डिजिटल प्रणाली में एकीकृत करने की आवश्यकता शामिल है। खाद्य सुरक्षा मानकों के बारे में चिंताओं के कारण भारतीय कृषि निर्यात को खारिज कर दिया जाता है। इससे किसानों के लिए कम कीमतें और निर्यात के अवसर खत्म हो सकते हैं। यह विश्वसनीय उत्पादक और निर्यातक के रूप में भारत की छवि को कमजोर करती है।

इस समस्या के समाधान के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। किसानों को समर्थन और संसाधन प्रदान करना महत्वपूर्ण है, ताकि वे सुरक्षित और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाकर खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता को सुनिश्चित कर सकें। सरकार को बुनियादी ढांचे और क्षमता निर्माण में निवेश को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। उपभोक्ताओं को सुरक्षित भोजन की मांग करने के लिए सशक्त बनाया जाना चाहिए।

नए नेतृत्व होंगे तैयार, बनी रणनीति...

पार्टी छोड़कर गए नेताओं के लिए कांग्रेस ने बंद कर दिए दरवाजे...

मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए नेताओं के लिए वापसी के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। कांग्रेस नए नेतृत्व तैयार करेगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी जहां विधानसभा और लोकसभा चुनाव में लगातार हार का सामना करना पड़ा है वही पार्टी छोड़ने वाले नेताओं की भी झड़ी लगी हुई कुछ नेता भाजपा में सही जगह नहीं मिलने से कांग्रेस में वापसी करना चाहते हैं लेकिन कांग्रेस एक बार पार्टी छोड़कर गए नेताओं के लिए रास्ते बंद कर दिए। निचले स्तर तक कांग्रेस अब नए नेतृत्व तैयार करेगी। कांग्रेस एक बार फिर संगठन में जान फूंकने की कोशिश कर रही है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में शनिवार और रविवार को चली मैराथन बैठक के बाद संगठन की मजबूती और जनता के बीच पकड़ बनाने के लिए रणनीति बनी है।

प्रदेश में अलग-अलग विभागों से भ्रष्टाचार की जानकारी सामने आ रही है, इसे लेकर कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। अब पार्टी ने तय किया है कि इन मुद्दों को ग्रामीण स्तर तक ले जाकर जनता को बताया जाएगा।पार्टी के सभी नेता अब भ्रष्टाचार पर सबसे अधिक ध्यान देंगे। कांग्रेस विभागवार गड़बड़ी का तथ्यात्मक चिट्ठा तैयार कर रही है । सभी विभाग का प्रजेंटेशन तैयार कर जनता को दिखाया और बताया जाएगा।

पार्टी को मजबूत करने के लिए दिए कई सुझाव

विधानसभा चुनाव हारे प्रत्याशियों और विधायकों ने कई पार्टी को मजबूत बनने के लिए कई सुझाव दिए हैं। जिसके बाद बैठक में तय किया गया है कि पार्टी पूरे जज्बे और मजबूती के साथ एक बार फिर जनता की आवाज बनेगी। राजनीतिक मामले की समिति में शामिल सदस्यों ने सभी सुझाव दिए हैं। इस आधार पर संगठन में बदलाव किया जाएगा। जनता के बीच पहुंचने के लिए अभियान चलाए जाएंगे। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भितरघात करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

पार्टी से गए नेताओं के लिए दिग्विजय ने दिया सुझाव

पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने बैठक में सुझाव दिया है कि जो लोग पार्टी से चले गए वह विचारधारा से अलग हो चुके हैं, उन्हें लेने की आवश्यकता नहीं है। वहीं पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने कहा है कि अनुशासन ऊपर से नीचे की होना चाहिए और पारदर्शिता नीचे से। कोई भी हो अनुशासनहीनता पर सख्त कार्रवाई की जाए। जबकि पूर्व मंत्री सचिन यादव ने सुझाया कि जो लोग कांग्रेस छोड़ निर्दलीय लड़े, भले ही अच्छी स्थिति में रहे पर उन्हें दोबारा टिकट न दिया जाए। अरुण यादव ने सुझाव दिया कि मोर्चा व संगठनों को दिए कामों की निगरानी राज्य स्तर से होनी चाहिए।

सदस्यता अभियान पर जोर : बैठक में तय किया गया है कि प्रदेश में पार्टी का विस्तार किया जाएगा। इसके लिए ग्रामीण स्तर तक सदस्यता अभियान चलाया जाएगा और युवाओं को पार्टी के साथ जोड़ने का काम किया जाएगा। प्रदेश में लगातार सदस्यता अभियान चलेगा। पार्टी का जोर नया नेतृत्व विकसित करने पर रहेगा। हर अंचल में अलग-अलग वर्ग का नया नेतृत्व तैयार किया जाएगा। इसमें अधिक से अधिक युवाओं को मौका दिया जाएगा।

कांग्रेस के संविधान के अनुसार बनेगी नई कार्यकारिणी...

मध्य प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि 15 से 20 दिन के अंदर नई कार्यकारिणी घोषित कर दी जाएगी। खास बातें हैं कि प्रदेश की नई कार्यकारिणी कांग्रेस के संविधान के अनुसार बनेगी। यह पहले की तरह बहुत बड़ी नहीं होगी। जो पद जितनी संख्या में निर्धारित हैं, उतने पदाधिकारियों को ही मौका दिया जाएगा। साथ ही अब राज्य स्तर के पदाधिकारियों के दौरा कार्यक्रम पीसीसी से बनाए जाएंगे। जिला इकाइयों को अपना अधिक ध्यान ग्रामीण क्षेत्रों में लगाना होगा। चार वर्ष तक सशक्त विपक्ष की भूमिका पार्टी निभाएगी हर स्तर पर सामंजस्य बनाकर काम करना है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने बैठक में सुझाव दिया है कि जो लोग पार्टी से चले गए वह विचारधारा से अलग हो चुके हैं, उन्हें लेने की आवश्यकता नहीं है।

सिंहस्थ से पहले उज्जैन को जोड़ने वाली सड़कों का चौड़ीकरण किया जाएगा...

सिंहस्थ- 2028 से पहले धर्मनगरी उज्जैन को जोड़ने वाली सभी सड़कें चौड़ी, फोरलेन में तब्दील हो जाएंगी। उज्जैन 450 किलोमीटर लंबे मालवा-निमाड़ विकास पथ (इंदौर-धार-अलीराजपुर एक्सप्रेस-वे) से भी जुड़ जाएगा। काम चरणबद्ध तरीके से होगा। वित्तीय वर्ष 2024-25 में इस कार्य के लिए पर्याप्त राशि का बजट में प्रविधान किया गया है।

46.475 किलोमीटर लंबे इंदौर रोड फोरलेन को सिक्सलेन में बदलने का काम इसी वर्ष शुरू होने की उम्मीद है। अगले चरण में मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम (एमपीआरडीसी) ने 95 किलोमीटर लंबे नागदा-जावरा रोड, 36.49 किलोमीटर लंबे उज्जैन-मक्सी रोड, 14.3 किलोमीटर लंबे सिंहस्थ बायपास मार्ग को फोरलेन में तब्दील करना, 24 किलोमीटर लंबे उन्हेल-इंगोरिया मार्ग और 36 किलोमीटर लंबे इंगोरिया-देपालपुर मार्ग को टूलेन में तब्दील करना प्रस्तावित किया है।

अगली कैबिनेट मीटिंग में ये प्रस्ताव स्वीकृत होने की उम्मीद है। फिलहाल मध्यप्रदेश सरकार ने उज्जैन और उससे जुड़े 10 जिलों में अधोसंरचना विकास के लिए इस वर्ष 500 करोड़ रुपये खर्च करने को राशि का बजट में प्राविधान किया है। मालूम हो कि बीते तीन वर्ष में सरकार, उज्जैन को जोड़ते आगर रोड, देवास रोड मार्ग को फोरलेन में तब्दील कर चुकी है। बड़नगर-बुरहानपुर मार्ग, गरोठ मार्ग को फोरलेन में तब्दील करने का काम चल रहा है।

ग्रीन फिल्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाई-वे से आशय ऐसे मार्ग से है जो हरे मैदान और खेतों के बीच से गुजरेगा। मौजूदा मार्ग इससे प्रभावित नहीं होगा। ये मार्ग पब्लिक प्राइवेट पार्टनशिप हाईब्रिड एनयूटी आधार पर 102.80 किलोमीटर लंबा बनाया जाएगा, जिस पर सात बड़े और 26 छोटे पुल सहित 270 पुलिया, पांच फ्लाई ओवर, दो रेलवे ओवर ब्रिज भी बनाए जाएंगे। ये मार्ग जावरा में

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे से जुड़ जाएगा।

126 करोड़ रुपये से शहर की आंतरित सड़कों को चौड़ा किया जाएगा। गाड़ी अड्डा चौराहे से वीडी क्लाथ मार्केट, निकास चौराहा, खजूरवाली मस्जिद होकर केडी गेट, जूना सोमवारिया होकर शिप्रा नदी पर बने बड़े पुल तक तक का मार्ग 32 करोड़ रुपये से चौड़ा किया जाएगा। वीडी क्लाथ मार्केट, तेलीवाड़ा, ढाबा रोड होकर छोटे पुल तक का मार्ग 25 करोड़ रुपये से, तेलीवाड़ा से कंठाल चौराहे तक का मार्ग 6 करोड़ रुपये से, कोयला फाटक चौराहे से छत्री चौक, गोपाल मंदिर तक का मार्ग 25 करोड़ रुपये से, कर्कराज मंदिर से भूखी माता मंदिर मार्ग एवं बड़नगर रोड के लालपुल तक का मार्ग 20 करोड़ रुपये से चौड़ा किया जाएगा।

खजूरवाली मस्जिद से अब्दालपुरा, रवीन्द्रनाथ टैगोर मार्ग, जीवाजीगंज थाने से गणेश चौक तक का मार्ग साढ़े आठ करोड़ रुपये से, कालभैरव मंदिर से सिंहस्थ सरोवर गणेश मंदिर तक का मार्ग साढ़े चार करोड़ रुपये से और नानाखेड़ा से शांति पैलेस चौराहे तक का मार्ग साढ़े पांच करोड़ रुपये से चौड़ा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 117 करोड़ रुपये से माधव सेवा न्यास पार्किंग स्थल से चौबीस खंभा माता मंदिर तक 24 मीटर चौड़ी, 360 मीटर लंबी सड़क और नरसिंह घाट पुल तिराहे से रामघाट झलारिया मठ तक एवं बंबईवाला धर्मशाला से रामघाट तक 12 मीटर चौड़ी और 450 मीटर लंबी सड़क बनाई जाएगी। गदा पुलिया से लालपुल ब्रिज तक 24 मीटर चौड़ी और 1463 मीटर लंबी सड़क बनाई जाएगी। शंकराचार्य चौराहे से मुरलीपुरा तक फोरलेन सड़क बनाई जाएगी।

मैसर्स पलिया कन्स्ट्रक्शन कंपनी निर्माण क्षेत्र में एक अग्रणी नाम

मैसर्स पलिया कन्स्ट्रक्शन कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर इंजीनियर श्री अनूप शर्मा का जन्म वर्ष 1978 में जिला मुरैना मध्यप्रदेश में एक प्रतिष्ठित धार्मिक परिवार में हुआ था तथा उनके प्रेरणास्त्रोत पिताजी श्री द्वारिका प्रसाद पलिया है। इंजीनियर श्री अनूप शर्मा एक दूरदर्शी, आशावादी और उत्साही उद्यमी है, जिन्होंने वर्ष 2007 में पलिया कंस्ट्रक्शन कंपनी की नींव रखी। उन्होंने अपनी व्यावसायिक यात्रा अपने फूफाजी श्री ए.आर. शर्मा जी के मार्गदर्शन में प्रारंभ कर निर्माण कार्य की बारीकियों को सीखा।

मैसर्स पलिया कंस्ट्रक्शन कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर इंजीनियर श्री अनूप शर्मा ने हमारा देश हमारा अभिमान पत्रिका की वरिष्ठ संरक्षक दीदी डॉक्टर शालिनी कौशिक जी को पुष्पों का गुलदस्ता भेंट कर आशीर्वाद लिया साथ मैं उनके पुत्र एवं कंपनी के सह प्रबंधक इंजिनियर शिवम शर्मा ने भी पुष्प भेंट किए और आशीर्वाद लिया।

मैसर्स पलिया कन्स्ट्रक्शन कंपनी मध्यप्रदेश की सर्वश्रेष्ठ निर्माण और विकास कंपनियों में से एक है, जिसने श्री अनूप शर्मा के मार्गदर्शन में वर्ष 2007 से सरकारी विभागों के निर्माण कार्य और डवलपर की शानदार यात्रा शुरू की। वर्तमान में मैसर्स पलिया कन्स्ट्रक्शन कंपनी प्रायवेट एवं सरकारी क्षेत्र के निर्माण व्यवसाय में अग्रणी है तथा कंपनी ने इस समयावधि में मानक सिद्धांतों और नीतिगत कार्य प्रणाली के साथ मध्यप्रदेश के निर्माण और विकास में गुणवत्ता, सामर्थ तथा पारदर्शिता के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। मैसर्स पलिया कन्स्ट्रक्शन कंपनी द्वारा मध्यप्रदेश में निर्माण श्रृंखला में निरंतर स्टॉपडेम, सीसी रोड, न्यायालयीन एवं प्रशासनिक भवन तथा अन्य सभी प्रकार के निर्माण कार्य किए गए हैं। कंपनी द्वारा नरिसंहपुर जिला न्यायालय भवन, तहसील न्यायालय भवन गोटेगांव जिला नरसिंहपुर जिला न्यायालय भवन, जौरा जिला मुरैना, तहसील न्यायालय मेहगांव जिला भिण्ड, तहसील न्यायालय भवन पिछोर जिला शिवपुरी, माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय भवन जिला रीवा तथा कलेक्ट्रेट भवन जिला अलीराजपुर का कार्य पूर्ण गुणवत्ता के साथ निर्धारित समयावधि में पूर्ण किए गए हैं। जिस हेतु मध्यप्रदेश से सबसे भरोसेमंद सरकारी निर्माण होने के लिए उन्हें कई पुरस्कार एवं प्रशंसा पत्र प्राप्त हुए है।

मैनेजिंग डायरेक्टर श्री अनूप शर्मा ने विशेष चर्चा के दौरान विचार व्यक्त किया कि उनकी कंपनी का उद्देश्य सभी शासकीय परियोजनाओं का निर्माण कार्य उत्तम गुणवत्ता के साथ निर्धारित समयावधि में पूर्ण कर उत्कृष्टता प्रदान करता है। वर्तमान उनकी कंपनी द्वारा सीएम राइज स्कूल भवनों का निर्माण, पहाड़गढ़ जिला मुरैना, हर्राई जिला छिंदवाड़ा, नरवर एवं शिवपुरी,

हमारा देश हमारा अभिमान पत्रिका की वरिष्ठ संरक्षक दीदी डॉक्टर शालिनी कौशिक एवं संपादक मनोज चतुर्वेदी के साथ मैसर्स पलिया कंस्ट्रक्शन कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर इंजीनियर अनूप शर्मा एवं उनके पुत्र इंजिनियर शिवम शर्मा के साथ विशेष चर्चा

हमारा देश हमारा अभिमान पत्रिका के वरिष्ठ संरक्षक दीदी डॉक्टर शालिनी कौशिक एवं संपादक मनोज चतुर्वेदी के साथ मैसर्स पलिया कंस्ट्रक्शन कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर इंजीनियर श्री अनूप शर्मा एवं उनके पुत्र इंजिनियर शिवम शर्मा।

डिण्डोरी तथा रीवा जिले में त्योंथर एवं मनगवां में भी किया जा रहा है, इसके अतिरिक्त एमपी हाउसिंग बोर्ड का एक बड़ा प्रोजेक्ट रतलाम में पूर्ण गुणवत्ता के साथ सम्पूर्ण होने की दिशा में है। उपरोक्त निर्माण कार्यों के अतिरिक्त भी कंपनी द्वारा सड़क, शानदार डुप्लेक्सस, फ्लैट्स, प्रायवेट होटल्स और वाणिज्यिक संपत्तियों के साथ-साथ मध्यप्रदेश के सदूर ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्वक निर्माण कार्य किए जा रहे हैं।

श्री अनूप शर्मा के अनुसार उनकी कंपनी की प्रगति एवं बहुमुखी विकास में कंपनी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का उत्साहपूर्ण एवं सकारात्मक योगदान रहा है। वर्तमान में कंपनी का प्रबंध उनके पुत्र इंजीनियर शिवम शर्मा द्वारा भी कुशलतापूर्वक, नवीन कार्यशैली एवं आधुनिक तकनीकी के साथ उत्कृष्टता की ओर अग्रसर किया जा रहा है। श्री अनूप शर्मा द्वारा कंपनी की शाश्वत प्रगति के लिए मध्यप्रदेश शासन की पारदर्शी योजनाओं एवं संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिए गए सकारात्मक सहयोग एवं मार्गदर्शन के लिए भी हृदय से आभार ज्ञापित किया गया है।

हमारा देश हमारा अभिमान मासिक पत्रिका के परिवार की ओर से हम मैसर्स पलिया कन्स्ट्रक्शन कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री अनूप शर्मा, प्रेरणा स्त्रोत पिता श्री द्वारिका प्रसाद पलिया, उनके पुत्र शिवम शर्मा एवं समस्त सहयोगीगण के उत्तम स्वास्थ्य, उज्जवल भविष्य एवं समृद्धि की कामना करते हैं तथा विश्वास है कि आने वाले समय में वे पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी एवं मानक मापदण्डों के अनुरुप सभी निर्माण कार्य निश्चित समयावधि में पूर्ण कर कंपनी की प्रतिष्ठा में चार चांद लगाएंगे।

▪ इन्हीं शुभकामनाओं के साथ...

बैंक खातों से लेकर क्रेडिट कार्ड बिल के भुगतान तक के बदल गये नियम

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) नियमों में संशोधन की घोषणा की है। जिसके मुताल्लिक नए मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी नियम के तहत ट्राई ने यूनिक पोर्टिंग कोड जारी करने के लिए सात दिन की प्रतीक्षा अवधि शुरू की है...

क्या आपको पता है कि एक जुलाई 2024 से बैंक के खातों से लेकर क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट तक के नियम बदल जाएंगे। यदि नहीं तो यह जान लीजिए कि एक जुलाई 2024 से मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी), नेशनल पेंशन स्कीम, फास्टैग पर सेवा शुल्क, क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट सहित कई नियमों में बदलाव लागू हो जाएंगे, जिसका आपके वित्तीय सेहत पर भी असर पड़ेगा। इसलिए इनसे निपटने के लिए अपनी प्राथमिकताएं तय कर लीजिए, ताकि आपकी जिंदगी की राह आसान हो सके।

एनपीएस में सौदे वाले दिन ही होगा निपटान

पहला बदलाव यह हुआ है कि पेंशन कोष विनियामक एवं विकास प्राधिकरण ने एक जुलाई 2024 से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अंशधारकों के लिए सौदे वाले दिन ही निपटान की अनुमति दे दी है। कहने का तातपर्य यह कि दिन विशेष को सुबह 11 बजे तक ट्रस्टी बैंक द्वारा प्राप्त एनपीएस अंशदान उसी दिन निवेश किया जाएगा और ग्राहकों को भी उसी दिन से एनएवी का लाभ मिलेगा। गौरतलब है कि अब तक ट्रस्टी बैंक द्वारा प्राप्त योगदान का निपटान अगले दिन (टी+1) किया जाता है, जो कि 1 जुलाई से नहीं हो पाएगा।

एमएनपी नीति में हुआ बदलाव, बढ़ा सात दिन का इंतजार : दूसरा बदलाव यह हुआ है कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) नियमों में संशोधन की घोषणा की है। जिसके मुताल्लिक नए मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी नियम के तहत ट्राई ने यूनिक पोर्टिंग कोड जारी करने के लिए सात दिन की प्रतीक्षा अवधि शुरू की है। कहने का तातपर्य यह कि यदि आपका सिम किसी कारण वश खोता है या फिर चोरी चला जाता है तो आपको तुरंत नया नम्बर नहीं मिलेगा। बल्कि इसके लिए किसी भी व्यक्ति को अब सात दिन का इंतजार करना होगा। विभाग का कहना है कि इस नए प्रावधान का उद्देश्य सिम स्वैप तकनीक का इस्तेमाल कर हो रही धोखाधड़ी को रोकना है। उम्मीद है कि ऐसा होने से मोबाइल सिम धोखाधड़ी में कमी आएगी।

भारत बिल पेमेंट सिस्टम के जरिए होगा क्रेडिट कार्ड पेमेंट

तीसरा बदलाव यह हुआ है कि आरबीआई ने एक जुलाई 2024 से क्रेडिट कार्ड के बिल पेमेंट को लेकर नया नियम लागू किया है। जिसके मुताबिक अब एक जुलाई से सभी क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट भारत बिल पेमेंट सिस्टम (बीबीपीएस) के जरिये हो सकेंगे। इसका उद्देश्य पेमेंट के प्रोसेस को सुव्यवस्थित करना और इसकी सुरक्षा को बढ़ाना है। हालांकि सभी बैंकों ने अभी तक इसे लागू नहीं किया है। फिर भी नया प्रावधान लागू होते ही सभी बैंकों पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ेगा और वो इसे जल्द अपनाने को बाध्य हो जाएंगे।

महंगा होगा मोबाइल रिचार्ज : पांचवां बदलाव यह हुआ है कि आगामी 1 जुलाई 2024 से मोबाइल रिचार्ज भी महंगा हो जाएगा। इसी के मद्देनजर जियो, एयरटेल तथा वोडाफोन जैसी टेलिकॉम कम्पनियों ने अपने-अपने मोबाइल टैरिफ में बदलाव की घोषणा की है, जो जुलाई के पहले हफ्ते से ही ये लागू हो जाएंगे। इससे उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त भार पड़ेगा, जिसका असर मोबाइल उपयोग ग्राहक संख्या पर भी दृष्टिगोचर हो सकता है।

पीएनबी बंद करेगा खाता

छठा बदलाव यह हुआ है कि पीएनबी ने सालों से निष्क्रिय अपने ग्राहकों के बैंक खातों को अब बंद करने का फैसला किया है। जिसके दृष्टिगत यह तय हुआ है कि बीते तीन साल में बिना लेन-देन के ही चलने वाले सभी खाते बन्द कर दिए जाएंगे। हालांकि, बैंक ने 30 जून 2024 तक केवाईसी कराने वालों को इससे छूट दी थी। जिसकी अवधि आज ही समाप्त हो जाएगी और कल 1 जुलाई से नया नियम लागू हो जाएगा।

फास्टैग पर बढ़ेगा सेवा शुल्क का बोझ

चौथा बदलाव यह हुआ है कि फास्टैग उपलब्ध कराने वाली बैंकिंग कम्पनियों ने एक जुलाई 2024 से नए शुल्क लगाने का फैसला लिया है। जिसके मुताबिक अब उपभोक्ताओं को तीन महीने में टैग मैनेजमेंट, खाते में पैसा कम होने, भुगतान विवरण निकालने जैसे शुल्क अदा करने होंगे। चर्चा है कि इससे लाभुकों पर बोझ बढ़ेगा।

उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए राज्य बजट में शामिल किए जाएंगे शिक्षकों के सुझाव - मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

शिक्षक विद्यार्थी के मित्र व मार्गदर्शक, उनकी राष्ट्रनिर्माण में अहम भूमिका

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि शिक्षित और सक्षम नागरिक ही राष्ट्र की प्रगति का आधार होते हैं। शिक्षक विद्यार्थियों में राष्ट्रीयता की भावना और संस्कारों का समावेश कर उन्हें कर्तव्यनिष्ठ नागरिक बनने के लिए प्रेरित करते हैं और राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं।

श्री शर्मा रविवार को धौलपुर जिले के बाड़ी स्थित ग्राम बिजोली में राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) के प्रदेश महासमिति अधिवेशन को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शिक्षक अपने शिष्य का मित्र, मार्गदर्शक और प्रेरणास्रोत होता है। विद्यार्थी स्कूल में जो कुछ सीखते हैं वह उनके जीवन को दिशा देता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राचीन काल से ही हमारे समाज में शिक्षक का महत्व सर्वोपरि रहा है। हमारी संस्कृति में गुरु-शिष्य परम्परा का विशेष स्थान हैं। कबीर दासजी ने तो गुरु गोविन्द दोउ खड़े... दोहे के माध्यम से गुरु की महत्ता ईश्वर से भी अधिक बताई है। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि राजस्थान सरकार भी शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य में सरकारी स्कूलों के बनुयादी ढांचे को मजबूत करने, स्मार्ट क्लासरूम स्थापित करने तथा शिक्षकों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने पर जोर दिया जा रहा है। इससे विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक की मदद से उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल पाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने सभी वंचित वर्गों को शिक्षा मुहैया करवाने के लिए अंतरिम बजट में अल्प आय वर्ग, लघु/सीमांत/बंटाईदार किसानों और खेतीहर श्रमिकों के बच्चों को के.जी. से पी.जी. तक की निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया है।

श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा व्यवस्था को और अधिक बेहतर बनाने के लिए अपने आगामी बजट में शिक्षकों से उनके सुझाव आमंत्रित किए हैं। सर्वश्रेष्ठ सुझावों को सरकार बजट में शामिल करेगी। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत में शिक्षा के क्षेत्र में बड़े सुधार हो रहे हैं। विद्यार्थियों में रचनात्मकता और समस्या समाधान का कौशल विकसित करने के लिए केन्द्र सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 लाई है। यह शिक्षा नीति शिक्षा के क्षेत्र में एक नया अध्याय शुरू करेगी और शिक्षा प्रणाली को रोजगारोन्मुखी बनाने तथा विद्यार्थियों को 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करने में मदद करेगी। इस नीति के सफल क्रियान्वयन से भारत एक ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में उभरेगा।

श्री शर्मा ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद देश में उच्च शिक्षा संस्थानों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। आज देश में 21 आईआईएम, 23 आईआईटी, 22 एम्स हैं। पिछले 10 वर्षों में मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी लगभग दोगुनी हो गई है। हमारे प्रमुख संस्थानों के कैम्पस विदेशों में भी खुल रहे हैं। अबूधाबी में आईआईटी दिल्ली तथा तंजानिया में आईआईटी मद्रास का कैम्पस शुरू हो चुका है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षक संघ का भी दायित्व है कि वे शिक्षकों के हितों के साथ-साथ शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने का कार्य करें। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में तकनीकी विकास के साथ ही शिक्षण विधियों में बदलाव लाने की आवश्यकता है। श्री शर्मा ने कहा कि शिक्षकों की नागरिक होने के साथ ही शिक्षक के रूप में समाज के प्रति दोहरी जिम्मेदारी है। वे अपने आस-पास के प्रत्येक वंचित और जरूरतमंद को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के संकल्प को साकार करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। श्री शर्मा ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर उन्हें याद करते हुए कहा कि उनका जीवन राष्ट्र के लिए पूरी तरह समर्पित था। डॉ. मुखर्जी ने कश्मीर मुद्दे पर राष्ट्रवाद को सर्वोपरि रखते हुए तत्कालीन कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और गृहमंत्री श्री अमित शाह ने दृढ़ इच्छाशक्ति का परिचय देते हुए कश्मीर से धारा 370 हटाई।

कार्यक्रम को मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित करते हुए राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के क्षेत्र प्रचारक श्री निंबाराम ने कहा कि शिक्षक राष्ट्र को मजबूत करने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि आधुनिक शिक्षा पद्धति में राष्ट्रीयता का समावेश आवश्यक है, जिससे विद्यार्थियों में राष्ट्रप्रेम की भावना विकसित हो। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर, गृह राज्य मंत्री श्री जवाहर सिंह बेढम, राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) के राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री महेन्द्र कपूर सहित अन्य पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में शिक्षक तथा आमजन उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जारी किए निर्देश...

परिवहन क्षेत्र में किए बदलाव... चेक पोस्ट पर अब लागू होंगे नए नियम

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि राज्य के परिवहन क्षेत्र में कुछ बदलाव किए गए हैं। चेक पोस्ट संबंधी नई व्यवस्था शीघ्र लागू की जा रही है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार, सीएम यादव ने रविवार को मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों से जुड़े प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि परिवहन विभाग को नई व्यवस्था में आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाए।

यादव ने कहा कि एक जुलाई से अन्य प्रांतों की सीमा से लगते परिवहन चेक पोस्ट पर संबंधित जिला प्रशासन के साथ तालमेल कर अव्यवस्थाओं को दूर करने के लिए कदम उठाया गया है। मध्य प्रदेश सुशासन के लिए जाना जाता है। परिवहन व्यवस्था के संबंध में शिकायतें प्राप्त होने पर राज्य शासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। नई व्यवस्था से भारी वाहनों के संचालकों को किस प्रकार की असुविधा नहीं होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब सीमावर्ती जिलों में नई व्यवस्था में उड़न दस्ते कार्य करेंगे। बाहरी वाहनों के संचालकों को कोई समस्या नहीं आएगी। नई पारदर्शी व्यवस्था सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि परिवहन विभाग द्वारा महाविद्यालयों में विद्यार्थियों के ड्राइविंग लाइसेंस तैयार करने के लिए शिविर लगाए जाएं। यात्री बसों के संचालन में निर्धारित स्थान से बस चलाने के नियम का पालन किया जाए। समय सारणी का पालन किया जाए। ग्रामीण परिवहन सेवा को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया जाए। परिवहन क्षेत्र में चेक पोस्ट

के स्थान पर चेक पॉइंट रहेंगे। अन्य राज्यों से लगे जिलों में मोबाइल उड़नदस्ते कार्य करेंगे। कुल 45 चेक पॉइंट रहेंगे। प्रदेश में 211 होमगार्ड के लिए आवश्यक व्यवस्था हुई है, जो सेवाएं देंगे। उन्हें नई परिवहन व्यवस्था के अंतर्गत आवंटित जिलों में पदस्थ किया गया है। प्रदेश में गुजरात में लागू पैटर्न के अनुसार कार्य किया जाएगा।

परिवहन नाकों के स्थान पर मोबाइल टीम कार्य करेगी। प्रदेश के 26 जिलों में विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं। वीडियो कांफ्रेंस में मुख्य सचिव वीरा राणा, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय डॉ राजेश राजौरा, अपर मुख्य सचिव परिवहन एस एन मिश्रा, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव संजय कुमार शुक्ला, राघवेंद्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव जनसम्पर्क एवं विमानन संदीप यादव एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

स्कूलों में बिना अनुबंध चल रहे वाहनों की भी होगी जांच, कार्रवाई होगी...

शहर और जिले के स्कूलों में बिना अनुबंध के बच्चों को लाने ले जाने में लगे वाहनों की अब लगातार जांच होगी। जरूरत पड़ने पर पहली कार्रवाई इन्हीं पर होगी। प्रशासन का मानना है कि जो बस या वाहन स्कूलों से संबद्ध है, वहां तो हमारे पास जानकारी होती है, लेकिन जो बाहर से सेवाएं देते हैं, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। ज्यादातर शिकायतें इन्हीं वाहनों की होती है।

इनमें रिक्शा, ट्रेवलर और अन्य श्रेणी के वाहन शामिल हैं। इसी के साथ शहर के जिन 15 चिह्नित मार्गों पर फुटपाथ को अतिक्रमण मुक्त करने की मुहिम चल रही थी, वह अब अन्य मार्गों पर भी चलेगी। सरकारी ऑफिस में सुबह 10 से शाम 6 बजे तक अधिकारी-कर्मचारियों का काम करना अनिवार्य है। अधिकारी खुद इसका पालन करेंगे तो कर्मचारी भी करेंगे।

यह बात कलेक्टर आशीष सिंह ने सोमवार को

साप्ताहिक समीक्षा बैठक के बाद कही। सिंह ने कहा जिले के पालक भी अपने बच्चों को स्कूल में अनुबंधित वाहन के माध्यम से ही स्कूल भेजें। बगैर अनुबंध चलने वाले वाहनों के खिलाफ परिवहन विभाग के अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए। भिक्षावृत्ति के विरुद्ध चल रहे अभियान को लगातार चलाने के लिए कहा। उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे पौधारोपण के लक्ष्य को शीघ्र पूरा करें।

अरे मौसी 13 राज्यों में 0 सीटें आई हैं, पर हीरो तो है ना...

पीएम मोदी ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलते हुए कांग्रेस पर करारा प्रहार किया है। उन्होंने किस्से कहानियों का जिक्र कर कांग्रेस पर निशाना साधा। इस दौरान प्रधानमंत्री ने शोले फिल्म का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं की बयानबाजी ने 'शोले' फ़िल्म को भी पीछे छोड़ दिया है। उसमें एक मौसी जी थीं... तीसरी बार ही तो हारे हैं, पर मौसी मोरल विक्ट्री तो है ना। अरे मौसी 13 राज्यों में 0 सीटें आई हैं, पर हीरो तो है ना। अरे पार्टी की लुटिया तो डुबोई है, पार्टी अभी भी सांसें तो ले रही है।

16 राज्यों में कांग्रेस जहां अकेले लड़ी, वहां उसका वोट शेयर गिर चुका है। गुजरात, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, तीन राज्यों में जहां कांग्रेस अपने दम पर लड़ी और वहां 64 में से सिर्फ 2 सीट जीत पाई है। इसका साफ मतलब है कि इस चुनाव में कांग्रेस पूरी तरह परजीवी बन चुकी और अपने सहयोगी दलों के कंधे पर चढ़कर सीटों का आंकड़ा बढ़ाया है। कांग्रेस ने अपने सहयोगियों के जो वोट खाए हैं, अगर वो न खाए होते तो लोकसभा में उनके लिए इतनी सीटें जीत पाना भी बहुत मुश्किल था। जहां-जहां बीजेपी-कांग्रेस की सीधी फाइट थी, जहां कांग्रेस मेजर पार्टी थी, वहां कांग्रेस का स्ट्राइक रेट सिर्फ 26 परसेंट है। लेकिन जहां वो किसी का पल्लू पकड़ के चलते थे, ऐसे राज्यों में उनका स्ट्राइक रेट 50 परसेंट है। कांग्रेस की 99 सीटों में से ज्यादातर सीटें उनके सहयोगियों ने जिताया है और इसलिए कह रहा हूं कि ये परजीवी कांग्रेस है। अब कांग्रेस पार्टी 2024 से एक परजीवी कांग्रेस के रूप में जानी जाएगी। 2024 से जो कांग्रेस है, वो परजीवी कांग्रेस है और परजीवी वो होता है जो जिस

शरीर के साथ रहता है, उसी को ही खाता है। कांग्रेस भी जिस पार्टी के साथ गठबंधन करती है, उसी के वोट खा जाती है और अपनी सहयोगी पार्टी की कीमत पर वो फलती-फूलती है। यह मैं तथ्यों के आधार पर कह रहा हूं।

हमारा एकमात्र लक्ष्य है - Nation First. हमारी हर नीति, हर निर्णय और हर कार्य का एक ही तराजू रहा है - भारत प्रथम। विश्व के सबसे बड़े चुनाव अभियान में देश की जनता ने हमें तीसरी बार देश की सेवा करने का मौका दिया है। ये अपने आप में लोकतांत्रिक विश्व के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और गौरवपूर्ण घटना है। हमें हर कसौटी पर कसने के बाद देश की जनता ने ये जनादेश दिया है। जनता ने हमारे 10 साल के ट्रैक रिकॉर्ड को देखा है। जनता ने देखा है कि गरीबों के कल्याण के लिए हमने समर्पण भाव से 'जनसेवा ही प्रभुसेवा' के मंत्र को चरितार्थ करते हुए कार्य किए हैं।

'उच्छृंखल छात्र नेता' की तरह व्यवहार कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष राहुल : उमा भारती

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की वरिष्ठ नेता उमा भारती ने मंगलवार को कहा कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर अपना पहला भाषण देते समय एक उच्छृंखल छात्र नेता की तरह व्यवहार किया और उन्हें याद रखना चाहिए कि अब वह अधेड़ व्यक्ति बन चुके हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर निशाना साधते हुए कहा था कि जो लोग स्वयं को हिंदू कहते हैं वे ''हिंसा, नफरत'' में लिप्त हैं।

इसका सत्तापक्ष की ओर से जबर्दस्त विरोध जताया गया और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा था कि पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना बहुत गंभीर विषय है। इस पर राहुल गांधी ने कहा था, ''नरेन्द्र मोदी पूरा हिंदू समाज

नहीं हैं। भाजपा पूरा हिंदू समाज नहीं है। आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है।'' राहुल गांधी की संसद में की गई उपरोक्त टिप्पणी पर उमा भारती ने कहा कि हिंदू हिंसा के शिकार हुए हैं।

पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर पोस्ट किया, ''हिंदू या तो हिंसा के शिकार हुए हैं या हिंसा का सामना किया है। कल संसद में राहुल गांधी जी का व्यवहार एवं भाषण विपक्ष के नेता की तरह नहीं, किसी कॉलेज के उच्छृंखल छात्र नेता की तरह था। राहुल को याद रखना होगा कि वह दुर्भाग्य से विपक्ष के नेता चुन लिए गए हैं, दूसरा वह अब युवा नहीं है बल्कि 50 साल से ज्यादा के अधेड़ हैं। राहुल जी अपना पद, अपना देश और अपनी उम्र का कुछ तो ख्याल रखिए, पूरे देशवासियों के साथ मैं भी आपकी भर्त्सना करती हूं।

जल्द जारी होगी NEET PG 2024 एग्जाम की नई डेट, सूत्रों का दावा

दो घंटे पहले तैयार होगा प्रश्नपत्र

1 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्रालय में एक बैठक हुई जिसमें स्वास्थ्य मंत्रालय, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (एनबीईएमएस) के अधिकारियों के साथ-साथ इसके तकनीकी भागीदार टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) और साइबर सेल के अधिकारियों ने चर्चा की। राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा-पोस्ट ग्रेजुएट (एनईईटी-पीजी) 2024 के स्थगित होने के बाद, नई परीक्षा तिथियों की घोषणा के बारे में कई अटकलें और अफवाहें सामने आई हैं। हाल ही में, अधिकारियों के एक सूत्र से पता चला है कि स्नातकोत्तर प्रवेश के लिए मेडिकल प्रवेश परीक्षा अगस्त के मध्य में होने की संभावना है। इस सप्ताह परीक्षा की संशोधित तारीख घोषित होने की उम्मीद है। हालाँकि, सटीक तारीख अभी भी अनिश्चित है। सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक वेबसाइट देखते रहें।

NEET PG परीक्षा की संशोधित तारीख इस सप्ताह के अंत तक घोषित होने की उम्मीद है, परीक्षा अगस्त में आयोजित होने की संभावना है। परीक्षा आयोजित करने की प्रक्रिया इसरो के पूर्व अधिकारी डॉ. राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाले एक विशेषज्ञ पैनल को सौंपी गई है। एनईईटी पीजी आयोजित करने के लिए जिम्मेदार राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (एनबीई) वर्तमान में नई तारीखों को अंतिम रूप देने से पहले इस समीक्षा पैनल से मंजूरी का इंतजार कर रहा है। NEET PG परीक्षा, जो मूल रूप से 23 जून को होने वाली थी, NEET UG पेपर लीक विवाद के मद्देनजर परीक्षा की अखंडता पर चिंताओं के बाद स्थगित कर दी गई थी।

1 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्रालय में एक बैठक हुई जिसमें स्वास्थ्य मंत्रालय, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (एनबीईएमएस) के अधिकारियों के साथ-साथ इसके तकनीकी भागीदार

टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) और साइबर सेल के अधिकारियों ने चर्चा की। एनईईटी-पीजी के लिए तैयारी, जो ऑनलाइन आयोजित की जानी है। एक सूत्र ने कहा, ''एनईईटी-पीजी के अलावा, विदेशी मेडिकल स्नातक परीक्षा के संचालन के लिए प्रणाली की मजबूती का मूल्यांकन करने के लिए बैठक आयोजित की गई थी, जो 6 जुलाई को होने वाली है। सूत्रों ने बताया कि सोमवार की बैठक आने वाले दिनों में परीक्षा के संचालन के लिए प्रणाली की ''मजबूती'' की जांच करने के लिए आयोजित की गई थी। यह पता चला कि टीसीएस के शीर्ष अधिकारियों ने बैठक में परीक्षा प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी दी। 22 जून को, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कुछ प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की अखंडता पर आरोपों के मद्देनजर 'एहतियाती उपाय' के रूप में 23 जून को होने वाली NEET-PG प्रवेश परीक्षा स्थगित कर दी।

अब मनमर्जी नहीं, जनमर्जी चलेगी', संसद में बोले अखिलेश, जोड़ने वाली राजनीति की जीत हुई..

सपा नेता ने कहा कि हम जाति जनगणना के पक्ष में हैं। हम अग्निवीर योजना को कभी स्वीकार नहीं कर सकते। जब इंडिया गठबंधन सत्ता में आएगा तो अग्निवीर योजना खत्म कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि फसलों पर एमएसपी की कानूनी गारंटी लागू नहीं की गई है। बागवानी फसलों को भी एमएसपी दिया जाना चाहिए।

नीट-यूजी परीक्षा विवाद पर केंद्र पर तीखा हमला करते हुए, समाजवादी पार्टी के सांसद और प्रमुख अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि युवाओं को नौकरियों से वंचित करने के लिए सरकार द्वारा इस तरह के पेपर लीक किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए अखिलेश ने कहा, 'पेपर लीक क्यों हो रहे हैं? सच तो यह है कि सरकार ऐसा इसलिए कर रही है ताकि उसे युवाओं को नौकरी न देनी पड़े।' उन्होंने कहा कि युवाओं को नौकरी नहीं दी गई, बल्कि सरकार

ने नौकरियां छीन ली हैं। आरक्षण देने के नाम पर सरकारी नौकरियाँ नहीं दी जा रही हैं।

सपा नेता ने कहा कि हम जाति जनगणना के पक्ष में हैं। हम अग्निवीर योजना को कभी स्वीकार नहीं कर सकते। जब इंडिया गठबंधन सत्ता में आएगा तो अग्निवीर योजना खत्म कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि फसलों पर एमएसपी की कानूनी गारंटी लागू नहीं की गई है। बागवानी फसलों को भी एमएसपी दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अयोध्या की जीत भारत के परिपक्व मतदाता की लोकतांत्रिक जीत है। इसके साथ ही उन्होंने दम भरते हुए कहा कि ईवीएम पर मुझे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी नहीं है भरोसा, 80/80 सीटों में जीत जब तब भी भरोसा नहीं...ईवीएम का मुद्दा खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि हर बात को जुमला बना देने वालों से जनता का भरोसा उठ गया है, इसीलिए बहुमत की सरकार नहीं है, यह सहयोग से चलने वाली सरकार है।

आबादी की संरचना-आंकड़ों की सटीक जानकारी मिल सके

जनगणना इसलिए भी जरूरी... बेहतर और कल्याणकारी नीतियां बन सकें

अंतिम बार जनगणना 2011 में हुई थी। भारत ने द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान भी जनगणना करवाई थी, लेकिन 1981 से हर दस वर्ष में शुरू हुए जनगणना के क्रम को वर्ष 2020 में कोरोना महामारी के कारण स्थगित करना पड़ा। लेकिन, आश्चर्य की बात यह है कि चार साल बीत जाने के बावजूद हमारे पास अब भी जनगणना कराने के लिए समय नहीं है।

हम वर्ष 2024 का आधा पड़ाव पार कर चुके हैं। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार अपने तीसरे कार्यकाल के लिए सत्ता में वापसी कर चुकी है। लेकिन हर दस वर्ष में होने वाली जनगणना को लेकर अब तक कोई बात नहीं की जा रही। अंतिम बार जनगणना 2011 में हुई थी। भारत ने द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान भी जनगणना करवाई थी, लेकिन 1981 से हर दस वर्ष में शुरू हुए जनगणना के क्रम को वर्ष 2020 में कोरोना महामारी के कारण स्थगित करना पड़ा। लेकिन, आश्चर्य की बात यह है कि चार साल बीत जाने के बावजूद हमारे पास अब भी जनगणना कराने के लिए समय नहीं है। बांग्लादेश और ब्राजील ने अपनी अंतिम जनगणना 2022 में संपन्न कराई थी। अमेरिका और चीन, तो चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी अपनी जनगणना 2020 में ही करवा चुके हैं। जनगणना के माध्यम से ग्रामीण स्तर तक देश के लोगों की संख्या और जनसांख्यिकीय व सामाजिक-आर्थिक विशेषताओं की जानकारियां बड़े स्तर पर जुटाई जाती हैं।

इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माइग्रेशन ऐंड डेवलपमेंट, केरल से संबंधित दो प्रतिष्ठित जनसांख्यिकीविद एस. इरुदया राजन और यूएस मिश्रा ने हाल ही में टिप्पणी की, कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश भारत में जनसंख्या की गणना वास्तविक नहीं है। दरअसल, भारत की जनसंख्या के ज्यादातर अनुमान दशकों पुराने आंकड़ों पर आधारित हैं। भारत जब तक अपनी समुचित जनगणना नहीं करा लेता, तब तक हमारे पास सिर्फ अनुमान ही होंगे। जनगणना में देरी के पीछे जो भी कारण हों, लेकिन जनगणना के आंकड़ों की कमी एक गंभीर मसला है। यह न केवल शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं के लिए नुकसानदेह है, बल्कि जनगणना के आंकड़ों में देरी की वजह से कल्याणकारी कार्यक्रमों का क्रियान्वयन भी प्रभावित होता है। जैसा राजन और मिश्रा भी इंगित करते हैं कि 'सटीक जनसंख्या और जनसांख्यिकीय संरचना को जानना महत्वपूर्ण है, ताकि हम बेहतर नीतियों का मसौदा तैयार कर सकें।'

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) 2013 के अंतर्गत देश के करीब 81.35 करोड़ लोगों को 31 दिसंबर, 2028 तक मुफ्त राशन दिया जाएगा। यह राशन 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार दिया जा रहा है। सरकार के 2019 के बयान के आधार पर देश की 67 फीसदी आबादी यानी 80 करोड़ लोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के हकदार हैं। स्वतंत्र शोधकर्ताओं का अनुमान है कि मौजूदा समय में करीब 92 करोड़ लोग इस दायरे में आने चाहिए।

पार्षदों को चाहिए 'पहचान'

पहली बार बनाए जा रहे

आईडी कार्ड

पार्षद बोले- दूसरे क्षेत्रों में महसूस होती है जरूरत

भोपाल के पार्षदों को 'पहचान' चाहिए। यही वजह है कि नगर निगम शहर के सभी 85 पार्षदों के लिए पहचान-पत्र बनवा रहा है। इसके लिए महीनेभर से कवायद चल रही है। परिषद सचिव ने इसके लिए प्रस्ताव भेजा था। बताया गया है कि निगम ने इसके लिए तीन अलग-अलग डिजाइन तैयार भी करा लिए हैं। इन्हीं में से कोई एक फाइनल होगा। इसके आधार पर जल्द ही पार्षदों को पहचान-पत्र जारी किए जाएंगे। इससे पहले कभी पार्षदों को निगम की ओर से पहचान पत्र जारी नहीं किए गए हैं।

पहचान पत्र के जो डिजाइन तैयार कराए गए हैं उनमें पार्षद के नाम के साथ वार्ड संख्या, मोबाइल नंबर और वेलिडिटी जैसी बेसिक जानकारी ही दर्ज की गई हैं। लेकिन, कुछ एमआईसी सदस्य और जोन अध्यक्ष पहचान-पत्र में अपने नाम के साथ एमआईसी सदस्य और जोन अध्यक्ष भी लिखवाना चाहते हैं। इसको लेकर खींचतान चल रही है। निगम अधिकारी ये लिखवाने के पक्ष में नहीं है। सूत्रों की मानें तो जल्द ही यह पहचान पत्र प्रिंट भी हो जाएंगे। इन पर महापौर और कमिश्नर दोनों के हस्ताक्षर कराए जा सकते हैं।

पार्षदों से इस बारे में पूछने पर ज्यादातर ने पहचान पत्र की जरूरत से ही इनकार किया है। जबकि, कुछ पार्षदों का कहना है कि अपने क्षेत्र में तो लोग पहचानते ही हैं, लेकिन दूसरे वार्ड या शहरों में जाओ तो पहचान पत्र की जरूरत महसूस होती है।

▶ पार्षदों की ओर से यह मांग की गई थी कि उनको पहचान पत्र बनाकर दिए जाएं। इसी को ध्यान में रखते हुए पहचान पत्र दिए जा रहे हैं।

-हरेंद्र नारायण, कमिश्नर, नगर निगम

ई-बसें चलाने के लिए 120 करोड़ में बनेंगे एक दर्जन डिपो

मध्यप्रदेश के छह बड़े शहरों में जल्द दौड़ेंगी इलेक्ट्रिक बसें...

एमपी में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन को बढ़ावा देने की तैयारी है। प्रदेश में प्रदूषण कम करने के लिए तीन हजार ई- बस चलाने का टारगेट है। इसके लिए मप्र इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2024 भी बना ली गई है। इसमें ई-चार्जिंग स्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के साथ इलेक्ट्रिक बसें शुरू करने के लिए खास प्रावधान रखे गए है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने यह नीति तैयार कराई है। इसके लिए मोहन यादव कैबिनेट पहले ही फरवरी में पीएम ई बस सेवा के अंतर्गत प्रदेश के 6 बड़े शहरों में इसके संचालन का फैसला कर चुकी है। भोपाल-इंदौर सहित 6 शहरों में साढ़े पांच सौ अधिक इलेक्ट्रिक बसें (ई-बसें) चलाने के लिए करीब एक दर्जन डिपो बनाने की तैयारी की जा रही है।

नगरीय प्रशासन और विकास विभाग द्वारा ई-बसों के आपरेशन और बसों के केंद्र से डिमांड समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा करने के साथ एसओपी (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर) तैयार की गई है उसके अनुसार 6 शहरों में डिपो बनाने के लिए लगभग 120 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसमें लगने वाली 60 फीसदी राशि केन्द्र और 40 फीसदी राशि राज्य सरकार खर्च करेगी। इसके लिए राज्य सरकार को पहले अपने बजट में प्रावधान करना होगा। सरकार को इसी बजट सत्र में राशि आवंटित करनी पड़ेगी। केन्द्र सरकार 60 फीसदी राशि देने के साथ ईवी चार्जिंग स्टेशन, बिजली केबल और बिजली कनेक्शन में लगने राशि का भी खर्च उठाएगी। इधर इन शहरों में ईवी बसें चलाने के लिए केन्द्रीयकृत निविदा जारी हो गई है, जिसकी निविदा अगले माह तक फाइनल होगी। इसके चलते राज्य सरकार को जल्दी डिपो तैयार करना होगा, जिससे एक जनवरी से बसों का संचालन हो सके। इन बसों के संचालन से यात्रियों को कम किराये में परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

10 साल बाद फिर नर्सिंग पाठ्यक्रम के लिए बनेगा बोर्ड

जबलपुर स्थित मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय में मेडिकल पाठ्यक्रम ट्रांसफर हुए 10 साल बीत चुके हैं। इस दौरान नर्सिंग कॉलेजों में भारी गड़बड़ी और अनियमितताएं सामने आई है। कई कॉलेजों की मान्यता पर सवाल खड़े हुए हैं। इन सबके बीच उच्च शिक्षा विभाग के निर्देश के बाद देवी अहिल्या विश्वविद्यालय नर्सिंग पाठ्यक्रम की परीक्षा करवाने की तैयारी कर रहा है। इसके पहले विश्वविद्यालय प्रशासन को बोर्ड ऑफ स्टडीज और डीन तय करने होंगे। उसके बाद ही विश्वविद्यालय परीक्षा संचालित कर सकता है। इस संबंध में परीक्षा विभाग को आदेश मिल चुका है। इसके बाद बोर्ड ऑफ स्टडीज गठन करने की तैयारी शुरू कर दी गई है।

नए सिरे से तैयार करना होगा अध्यादेश : सप्ताह भर पहले विश्वविद्यालय की स्थायी समिति की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें नर्सिंग पाठ्यक्रम की परीक्षा करवाने पर सहमति बनी। 10 साल बाद दोबारा विश्वविद्यालय में नर्सिंग पाठ्यक्रम जोड़ा जा रहा है, मगर विश्वविद्यालय के दायरे में आने वाले कॉलेजों में पाठ्यक्रम संचालित करने को लेकर नए सिरे से अध्यादेश तैयार करना होगा।

▶ उसके लिए विश्वविद्यालय को बोर्ड आफ स्टडी गठित करना होगी। तीन से चार सदस्यों वाले बोर्ड को परीक्षा करवाने से जुड़े नियम और परीक्षा योजना बनाना होगी। नर्सिंग कोर्स के लिए डीन को पाठ्यक्रम भी तय करना होगा। नर्सिंग पाठ्यक्रम की परीक्षा करवाने के संबंध में निर्देश मिले है। उसके आधार पर बोर्ड आफ स्टडी गठित किया जा रहा है। इसके लिए शिक्षकों व प्राचार्यों के नाम मांगे है। यह प्रक्रिया अगस्त से पहले की जाएगी। परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम भी तैयार होगा।

- डॉ. विष्णु मिश्रा, सहायक कुलसचिव, डीएवीवी।

5 साल उद्यानिकी फसलों का बीमा नहीं, 3.47 लाख से अधिक किसान हो रहे प्रभावित...

मध्य प्रदेश में पिछले 5 साल से मौसम आधारित उद्यानिकी फसलों का बीमा नहीं किया जा रहा है। प्रतिवर्ष प्रदेश के तीन लाख 46 हजार से अधिक किसान फसल बीमा से वंचित रह जाते हैं। यह स्थिति तब है जब सरकार खेती से आय बढ़ाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने में लगी है। जबकि महाराष्ट्र जैसे राज्यों में किसानों को उद्यानिकी फसलों के बीमा कवरेज की व्यवस्था की गई है। वहीं, मप्र में वर्ष 2019 -20 से वर्ष 2023-24 तक फसलों का बीमा नहीं किया गया है। शुक्रवार को विधानसभा में पूर्व मंत्री व विधायक अर्चना चिटनीस ने उद्यानिकी फसलों का बीमा किए जाने का प्रश्न उठाया। उन्होंने कहा कि 5 साल से फसलों का बीमा क्यों नहीं किया जा रहा है।

मंत्री नारायण सिंह कुशवाह ने बताया ये कारण

जवाब में उद्यानिकी मंत्री नारायण सिंह कुशवाह ने बताया कि जल्द बीमा कराने का प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए अर्चना चिटनीस भी दिल्ली गई थीं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2020 से रबी 2022-23 के लिए छह बार टेंडर जारी किए गए थे, लेकिन दरें अधिक आने के कारण योजना का क्रियान्वयन नहीं किया जा सका। रबी 2022-23 से रबी 20223-24 के लिए निविदा आमंत्रित की गई, लेकिन एक ही निविदा प्राप्त होने के कारण निविदा नहीं खोली गई। खरीफ 2023-24 से रबी 2025-26 के लिए निविदा आमंत्रित की गई, लेकिन विभाग द्वारा केंद्र सरकार के नए दिशा-निर्देशानुसार आगामी कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए केंद्र से भी बात करके शीघ्र फसल बीमा कराने का प्रयास करेंगे।

16.41 लाख रुपए किसानों ने योजना का लिया था लाभ

बता दें कि वर्ष 2015 से 2019 तक मध्य प्रदेश के 21 लाख 31 हजार 919 किसानों फसल बीमा के लिए पंजीयन कराया था। इसमें से 16 लाख 41 हजार 685 किसानों ने उद्यानिकी फसल बीमा योजना का लाभ लिया। इसके बाद से बीमा बंद है।

बजट में मंडी टैक्स में नहीं मिली राहत, बार-बार की घोषणाएं अधूरी

मोहन सरकार के पहले पूर्ण बजट से प्रदेश का दाल-दलहन उद्योग निराश नजर आता है। दरअसल मध्य प्रदेश में बीते तीन-चार वर्षों से मंडी टैक्स की असमानता दूर करने की मांग हो रही है। इस संबंध में घोषणाएं भी सार्वजनिक मंचों से होती रही हैं।

मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले व्यापारियों के दबाव में तत्कालीन सरकार ने आंशिक राहत तो दी थी, लेकिन ताजा बजट में मंडी टैक्स में राहत का कोई ठोस ऐलान नहीं हुआ। मध्य प्रदेश में अनाज, दलहन और तमाम कृषि उपज पर 1.20 रुपये प्रति सैकड़ा की दर से मंडी टैक्स लागू हो रहा है।

कई बार मंडी टैक्स से राहत देने का ऐलान हुआ था

दाल उद्योग और आम किराना व थोक बाजार मंडी टैक्स की इस अधिक दर से परेशान नजर आता है। बीते साल मंडी टैक्स की अधिक दर को लेकर 16 दिन तक प्रदेश की मंडियों में हड़ताल भी की गई थी। इससे पहले तीन वर्षों में कम से कम तीन बार कृषि मंत्री ने भी सार्वजनिक मंचों से मंडी टैक्स में राहत देने का ऐलान किया, लेकिन उस पर अमल आज तक नहीं हो सका।

एमपी में 1 रुपये 20 पैसे लगता है मंडी टैक्स

मध्य प्रदेश में भले ही यहां उपजी फसल हो या बाहर से आयात की गई दलहन या कोई अनाज, सभी पर सरकार मंडी टैक्स वसूलती है। मंडी टैक्स की दर भी प्रदेश में सबसे ज्यादा बताई जाती है। आल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल के अनुसार मध्य प्रदेश में 1 रुपये 20 पैसे प्रति सैकड़ा मंडी टैक्स लगता है।

टैक्स लगने से बढ़ जाती है सभी चीजों की लागत

महाराष्ट्र में 80 पैसा प्रति सैकड़ा मंडी टैक्स लागू है। इसके मुकाबले गुजरात में 50 पैसे प्रति सैकड़ा ही मंडी शुल्क लगता है। इसी तरह उत्तर प्रदेश और बिहार में तो मंडी शुल्क शून्य है। ऐसे में हो यह रहा है कि यहां बनने वाली दाल या प्रोसेस होने वाले पोहे-चावल सभी की लागत इस टैक्स के लगने के कारण बढ़ जाती है।

कृषि उपज मंडियों की व्यवस्था के प्रति किसानों का विश्वास बरकरार रहे...

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में तुअर के उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाए। कोदो-कुटकी के रकबे को बढ़ाने से पानी-बिजली का उपयोग संतुलित होगा तथा फसल चक्र में भी सुधार होगा। अतः किसानों को कोदो-कुटकी की फसल लेने के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता है। फसल चक्र पर ग्रीष्मकालीन फसल लेने के नकारात्मक प्रभाव से भी कृषकों को अवगत कराना जरूरी है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव कृषक हितग्राही मूलक योजनाओं सहित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तथा कृषि विविधीकरण के लिए किया जा रहे प्रयासों पर मंत्रालय में आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री ऐदल सिंह कंषाना, मुख्य सचिव श्रीमती वीरा राणा उपस्थित थीं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि कृषि उपज मंडियों की व्यवस्था को चाक-चौबंद रखने के लिए वरिष्ठ अधिकारी मंडियों के तौल-काँटे, वित्तीय लेन-देन तथा अन्य व्यवस्था का आकस्मिक निरीक्षण करें। यह सुनिश्चित किया जाए कि किसानों के हितों से कहीं भी खिलवाड़ ना हो और मंडी व्यवस्था के प्रति किसानों का विश्वास बरकरार रहे। कलेक्टर कृषि उपज मंडी के संचालन पर भी निगरानी रखें। कहीं पर भी कृषि उपज मंडी में गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित सचिव जिम्मेदार होंगे, उनके विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने वेयरहाउस निर्माण व उपयोग के प्रावधानों में किसानों के हितों को सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक संशोधन करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश, जलवायु परिस्थितियों, मिट्टी और फसलों के विविध पैटर्न के साथ संपन्न है। हमारे किसान भाईयों की अथक मेहनत से प्रदेश कृषि विकास में सर्वोपरि है। हमारा प्रदेश दलहन व तिलहन के क्षेत्र तथा उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है। किसानों की आय में वृद्धि करने तथा कृषि को लाभ का धंधा बनाने की दिशा में हम निरंतर प्रयासरत हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से अधिक से अधिक सीमांत, लघु कृषकों को लाभ मिले यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सुधारात्मक उपाय किए जाएं।

रानी दुर्गावती श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पौष्टिक श्रीअन्न का उत्पादन बढ़ाने और इसकी पैदावार करने वाले कृषकों को प्रोत्साहित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि धान एवं गेहूँ के स्थान अन्य लाभकारी फसलें लेने के लिए फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित किया जाए। ऐसी फसलों को बढ़ावा दिया जाए जो सरकारी खरीद पर निर्भर नहीं हों और जिनका दाम बाजार व निर्यात की मांग से जुड़ा हो।

मोदी सरकार ने लागू किया नया कानून

पेपर लीक करने वालों को दस साल की जेल, एक करोड़ रुपये जुर्माना

नीट यूजी और यूजीसी नेट पेपर लीक होने के बाद सरकार पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। जहां एक तरफ छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं विपक्ष भी सरकार को घेर रहा है। इसी बीच सरकार ने पेपर लीक को लेकर केंद्र सरकार नया कानून लागू कर दिया है। जिसमें एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। दरअसल, केंद्र सरकार ने लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 यानी केंद्रीय भर्ती और केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए परीक्षाओं के लिए पेपर लीक विरोधी कानून को लागू कर दिया। कार्मिक मंत्रालय ने शुक्रवार को इसका गजट नोटिफिकेशन जारी किया। इस कानून के तहत अधिकतम दस साल की जेल और एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। यह कानून 21 जून से लागू हो गया है।

क्या है उद्देश्य-इस कानून का उद्देश्य सरकारी भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाओं और गड़बड़ियों को रोकना है। इसके साथ ही इसमें फर्जी वेबसाइट जैसी अनियमितताओं के खिलाफ भी सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

CSIR UGC NET भी रद्दः नीट और नेट का पेपर लीक होने के बाद अब एनटीए ने सीएसआईआर-यूजीसी-नेट परीक्षा जून 2024 को स्थगित कर दिया है। यह 25 से 27 जून के बीच आयोजित होने वाली थी। इस परीक्षा की तारीख आगामी कुछ दिनों में घोषित की जाएगी। इधर, मंगलवार यानी 18 जून को हुए यूजीसी नेट 2024 परीक्षा को 19 जून को रद्द कर दिया गया था। इस एग्जाम को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ही कराता है। सरकार ने परीक्षा में गड़बड़ी के कारण मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंपी है।

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सांसद शंकर लालवानी की लोक संस्कृति मंच संस्था पर 21 हजार रु. का जुर्माना

सांसद शंकर लालवानी की संस्था लोक संस्कृति मंच ने देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर की छवि धूमिल की है। 12 से 18 जून तक शहर की ऐतिहासिक धरोहर लालबाग पैलेस में संस्था द्वारा आयोजित मालवा उत्सव के दौरान फेंका गया कचरा शहर की स्वच्छता में दाग लगा रहा है। उत्सव के समाप्त होने के एक सप्ताह बाद भी कचरा परिसर में जहां-तहां पड़ा था। इससे उठने वाली बदबू से यहां आने वाले पर्यटकों का सांस लेना तक मुश्किल हो गया। हरियाणा से आई इंदौर की एक पर्यटक ने व्यथित होकर इस कचरे का वीडियो तक वायरल कर दिया। इसके बाद नींद से जागे इंदौर नगर निगम ने संस्था लोक संस्कृति पर 21 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। बहुप्रसारित वीडियो में महिला द्वारा कही गई बात से हर इंदौरी शर्मिंदगी महसूस करेगा। वीडियो में पर्यटक कह रही है कि वह अपने बच्चे के एडमिशन के सिलसिले में इंदौर आई थी। इंदौर देश का सबसे स्वच्छ शहर है। यहां की स्वच्छता से जुड़ी चर्चाओं को सुनकर वह बहुत प्रभावित थी और लालबाग पैलेस घूमने आ गई। यहां परिसर में बहुत गंदगी है और मुंह पर मास्क लगाए बगैर निकलना तक मुश्किल है। संस्था लोक संस्कृति मंच लालबाग पैलेस में प्रतिवर्ष मालवा उत्सव आयोजित करता है। सांसद लालवानी ही इस संस्था के कर्ताधर्ता हैं। सप्ताहभर चलने वाले इस आयोजन में रोजाना हजारों लोग आते हैं। इससे बड़ी मात्रा में कचरा भी निकलता है।

संस्था को इस कचरे के निबटान के लिए नगर निगम में एक निश्चित राशि जमा कराना होती है, लेकिन संस्था ने यह राशि जमा नहीं करवाई। नतीजतन कचरा परिसर में ही पड़ा रहा। आयोजन समाप्त हुए एक सप्ताह बीतने के बाद भी हालत जस की तस रही। इंदौर आई महिला का वीडियो बहुप्रसारित होने के बाद मंगलवार को इंदौर नगर निगम ने संस्था पर 21 हजार रुपये का जुर्माना लगाया और कचरा हटाया गया।

▶ हर वर्ष हम आयोजन से पहले ही निगम में शुल्क जमा कराकर रसीद कटवा लेते थे, लेकिन इस वर्ष ऐसा नहीं कर सके। जिस व्यक्ति के पास यह जिम्मेदारी थी, वह सीएसआई से समन्वय नहीं कर सका। हमसे कहा गया था कि बाद में रसीद काट देंगे। मैं फिलहाल दिल्ली में हूं। इंदौर आने पर इस मामले को दिखवाता हूं। -शंकर लालवानी, सांसद

52 साल बाद मोहन सरकार ने बदला नियम सीएम व मंत्री अब खुद भरेंगे इनकम टैक्स

मोहन यादव ने कहा कि विभिन्न सुरक्षा बलों में शहीदों के जीवनसाथी को 1 करोड़ रुपये मिलते हैं। हमने किसी भी पारिवारिक समस्या से बचने के लिए उस राशि को प्रदेश के किसी जवान के शहीद होने पर दी जाने वाली सहायता राशि में 50% शहीद की पत्नी और 50% राशि माता-पिता को दी जाएगी।

मध्य प्रदेश कैबिनेट ने मंगलवार को फैसला किया कि राज्य सरकार को इस तरह का बोझ उठाने के बजाय राज्य के मंत्रियों को अपना आयकर देना होगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक बयान में कहा कि कैबिनेट ने 1972 के उस नियम को खत्म करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत राज्य सरकार मंत्रियों के वेतन और भत्तों पर आयकर का भुगतान कर रही थी। कैबिनेट बैठक पर मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने कहा कि आज कई ऐसे फैसले लिए गए जिनका राज्य में दूरगामी असर होगा। सभी मंत्री अपने इनकम टैक्स का खर्च उठाएंगे।

राज्य यह खर्च नहीं उठाएगा।

मोहन यादव ने कहा कि विभिन्न सुरक्षा बलों में शहीदों के जीवनसाथी को 1 करोड़ रुपये मिलते हैं। हमने किसी भी पारिवारिक समस्या से बचने के लिए उस राशि को प्रदेश के किसी जवान के शहीद होने पर दी जाने वाली सहायता राशि में 50% शहीद की पत्नी और 50% राशि माता-पिता को दी जाएगी। राज्य के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कैबिनेट बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया कि मंत्री अपना आयकर खुद भरें।

इससे पहले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रालय में आयोजित बैठक में अधिकारियों के साथ औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के कार्यों की समीक्षा की। यादव ने अधिकारियों को उद्योगों के विकास के लिए समेकित योजना तैयार करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में सिर्फ मेट्रो ट्रेन द्वारा ही नहीं, आने वाले समय में वंदे मेट्रो, रोप-वे, इलेक्ट्रिक बस एवं केबल कार जैसे साधनों से और आवागमन अधिक सुगम होगा।

मप्र बोर्ड के स्कूलों में नौवीं कक्षा में 13 वर्ष से कम उम्र के विद्यार्थी प्रवेश नहीं ले सकेंगे...

प्रदेश के मप्र बोर्ड के सरकारी व निजी स्कूलों में नौवीं कक्षा में 13 साल से कम उम्र के विद्यार्थी प्रवेश नहीं ले सकेंगे। नौवीं कक्षा में प्रवेशित वर्ष में विद्यार्थी की उम्र 13 वर्ष पूर्ण होना आवश्यक है। मप्र माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) ने वर्ष 2024-25 के लिए नौवीं से 12वीं तक की प्रवेश नीति को जारी कर दिया है। नौवीं कक्षा में प्रवेश एक अप्रैल की स्थिति में 13 साल से कम उम्र में नहीं दिया जाएगा। साथ ही नर्सरी कक्षा में तीन साल से साढ़े चार वर्ष की उम्र में बच्चों को प्रवेश मिलेगा। प्रवेश के लिए उम्र की समय-सीमा को माशिमं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप तय किया है। अभी तक स्कूलों में पहली कक्षा में दिए गलत उम्र में प्रवेश नौवीं के नामांकन में परेशानी बन गया था।

दरअसल मप्र स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा पहली में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु पांच वर्ष की थी।राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा भी हर साल जारी निर्देशों में पांच वर्ष की न्यूतनम आयु के विद्यार्थियों को पहली कक्षा में प्रवेश देने के लिए सत्र की शुरुआत में निर्देश जारी करता था।

इसके अनुसार माशिमं भी नौवीं के नामांकन में न्यूनतम आयु 13 साल (5 प्लस 8) था, लेकिन कई विद्यार्थी सरकारी स्कूलों में आठवीं तक 12 वर्ष तक के थे। वर्तमान में माशिमं में नौवीं के नामांकन का कार्य चल रहा है। जिसमें 31 दिसंबर 2010 के बाद के जन्म लेने वाले विद्यार्थियों का नौवीं में नामांकन नहीं हो रहा है। इससे हजारों की संख्या में विद्यार्थियों का अभी तक नामांकन नहीं हो पाया है,जबकि नामांकन की अंतिम तिथि मंडल ने 30 सितंबर तक निर्धारित की है। वहीं नीति में 10वीं में बेस्ट आफ फाइव योजना समाप्त कर कुछ नए नियम जारी किए हैं। अब 10वीं के विद्यार्थी तीन भाषा के विषय में दो ले सकते हैं।एक विषय के रूप में नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क(एनएसक्यूएफ) से एक विषय लेना होगा।

अभी तक मप्र स्कूल शिक्षा विभाग प्रारंभिक कक्षा के नाम पर बच्चों को तीन से पांच साल की उम्र में आंगनबाड़ी में प्रवेश दिलाता था। इसके बाद विद्यार्थी न्यूनतम पांच से सात साल की उम्र में पहली कक्षा में प्रवेश लेते हैं ।आठवीं पास करने के बाद विद्यार्थियों की उम्र 13 साल होना चाहिए, लेकिन राज्य शिक्षा केंद्र ने पहली में न्यूनतम आयु पांच वर्ष से कम उम्र के विद्यार्थियों के प्रवेश भी ले लिए। इससे आठवीं तक निरंतर पढ़ते हुए इस साल हजारों विद्यार्थियों की उम्र 12 साल के आसपास रहता था।अब इन विद्यार्थियों का नौवीं में नामांकन 13 साल से कम उम्र होता था।साथ ही मप्र बोर्ड के कई निजी स्कूल दो या ढाई साल की उम्र में ही बच्चों का प्रवेश नर्सरी कक्षा में ले लेते थे।

फसलों की बढ़ी MSP पर सियासत, कमलनाथ बोले- किसानों के साथ छल कर रही भाजपा...

केंद्रीय कैबिनेट ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए खरीफ की 14 फसलों पर एमएसपी को मंजूरी दी गई है। इसे लेकर मध्य प्रदेश में सियासत शुरू हो गई है। जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया है।

साथ ही केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से पूछा कि इस इस धोखेबाजी के पीछे का क्या कारण है? कमलनाथ ने अपने एक्स पोस्ट पर लिखा, भाजपा सरकार का किसानों से छल जारी है। केंद्र सरकार ने धान के लिए जो नया एमएसपी जारी किया है वह 2300 रुपया प्रति क्विंटल है। जबकि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा ने किसानों को 3100 रुपया प्रति क्विंटल एमएसपी देने का वादा किया था।

भाजपा के वादे से 800 रुपए प्रति क्विंटल कम एमएसपी: कमलनाथ ने कहा है कि यह नया एमएसपी

किसानों को भाजपा के वादे से 800 रुपए प्रति क्विंटल कम एमएसपी दे रहा है। यह हाल तब है जब मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देश के कृषि मंत्री और मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं।

3100 रुपए प्रति क्विंटल धान के वादे पर वोट डाला : पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आगे लिखा कि मध्य प्रदेश के किसान भाइयों को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी झूठे वादों की राजनीति करती है। किसानों ने 3100 रुपये प्रति क्विंटल धान के वादे पर वोट डाला और आज उन्हें 800 रुपया प्रति क्विंटल कम दिया जा रहा है। मैं मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री से मांग करता हूं कि वे जनता के सामने आकर स्पष्ट करें कि आखिर इस धोखेबाजी के पीछे क्या कारण है? कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ इस धोखेबाजी को बर्दाश्त नहीं करेगी, अगर जल्द से जल्द किसानों को वादे के मुताबिक एमएसपी नहीं दिया गया तो कांग्रेस पार्टी हर स्तर पर इसके लिए संघर्ष करेगी।

पीएम मोदी ने कहा- भारत डिजिटल पेमेंट में सबसे आगे

जल्द बनेगा तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र दौरे पर रहे। पीएम मोदी ने शनिवार को कहा कि, भारत जल्द तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश भी बन जाएगा। इससे पहले उन्होंने मुंबई के गोरेगांव स्थित नेस्को प्रदर्शनी केंद्र में आयोजित एक समारोह में 29,400 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। भारत डिजिटल भुगतान में सबसे आगे- पीएम मोदी ने मुंबई के बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स में इंडियन न्यूजपेपर सोसायटी (INS) के सचिवालय आईएनएस टावर (INS Tower) का उद्घाटन करने के बाद जनता को संबोधित किया। पीएम मोदी ने इसका भी जिक्र किया कि कैसे भारत डिजिटल भुगतान (India Digital Payments) में अग्रणी बन गया है। मोदी ने कहा, ''एक समय था जब कुछ नेता कहते थे कि डिजिटल लेन-देन भारत के लिए नहीं है। उनकी यह पूर्व धारणा थी कि इस देश में आधुनिक तकनीक काम नहीं कर सकती।''

दुनिया देख रही लोगों की क्षमता- पीएम मोदी ने कहा,

''हालांकि, दुनिया देश के लोगों की क्षमताओं को देख रही है। आज भारत डिजिटल लेन-देन में नए कीर्तिमान बना रहा है। भारत के यूपीआई और आधुनिक डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की वजह से लोगों की जिंदगी आसान हुई है और उनके लिए एक देश से दूसरे देश में पैसे भेजना आसान हुआ है।''

2014 से पहले लोग नहीं जानते थे स्टार्टअप

पीएम मोदी ने कहा कि इंडियन न्यूजपेपर सोसायटी द्वारा किए गए प्रभावी काम से देश को लाभ होगा। उन्होंने कहा, ''मीडिया लोगों को उनकी ताकत से अवगत कराता है।'' उन्होंने यह भी कहा कि मीडिया की स्वाभाविक भूमिका विमर्श को शुरू करना है। मोदी ने कहा, ''2014 से पहले ज्यादातर लोग स्टार्टअप शब्द से अनजान थे, लेकिन मीडिया ने इसे घर-घर तक पहुंचा दिया।

हिंदू रीति से हुई शादी को लेकर हाई कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

रीति से नहीं हुई शादी तो मैरिज सर्टिफिकेट भी नहीं होगा मान्य

परिवार कोर्ट में लखनऊ में एक मामले को चुनौती दी गई है। इसमें चुनौती देने वाली युवती ने दलील दी थी कि प्रतिवादी एक धर्मगुरु है। युवती की मां और मौसी धर्मगुरु की अनुयायी थी। मामला वर्ष 2009 का है जब चुनौती देने वाली युवती और उसकी मां को धर्मगुरु ने अपने पास बुलाया।

उत्तर प्रदेश में हिंदू शादी को लेकर हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने धर्म गुरु द्वारा की गई धोखाधड़ी के कारण 18 वर्षीय युवती से की गई शादी को अमान्य घोषित कर दिया है। कोर्ट ने साफतौर पर कहा है कि अगर शादी हिंदू रीति रिवाज से नहीं हुई है तो उस शादी को मैरिज रजिस्ट्रार द्वारा जारी किए गए मैरिज सर्टिफिकेट या आर्य समाज मंदिर के सर्टिफिकेट से भी मान्य नहीं माना जा सकता है। ऐसी शादी का महत्व नहीं रह जाता और सर्टिफिकेट इसे मान्य नहीं साबित कर सकता।

बता दें कि परिवार कोर्ट में लखनऊ में एक मामले को चुनौती दी गई है। इसमें चुनौती देने वाली युवती ने दलील दी थी कि प्रतिवादी एक धर्मगुरु है। युवती की मां और मौसी धर्मगुरु की अनुयायी थी। मामला वर्ष 2009 का है जब चुनौती देने वाली युवती और उसकी मां को धर्मगुरु ने अपने पास बुलाया। दोनों से धर्मगुरु ने कागजात पर साइन करवाए और कहा कि वो उन्हें अपने धार्मिक संस्थान का नियमित सदस्य बनाना चाहता है। इसके बाद उसने उसी वर्ष तीन अगस्त 2009 को भी रजिस्ट्रार ऑफिस में दोनों को बुलाकर उनके साइन करवाए।

इसके कुछ दिन बाद धर्मगुरु ने युवती के पिता को बताया कि उसकी शादी पांच जुलाई को आर्य समाज मंदिर में युवती के साथ हुई है। तीन अगस्त को उन्होंने शादी रजिस्टर भी करवाई है। हालांकि युवती ने दावा किया की सभी दस्तावेज धोखे से बनवाए गए है। इसका विरोध भी किया गया। दोनों पक्षों की दलील सामने आने के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया कि शादी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर था। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा सात के तहत हिंदू रीति से वो शादी को साबित नहीं कर सका। ऐसे में शादी को संपन्न नहीं माना जा सकता है।

माता वैष्णो देवी के भक्तों को 6 साल तक मुफ्त होगी ये सेवा

माता वैष्णो देवी के दरबार में उनके भक्त जरुर जाते हैं। अगर आप भी मां वैष्णो देवी के मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि 6 सालों तक मुफ्त में होगी ये सेवा।

त्रिकुटा पहाडियों पर स्थित श्री माता वैष्णो देवी के भवन गुफा मंदिर के दर्शन करने वाले भक्तों को आगामी 6 सालों तक हर एक गुरुवार को मुफ्त में भोजन कराया जाएगा। यह हिमाचल के प्रसिद्ध उद्योगपति और समाज सेवी डॉ. महिंद्न शर्मा ने श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड कटरा को 1 करोड़ एक लाख रुपये की धन राशि दान में दी है। हिमाचल के प्रसिद्ध उद्योगपति और समाज सेवी डॉ. महिंद्न शर्मा ने यह राशि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अंशुल गर्ग को कटरा में आज एक करोड़ एक लाख रुपये का पंजाब नेशनल बैंक ड्राफ्ट में भेंट करके दी। इस दौरान उनका बेटा ध्रुव शर्मा और कंपनी के सी.ई ओ अमित झा मौजूद थे। वहीं, उन्होंने श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को 18 जुलाई 2024 से लेकर 3 अक्टूबर 2030 तक पड़ने वाले जितने भी गुरुवार है उस दिन श्रद्धालुओं को तारकोटे में लंगर प्रदान करने के लिए 31000 रुपए प्रति लंगर की धन राशि दान की है।

नवग्रहों में बृहस्पति को प्राप्त है देवगुरु का दर्जा, जानें कैसे इस ग्रह को करें मजबूत

गुरु का सम्मान करने पर गुरु ग्रह जातक के ज्ञान में वृद्धि करते हैं और शिक्षा आदि के क्षेत्र में सफलता मिलती है। ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति यानी की गुरु ग्रह को ज्ञान का कारक कहकर परिभाषित किया गया है। ज्योतिष शास्त्र में गुरु का सम्मान करने पर कुंडली में बैठे गुरु की स्थिति मजबूत होती है और व्यक्ति को इसके शुभ फल मिलते हैं। वहीं किसी से जाने या अंजाने में गुरु का अपमान होता है, तो गुरु कमजोर होता है और कुंडली में बैठे सबल ग्रह भी अच्छे परिणाम नहीं दे पाते हैं। बता दें कि नवग्रह में हर ग्रह किसी न किसी मानवीय रिश्ते या पद का प्रतिनिधित्व करते हैं। ज्योतिष में बृहस्पति गृह को देवताओं का गुरु माना जाता है। वहीं बृहस्पति को गुरु ग्रह भी कहा जाता है। गुरु ग्रह धरती पर सभी गुरुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। गुरु का सम्मान करने पर गुरु ग्रह जातक के ज्ञान में वृद्धि करते हैं और शिक्षा आदि के क्षेत्र में सफलता मिलती है। ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति यानी की गुरु ग्रह को ज्ञान का कारक कहकर परिभाषित किया गया है। गुरु ग्रह को सबसे ज्यादा शुभ ग्रह माना जाता है और इसकी दृष्टि कल्याणकारी होती है। कुंडली में गुरु ग्रह जिस स्थान को देखता है, उस स्थान के शुभ प्रभावों में वृद्धि करता है।

यदि किसी जातक की कुंडली में गुरु ग्रह उच्च यानी की बलवान होता है, तो ऐसा व्यक्ति ज्ञानवान और सद्गुण संपन्न होता है। क्योंकि बृहस्पति नवग्रह से सबसे ज्यादा शुभ ग्रह है। यह ग्रह विवाह और संतान का भी कारक है। अगर किसी जातक की शादी में देरी हो रही है, तो उसको गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु मंत्र प्राप्त करके गुरु पूजन करना चाहिए और गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। इससे विवाह में होने वाली देरी खत्म हो जाती है।

जिन जातकों की कुंडली में गुरु ग्रह कारक अवस्था में होता है, उनको गुरु पूर्णिमा के दिन दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में पुखराज या उपरत्न सुनहला धारण करना चाहिए। क्योंकि गुरु ग्रह के अशुभ होने पर जातक की शिक्षा में अवरोध आने लगता है। कन्या की कुंडली में गुरु ग्रह से उसके पति का विचार किया जाता है। जिस कन्या की कुंडली में गुरु ग्रह अशुभ यानी नीच के होते हैं, उसके विवाह में बाधा या रुकावट उत्पन्न होने लगती है। ऐसे में गुरु ग्रह के शुभ फल पाने के लिए जातक को गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। जिससे कि कुंडली में बैठा गुरु आपको शुभ फल दे सके।

सावन का महीना... जानिए भगवान शिव आराधना और उसका महत्व

हिंदू कैलेंडर में सावन का महीना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। सावन के महीने को बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है। सावन का पूरा महीना भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है और इस पूरे माह विशेष रूप से भगवान शिव की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन के महीने में पूरी सृष्टि की कमान भोलेनाथ के हाथ में होती है क्योंकि सृष्टि के पालक भगवान विष्णु चार महीनों के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। सावन के महीने में देशभर में कांवड़ की यात्राएं निकाली जाती हैं। आइए जानते हैं इस साल कब से सावन का महीना शुरू हो रहा है।

सावन कब से शुरू

वैदिक पंचांग के अनुसार श्रावण का महीना इस साल 22 जुलाई से आरंभ हो रहा है और इसका समापन 19 अगस्त को होगा। इस बार सावन के पहले सोमवार से ही सावन महीने की शुरुआत हो रही है। प्रीति योग में सावन का महीना शुरू होगा। प्रीति योग में पूजा-पाठ करने से सभी तरह के शुभ योगों की प्राप्ति होती है।

सावन सोमवार तिथि

सावन माह में आने वाले सोमवार का विशेष महत्व होता है। इस बार सावन में पांच सोमवार पड़ेंगे। 22 जुलाई को सावन का पहला सोमवार हैं, फिर 29 जुलाई को सावन का दूसरा, 5 अगस्त को सावन का तीसरा, 12 अगस्त को सावन का चौथा और 19 अगस्त को सावन का आखिरी सावन सोमवार होगा। इस वर्ष सावन महीने की शुरुआत और समाप्ति दोनों ही सोमवार से हो रही है।

सावन माह का महत्व

हिंदू धर्म में सावन का महीना बहुत ही खास होता है। ज्योतिष और धार्मिक दृष्टि से सावन का महीना बहुत ही फलदायी माना जाता है। सावन माह में भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। सावन के महीने में पड़ने वाला सभी सोमवार का विशेष महत्व होता है। इस माह में भगवान शिव की पूजा करने पर जीवन में सुख-संपन्नता आती है। इसके अलावा ऐसी मान्यता है कि देवी पार्वती ने भगवान शिव को पतिरूप में पाने के लिए कठोर व्रत, उपवास करके भगवान शिव को श्रावण माह में ही दोबारा से पाया। श्री विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र, शिवगण आदि सभी श्रावण में पृथ्वी पर ही वास करते हैं और सभी अलग-अलग रूपों में अनेकों प्रकार से शिव आराधना करते हैं। श्रावण मास में ज्योतिर्लिंगों का दर्शन एवं जलाभिषेक करने से अश्वमेघ यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है।

सावन शिवरात्रि 2024

हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर शिवरात्रि का व्रत रखा जाता है। ऐसे में सावन माह में पड़ने वाली शिवरात्रि का विशेष महत्व होता है। इस बार सावन माह में शिवरात्रि 02 अगस्त को पड़ रही है।

सावन : कांवड़ यात्रा

सावन के महीने में कांवड़ यात्राएं निकाली जाती है। सावन में हर जगह कांवड़ियों की लम्बी कतारें बम बम भोले के जयकारे लगाते हुए दिखतीं है। हर साल श्रावण मास में लाखों की तादाद में कांवडिये सुदूर स्थानों से आकर गंगाजल से भरी कांवड़ लेकर पदयात्रा करके अपने गांव वापस लौटते हैं इस यात्रा को कांवड़ यात्रा बोला जाता है। श्रावण की चतुर्दशी के दिन उस गंगा जल से अपने निवास के आसपास शिव मंदिरों में शिव का अभिषेक किया जाता है।

सावन मंगला गौरी व्रत

श्रावण मास भगवान शिव को समर्पित है और सावन का मंगलवार देवी पार्वती की पूजा के लिए श्रेष्ठ माना गया है। सावन के मंगलवार को मंगला गौरी यानी माता पार्वती की पूजा का विधान है। मंगला गौरी व्रत विशेष रूप से महिलाएं रखती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, देवी पार्वती ने इसी व्रत का पालन कर भगवान शिव को प्रसन्न किया था और उन्हें पति के रूप में प्राप्त किया था। इसलिए माना जाता है कि मंगला गौरी व्रत रखने से वैवाहिक जीवन में सुख एवं समृद्धि की प्राप्ति होती है।

मानसून में चाहिए खिली-खिली स्किन, तो चावल के आटे का करें इस्तेमाल

मानसून में मौसम में ह्यूमिडिटी लेवल बढ़ जाने से स्किन पर अधिक पसीने और ऑयल की समस्या होती है। ऐसे में सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप चावल के आटे का इस्तेमाल करें। आप चावल के आटे को दही या शहद के साथ मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बना लें। मानसून का मौसम आते ही स्किन से जुड़ी कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस मौसम में ना केवल स्किन में अधिक चिपचिपेपन का अहसास होता है, बल्कि स्किन में डलनेस और इचिंग जैसी शिकायतें भी होती है। यही कारण है कि इस मौसम में आपकी स्किन अतिरिक्त केयर मांगती है। अमूमन देखने में आता है कि मानसून के मौसम में लोग तरह-तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने लग जाते हैं। हालांकि, अगर आप चाहें तो नेचुरल तरीके से भी अपनी स्किन को पैम्पर कर सकते हैं।

अधिक ऑयल को करें कंट्रोल

मानसून में मौसम में ह्यूमिडिटी लेवल बढ़ जाने से स्किन पर अधिक पसीने और ऑयल की समस्या होती है। ऐसे में सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप चावल के आटे का इस्तेमाल करें। आप चावल के आटे को दही या शहद के साथ मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बना लें। अब आप अपनी स्किन को क्लीन करके इसे चेहरे पर समान रूप से लगाएं और धोने से पहले 15-20 मिनट के लिए छोड़ दें। यह अतिरिक्त ऑयल को सोखने में मदद करेगा, जिससे आपकी स्किन अधिक फ्रेश नजर आएगी।

स्किन को बनाएं ब्राइटन

अगर आपको मानसून में अपनी स्किन अधिक डल व बेजान नजर आ रही है तो आप चावल के आटे का इस्तेमाल करें और अपनी स्किन को ब्राइटन बनाएं। इसके लिए आप दो चम्मच चावल के आटे में एक चुटकी हल्दी और पर्याप्त दूध मिलाकर पेस्ट बना लें। चेहरे पर लगाएं, 15 मिनट के लिए छोड़ दें, फिर धो लें। जहां, हल्दी चेहरे को चमकदार बनाती है जबकि चावल का आटा स्किन को धीरे-धीरे एक्सफोलिएट करता है।

स्क्रब की तरह करें इस्तेमाल

मानसून के मौसम में स्किन को डीप क्लीनिंग की जरूरत होती है, इसलिए हर 15 दिन में स्क्रब करना बेहद जरूरी है। चावल का आटा एक जेंटल एक्सफोलिएटर की तरह काम करता है और गंदगी को दूर करता है। आप चावल के आटे से स्क्रब बनाने के लिए आटे में शहद और नींबू के रस की कुछ बूंदों को मिक्स करें। अब अपने फेस को क्लीन करके इस स्क्रब को लगाएं और बेहद हल्के हाथों से मसाज करें। अंत में, पानी की मदद से फेस क्लीन करें। अगर आपकी स्किन सेंसेटिव है तो आप चावल के आटे में गुलाब जल मिक्स करके स्क्रब बना सकते हैं।

त्वचा के लिए सबसे बेहतर क्या है बीयर या वाइन...?

क्या आप ने कभी सोचा है बीयर और वाइन पीने से स्किन को सबसे ज्यादा फायदा होता है? वैसे तो बीयर और वाइन पीने के कई नुकसान होते हैं। लोग अक्सर इसने न पीने की सलाह देते हैं। लेकिन ये स्किन के लिए फायदेमंद होता है, आइए जानते हैं कैसे?

आमतौर पर लोग बीयर या वाइन जरुर पीते होंगे। लेकिन कभी किसी ने नहीं सोचा होगा कि बीयर और वाइन पीने से स्किन को सबसे ज्यादा फायदा होता है। वाइन मुख्य रुप से एक मादक पेय है जो खमीर के साथ किण्वित फल से बनाया जाता है। वहीं, बीयर एक अल्कोहलिक पेय है। इसमें चावल, जई, गेहूं और मक्का भी होता है।

क्या वाइन त्वचा के लिए बेहतर है? : आप ने कभी नहीं सोचा होगा कि वाइन टैनिन और फ्लेवोनोइड जैसे एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है। जो त्वचा में कोलेजन को बहाल करती है और उम्र बढ़ने के संकेतों से लड़ती है। स्किन को हेल्थी रखती है। इसके साथ ही वाइन में पॉलीफेनोल्स होते हैं जो बेजान त्वचा को ठीक करते हैं और हमारी त्वचा को चमक देता है। यह हमारी त्वचा को फुंसियों से भी बचाता है।

क्या बीयर त्वचा को बेहतर करती है? : यह सच है कि बीयर त्वचा के लिए अच्छी होती है। क्योंकि, यह त्वचा को पोषण देती है और विटामिन बी से भरपूर होती है जो त्वचा को स्वस्थ और पोषित बनाता है। बीयर विटामिन से भरपूर होता है। जो त्वचा के प्राकृतिक चमक लाती है और त्वचा के पीएच संतुलन को बनाए रखते हुए नेचुरल फेस क्लींजर की तरह काम करती है।

आपकी त्वचा के लिए दोनों में से क्या बेहतर है? : फ्रेश रेड वाइन का सेवन और बीयर दोनों ही त्वचा के लिए समान लाभ प्रदान करते हैं। याद रहे कि दोनों का सेवन सीमित मात्रा में करें अन्यथा इसके दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं।

बीयर और वाइन के नुकसान : चाहे बीयर हो या वाइन, दोनों ही सेहत को अलग-अलग तरह से नुकसान पहुंचा सकते हैं। इससे लिवर से लेकर अन्य अंगों पर ज्यादा दुष्प्रभाव देखने को मिलता है।

मानसून में अपनी थाली से बाहर ही रखें ये दालें

मानसून के मौसम के दौरान उड़द दाल का सेवन करना अच्छा नहीं माना जाता है। दरअसल, उड़द दाल भारी होती है और पचने में ज़्यादा समय लेती है, जिससे पेट फूलना, गैस और अपच जैसी पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं।

दालों का सेवन करना सेहत के लिए काफी अच्छा माना जाता है। दालें प्रोटीन सहित कई तरह के पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं, जो आपकी सेहत का अधिक बेहतर ख्याल रखती हैं। हालांकि, जब आप दाल को अपनी थाली का हिस्सा बना रहे हैं तो आपको मौसम का भी खास ख्याल रखना चाहिए। दरअसल, जब मानसून का मौसम आता है तो कुछ दालों से बचना ही बेहतर माना जाता है।

ऐसा इसलिए है, क्योंकि इस मौसम में अधिकतर लोगों को गैस, पेट फूलना और एसिडिटी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में वे अगर कुछ खास तरह की दालों का सेवन करते हैं तो इससे उनके पाचन तंत्र पर अधिक दबाव पड़ सकता है और ऐसे में उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए आज इस लेख में हम आपको ऐसी ही कुछ दालों के बारे में बता रहे हैं, जिन्हें आप मानसून में अवॉयड करें-

उड़द दाल : मानसून के मौसम के दौरान उड़द दाल

का सेवन करना अच्छा नहीं माना जाता है। दरअसल, उड़द दाल भारी होती है और पचने में ज़्यादा समय लेती है, जिससे पेट फूलना, गैस और अपच जैसी पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा, मानसून के दौरान ह्यूमिडिटी बढ़ने से बैक्टीरिया और अन्य रोगजनक अधिक आसानी से पनपने लगते हैं, जिससे संदूषण और संक्रमण का जोखिम बढ़ जाता है।

चना दाल : मानसून में लोगों को चना दाल खाने से बचना चाहिए या फिर इसका सेवन बेहद ही सीमित मात्रा में करना चाहिए। चना दाल को गैस और पेट फूलने का कारण माना जाता है। मानसून का आर्द्र मौसम इन लक्षणों को और बढ़ा सकता है। इसके अलावा, उड़द दाल की तरह, चना दाल भी अपेक्षाकृत भारी और पचाने में मुश्किल होती है, जो मानसून के दौरान पाचन तंत्र पर बोझ डाल सकती है।

लाल मसूर दालः सेहत के लिए लाल मसूर दाल बेहद गुणकारी मानी गई है। इसमें प्रोटीन, फाइबर, पोटैशियम, मैग्नीशियम, आयरन और विटामिन सी और बी होते हैं। लाल मसूर दाल में फाइबर और पोटेशियम भरपूर मात्रा में होता है, जो इसे दिल और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने के लिए एक अच्छा विकल्प बनाता है। लेकिन इसमें मौजूद रैफिनोज़ और स्टैचियोज़ जैसी शुगर के कारण पेट फूल सकता है, जिन्हें पचाना मुश्किल होता है।

डायबिटीज है तो फल और सब्जियां भी पहुंचा सकती हैं नुकसान...

इस मौसम में ढेर सारे फल-सब्जियां आती हैं, मगर डायबिटीज रोगियों को कई फल-सब्जी नुकसान भी करते हैं। ऐसे में उन्हें किन खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए? मधुमेह यानी डायबिटीज जीवन-शैली से जुड़ी एक ऐसी बीमारी है, जो खान-पान से सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। आप भले ही दवाएं ले रही हों या इंसुलिन, लेकिन आपकी डाइट में क्या शामिल है, आप क्या खाती हैं और क्या नहीं, यह बेहद मायने रखता है। अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन (एडीए) के अनुसार, इस मौसम में जिन फलों, सब्जियों और पेय में फाइबर के साथ विटामिन की भरपूर मात्रा होती है और केमिकल कम होता है, उन का सेवन डायबिटीज रोगियों के लिए लाभकारी होता है।

कौन-कौन से फल : डायबिटीज के मरीजों को कुछ चुनिंदा फल खाने की ही अनुमति होती है, जिनमें से वे तरबूज, बेरीज, कीवी और अमरूद खा सकते हैं, क्योंकि इनका जीआई टैग कम होता है और ये ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रण करते हैं। इन फलों में कई महत्वपूर्ण पोषक तत्व, जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, विटामिन सी, विटामिन ए, आयरन, कैल्शियम और पोटैशियम की अच्छी मात्रा होती है, जो आपको ऊर्जा के साथ-साथ ठंडक भी देती है।

गर्मियों में इन फलों के साथ कई तरह की बेरीज बाजार में मिलती है, जैसे कि स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी और शहतूत।

बेरीज में एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर की अच्छी मात्रा होती है, जो ब्लड शुगर को बढ़ने नहीं देती। अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन के अनुसार, डायबिटीज के मरीजों को फलों और सब्जियों के जूस के मुकाबले उनका साबुत रूप में सेवन करना चाहिए।

सब्जियों में क्या : डायबिटीज के रोगियों के लिए विभिन्न प्रकार की सब्जियों का सेवन करना महत्वपूर्ण होता है। इसलिए इस मौसम में आपको अपने आहार में मुख्य रूप से खीरा, करेला, आंवला, धनिया, लौकी, अदरक और हरी पत्तेदार सब्जियों को शामिल करना चाहिए।

महाप्रभु जगन्नाथ की रथयात्रा का पुण्य सौ यज्ञों के बराबर माना जाता है...

सभी वर्गों के लोग होते हैं शामिल यात्रा में...

भगवान की रथयात्रा में सभी वर्गों के लोग शामिल होते हैं। रथयात्रा आरंभ होने से पहले पुराने राजाओं के वंशज पारंपरिक ढंग से सोने के हत्थे वाली झाड़ू से ठाकुर जी के प्रस्थान मार्ग को साफ करते हैं। इसके बाद मंत्रोच्चार एवं जयघोष के साथ रथयात्रा शुरू होती है।

भारतीय संस्कृति में धार्मिक और सांस्कृतिक त्योहारों का विशेष महत्व है। इसी कड़ी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का पर्व देशभर में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। जगन्नाथ रथ यात्रा का मुख्य आयोजन ओडिशा के पुरी नगर में होता है। इस महापर्व में लाखों भक्त भगवान के रथ को खींचने के लिए उत्साह से भरे होते हैं। यह पर्व न केवल धार्मिक भावनाओं का प्रतीक है, बल्कि भारत की सामाजिक एवं सांस्कृतिक समृद्धि का भी प्रतीक है। इस पर्व में भगवान जगन्नाथ के रथ की यात्रा को देखने का अनुभव अद्वितीय होता है। लोग भक्ति और श्रद्धा के साथ रथ को खींचते हैं। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को खासतौर पर ओडिशा के पुरी नामक स्थान और गुजरात के द्वारका पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा बड़ी धूमधाम से निकाली जाती है। पुरी में श्री जगदीश भगवान को सपरिवार विशाल रथ पर आरुढ़ कराकर भ्रमण करवाया जाता है फिर वापस लौटने पर यथास्थान स्थापित किया जाता है। यह उत्सव अद्वितीय होता है। इस अवसर पर देश विदेश से लाखों श्रद्धालु यहां एकत्र होते हैं। इस उत्सव के दौरान श्रद्धालुओं का भक्ति भाव देखते ही बनता है क्योंकि जिस रथ पर भगवान सवारी करते हैं उसे घोड़े या अन्य जानवर नहीं बल्कि श्रद्धालुगण ही खींच रहे होते हैं।

रथयात्रा के दिन भगवद भक्त व्रत रखते हैं और उत्सव मनाते हैं। पुरी में जिस रथ पर भगवान की सवारी चलती है वह विशाल एवं अद्वितीय है। वह 45 फुट ऊंचा, 35 फुट लंबा तथा इतना ही चौड़ाई वाला होता है। इसमें सात फुट व्यास के 16 पहिये होते हैं। इसी तरह बालभद्र जी का रथ 44 फुट ऊंचा, 12 पहियों वाला तथा सुभद्रा जी का रथ 43 फुट ऊंचा होता है। इनके रथ में भी 12 पहिये होते हैं। प्रतिवर्ष नए रथों का निर्माण किया जाता है। भगवान मंदिर के सिंहद्वार पर बैठकर जनकपुरी की ओर रथयात्रा करते हैं। जनकपुरी में तीन दिन का विश्राम होता है जहां उनकी भेंट श्री लक्ष्मीजी से होती है। इसके बाद भगवान पुनः श्री जगन्नाथ पुरी लौटकर आसनरुढ़ हो जाते हैं।

भारत के मुख्य पर्वों में दस दिवसीय रथयात्रा महत्वपूर्ण स्थान रखती है। भगवान श्रीकृष्ण के अवतार 'जगन्नाथ' की रथयात्रा का पुण्य सौ यज्ञों के बराबर माना जाता है। यात्रा की तैयारी अक्षय तृतीया के दिन श्रीकृष्ण, बलराम और सुभद्रा के रथों के निर्माण के साथ ही शुरू हो जाती है। जगन्नाथ जी का रथ 'गरुड़ध्वज' या 'कपिलध्वज' कहलाता है। रथ पर जो ध्वज है, उसे 'त्रैलोक्यमोहिनी' या 'नंदीघोष' रथ कहते हैं। बलराम जी का रथ 'तलध्वज' के नाम से पहचाना जाता है। रथ के ध्वज को 'उनानी' कहते हैं। जिस रस्सी से रथ खींचा जाता है वह 'वासुकी' कहलाता है। सुभद्रा का रथ 'पद्मध्वज' कहलाता है। रथ ध्वज 'नदंबिक' कहलाता है। इसे खींचने वाली रस्सी को 'स्वर्णचूडा' कहते हैं।

भगवान की रथयात्रा में सभी वर्गों के लोग शामिल होते हैं। रथयात्रा आरंभ होने से पहले पुराने राजाओं के वंशज पारंपरिक ढंग से सोने के हत्थे वाली झाड़ू से ठाकुर जी के प्रस्थान मार्ग को साफ करते हैं। इसके बाद मंत्रोच्चार एवं जयघोष के साथ रथयात्रा शुरू होती है। सर्वप्रथम बलभद्र का रथ तालध्वज प्रस्थान करता है। थोड़ी देर बाद सुभद्रा की यात्रा शुरू होती है। अंत में लोग जगन्नाथ जी के रथ को बड़े ही श्रद्धापूर्वक खींचते हैं। मान्यता है कि रथयात्रा में सहयोग से मोक्ष मिलता है, अतः सभी श्रद्धालु कुछ पल के लिए रथ खींचने को आतुर रहते हैं। जगन्नाथ जी की यह रथयात्रा गुंडीचा मंदिर पहुंचकर संपन्न होती है। 'गुंडीचा मंदिर' वहीं पर स्थित है जहां विश्वकर्मा जी ने तीनों देव प्रतिमाओं का निर्माण किया था। यह भगवान की मौसी का घर भी माना जाता है। यहां भगवान एक सप्ताह प्रवास करते हैं और इस दौरान यहीं पर उनकी पूजा की जाती है। आषाढ़ शुक्ल दशमी को जगन्नाथ जी की वापसी यात्रा शुरू होती है। शाम तक रथ जगन्नाथ मंदिर पहुंच जाते हैं लेकिन प्रतिमाओं को अगले दिन ही मंत्रोच्चार के साथ मंदिर के गर्भगृह में फिर से स्थापित किया जाता है।

मथुरा-वृंदावन... इन मंदिरों में भगवान श्री

भगवान श्रीकृष्ण की नगरी मथुरा और वृंदावन सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत से पूर्ण है। मथुरा में सबसे ज्यादा मंदिर कृष्ण को समर्पित है जो भक्तों और पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं।

भारत में कई प्रमुख तीर्थ स्थालों में से एक है श्रीकृष्ण की नगरी मथुरा भी शामिल है। यहां हर दिन हजारों श्रृद्धालु मथुरा के मंदिरों में भगवान की एक झलक देखने के लिए आते हैं। दरअसल, मथुरा में भगवान कृष्ण को समर्पित एक से एक मंदिर स्थित है, जहां की आधुनिक निर्माण शैली और वास्तुकला दुनियाभर में मशहूर है। अगर आप भी मथुरा-वृंदावन घूमने का प्लान बना रहे हैं तो इन 7 मंदिरों के दर्शन करना न भूले।

बांके बिहारी मंदिर, वृंदावन

सबसे प्रतिष्ठित और पुराने कृष्ण मंदिरों में से एक वृंदावन का बांके बिहारी मंदिर, जहां जाकर आप आधे से ज्यादा वृंदावन धाम के दर्शन कर लेंगे। बांके बिहारी मंदिर में भक्तों की भीड़ हमेशा रहती है। यहां पर श्रीकृष्ण की काले रंग की प्रतिमा स्थापित है।

श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर

यह तो हर कोई जानता है कि भगवान श्रीकृष्ण का जन्म स्थान मथुरा में ही स्थित है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर के गर्भगृह में ही भगवान श्रीकृष्ण का जन्म हुआ था, जो पहले कारागृह था। इस मंदिर में कान्हा जी के बालस्वरुप के दर्शन मिलते हैं।

द्वारकाधीश मंदिर, मथुरा

यह मंदिर भगवान श्रीकृष्ण को समर्पित है, द्वारकाधीश मंदिर की वास्तुकला राजस्थानी शैली पर आधारित है। इस मंदिर में भगवान श्रीकृष्ण के दर्शन तो मिलेंगे ही, साथ उनके जीवन से जुड़ी घटनाओं से जुड़ी कलाकृतियां भी देखने को मिलेंगी।

श्री राधा रमण मंदिर, मथुरा

श्री राधारमण मंदिर काफी प्राचीन है, यहां पर भगवान की अनोखी मूर्ति स्थापित है। बता दें कि, भगवान का ये स्वरुप शालिग्राम पत्थर से निकला था। गोपाल भट्ट गोस्वामी द्वारा स्थापित इस मंदिर में प्रतिदिन नियम से पूजा और अनुष्ठान किए जाते हैं।

प्रेम मंदिर, वृंदावन

यह मंदिर श्रीकृष्ण और राधा जी को समर्पित करते हुए वृंदावन में भव्य प्रेम मंदिर भी बनाया गया है। इस मंदिर की खूबसूरती देश-विदेश से पर्यटकों को आकर्षित करती है। यहां की वास्तुकला और मूर्तियों में भगवान श्रीकृष्ण की लीलाएं दिखाई गई हैं।

श्री गोपीनाथ जी मंदिर

वृंदावन के सबसे पुराने मंदिरों में श्री गोपीनाथ जी का मंदिर भी है, जहां राधा रानी और भगवान कृष्ण के साथ राधा जी की छोटी बहन अनंग मंजरी और उनकी सखी ललिता और विशाखा की मूर्तियां स्थापित हैं।

श्री निधिवन

वृंदावन का सबसे फेमस और प्राचीन मंदिर निधिवन है। जहां भगवान कृष्ण, राधा रानी और गोपियों के बीच पवित्र रासलीला रचाई। इस मंदिर में आज भी भगवान श्रीकृष्ण के साथ राधा रानी का श्रृंगार भी होता है।

चार महीने के लिए रुक जाएंगे मांगलिक कार्य

आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवशयनी या हरिशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। देवशयनी एकादशी से श्री हरिविष्णु चार मास के लिए निद्रा में लीन हो जाते हैं। इसीलिए इसी दिन से चातुर्मास की शुरुआत होती है और कार्तिक मास में आने वाली देवउठनी एकादशी में शयनकाल समाप्त होता है और इसी के साथ चातुर्मास भी समाप्त हो जाता है।

आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवशयनी या हरिशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवशयनी एकादशी के दिन से ही श्री हरि विष्णु योगनिद्रा में चले जाते हैं। मान्यता के अनुसार इस बीच सम्पूर्ण सृष्टि का दायित्व भगवान भोलेनाथ के ऊपर होता है। देवशयनी एकादशी से श्री हरिविष्णु चार मास के लिए निद्रा में लीन हो जाते हैं। इसीलिए इसी दिन से चातुर्मास की शुरुआत होती है और कार्तिक मास में आने वाली देवउठनी एकादशी में शयनकाल समाप्त होता है और इसी के साथ चातुर्मास भी समाप्त हो जाता है। आइए जानते हैं कब से शुरू हो रहे हैं चातुर्मास और क्या हैं इससे जुड़े नियम।

चातुर्मास में न करें ये काम

- चातुर्मास के दौरान विवाह समारोह, सगाई, मुंडन, बच्चे का नामकरण, गृहप्रवेश जैसे तमाम मांगलिक कार्य करने की मनाही है।
- अगर आप चातुर्मास के दौरान चार माह का व्रत रखते हैं या कोई विशेष साधना करते हैं तो इस बीच यात्रा न करें।
- चातुर्मास के दौरान दही, मूली, बैंगन और साग आदि खाना वर्जित माना जाता है।
- झूठ, छल, कपट, ईर्ष्या, कटु वचन जैसी आदतों से दूर रहें।
- संभव हो तो किसी का दिल न दुखाएं और खुद पर संयम बनाए रखें।
- चातुर्मास के दौरान तामसिक भोजन से परहेज करना चाहिए।
- ब्रह्मचर्य का भी पालन करना चाहिए।

चातुर्मास में करें ये काम

- चातुर्मास के दौरान श्रीहरि विष्णु की उपासना करनी चाहिए।
- आप इस दौरान विशेष अनुष्ठान, मंत्र जाप, गीता का पाठ आदि कर सकते हैं।

विटामिन सी, आयरन और कैल्शियम जैसे पोषक तत्वों से भरपूर जामुन...

जामुन विटामिन और मिनरल का एक अच्छा स्रोत है, जिसमें विटामिन सी, आयरन, कैल्शियम और पोटेशियम शामिल हैं, जो संपूर्ण स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं। जामुन को अपने आहार में शामिल करने से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, पाचन तंत्र में सुधार होता है, और रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद मिलती है।

गर्मियों में आम, लीची, तरबूज और खरबूज के अलावा जामुन भी एक पसंदीदा फल है, जो विटामिन सी, आयरन और कैल्शियम जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होता है। जामुन को अपने आहार में शामिल करने से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, पाचन तंत्र में सुधार होता है, और रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। इसके एंटीऑक्सीडेंट गुण शरीर को हानिकारक मुक्त कणों से बचाते हैं और विभिन्न बीमारियों से राहत दिलाते हैं।

पोषक तत्वों से भरपूर

जामुन विटामिन और मिनरल का एक अच्छा स्रोत है, जिसमें विटामिन सी, आयरन, कैल्शियम और पोटेशियम शामिल हैं, जो संपूर्ण स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं।

एंटीऑक्सीडेंट गुण

जामुन में एंथोसायनिन, पॉलीफेनोल और फ्लेवोनोइड जैसे शक्तिशाली एंटीऑक्सिडेंट होते हैं, जो शरीर को ऑक्सीडेटिव तनाव और मुक्त कणों से होने वाले नुकसान से बचाने में मदद करते हैं।

मधुमेह प्रबंधनः जामुन अपने हाइपोग्लाइसेमिक गुणों के लिए जाना जाता है, जो रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है। इस फल के बीज मधुमेह रोगियों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद होते हैं क्योंकि वे स्टार्च को चीनी में बदलने की प्रक्रिया को धीमा कर देते हैं।

पाचन स्वास्थ्य

जामुन में मौजूद फाइबर पाचन में सहायता करता है, कब्ज को रोकता है और स्वस्थ पाचन तंत्र को बढ़ावा देता है। इसमें कसैले गुण भी होते हैं जो दस्त और पेचिश के इलाज में मदद कर सकते हैं।

हृदय स्वास्थ्य

जामुन में मौजूद पोटैशियम रक्तचाप को नियंत्रित रखने और उच्च रक्तचाप के जोखिम को कम करके हृदय स्वास्थ्य का समर्थन करता है। इसके एंटीऑक्सीडेंट गुण समग्र हृदय स्वास्थ्य में भी योगदान करते हैं।

वजन प्रबंधन

कम कैलोरी और उच्च फाइबर वाला जामुन वजन प्रबंधन आहार में एक अच्छा अतिरिक्त हो सकता है क्योंकि यह तृप्ति बनाए रखने और समग्र कैलोरी सेवन को कम करने में मदद करता है।

प्रतिरक्षा को बढ़ाता है : जामुन में मौजूद विटामिन सी की उच्च मात्रा प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करती है और शरीर को संक्रमण और बीमारियों से लड़ने में मदद करती है। त्वचा स्वास्थ्यः जामुन में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन स्वस्थ, चमकदार त्वचा में योगदान करते हैं। वे मुंहासे, दाग-धब्बे और काले धब्बे कम करने में मदद करते हैं और त्वचा की समग्र बनावट में भी सुधार करते हैं।

मौखिक स्वास्थ्य

जामुन के जीवाणुरोधी गुण मसूड़ों के संक्रमण, सांसों की बदबू और अन्य दंत समस्याओं को रोककर मौखिक स्वच्छता बनाए रखने में मदद करते हैं।

एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण

जामुन में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो गठिया और अन्य सूजन संबंधी बीमारियों जैसी स्थितियों में सूजन और दर्द को कम करने में मदद कर सकते हैं।

हीमोग्लोबिन के स्तर में सुधार करता हैः जामुन में मौजूद आयरन हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाने में मदद करता है, जो एनीमिया से पीड़ित लोगों के लिए फायदेमंद है।

ओलंपिक के लिए राइफल और पिस्टल टीम घोषित, दो स्पर्धाओं में भाग लेगी मनु

भारतीय निशानेबाजी महासंघ ने पेरिस ओलंपिक के लिए 15 सदस्यीय राइफल और पिस्टल टीम की घोषणा की जिसमें स्टार पिस्टल निशानेबाज मनु भाकर अकेली ऐसी खिलाड़ी है जो दो स्पर्धाओं में भाग लेगी। टीम का चयन वर्चुअल बैठक में किया गया। टीम में आठ राइफल और सात पिस्टल निशानेबाज शामिल हैं। भारतीय निशानेबाजी महासंघ ने पेरिस ओलंपिक के लिए मंगलवार को 15 सदस्यीय राइफल और पिस्टल टीम की घोषणा की जिसमें स्टार पिस्टल निशानेबाज मनु भाकर अकेली ऐसी खिलाड़ी है जो दो स्पर्धाओं में भाग लेगी। टीम का चयन वर्चुअल बैठक में किया गया। टीम में आठ राइफल और सात पिस्टल निशानेबाज शामिल हैं।

चयन समिति ने ट्रायल्स के परिणामों को प्राथमिकता देने का फैसला किया जिससे विश्व चैंपियन रुद्राक्ष पाटिल जैसे निशानेबाजों के लिए दरवाजे बंद हो गए। पाटिल अपनी पसंदीदा 10 मीटर एयर राइफल में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए थे लेकिन इसके बावजूद वह ओलंपिक टीम में शामिल करने की गुहार लगा रहे थे क्योंकि उन्होंने कोटा हासिल किया था। निशानेबाजी में कोई व्यक्तिगत खिलाड़ी नहीं बल्कि देश को कोटा दिया जाता है। टीम के सभी सदस्य, कोच और सहयोगी स्टाफ अभी फ्रांस के वोल्मेरेंज लेस माइंस में शिविर में भाग ले रहे हैं। इसका उद्देश्य परिस्थितियों से सामंजस्य बिठाना है। ओलंपिक में जाने से पहले सभी खिलाड़ी दो सप्ताह के लिए स्वदेश लौटेंगे। शॉटगन टीम की घोषणा इटली के लोनाटो में होने वाले विश्व कप के बाद की जाएगी, जिसमें प्रतियोगिताएं बुधवार से शुरू होकर 18 जून तक चलेंगी। पेरिस ओलंपिक खेल 26 जुलाई से 11 अगस्त तक आयोजित किए जाएंगे। भारतीय निशानेबाजों ने इस बार संभावित 24 में से 21 कोटा स्थान हासिल किए हैं। राइफल और पिस्टल में उसने सभी आठ आठ कोटा स्थान हासिल किए हैं। भारत ने इससे पहले कभी इतनी अधिक कोटा स्थान हासिल नहीं किए थे। तोक्यो ओलंपिक के लिए भारत ने 15 कोटा स्थान हासिल किए थे।

पेरिस ओलंपिक के लिए भारत की राइफल और पिस्टल निशानेबाजी टीम इस प्रकार हैं

राइफलः संदीप सिंह, अर्जुन बबूता (10 मीटर एयर राइफल पुरुष), एलावेनिल वलारिवन, रमिता (10 मीटर एयर राइफल महिला), सिफ्ट कौर समरा, अंजुम मौदगिल (50 मीटर राइफल 3 पोजिशन महिला), ऐश्वर्य तोमर, स्वप्निल कुसाले (50 मीटर राइफल 3 पोजिशन पुरुष)

पिस्टलः सरबजोत सिंह, अर्जुन चीमा (10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष), मनु भाकर, रिदम सांगवान (10 मीटर एयर पिस्टल महिला), अनीश भानवाल विजयवीर सिद्धू (25 मीटर आरएफपी पुरुष), मनु भाकर, ईशा सिंह (25 मीटर पिस्टल महिला)।

गोल्फर अदिति और दीक्षा ने पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालीफाई किया...

अदिति पहली भारतीय गोल्फर है जो तीसरी बार ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करेंगी। दीक्षा के लिए यह दूसरा मौका होगा तो वहीं शुभंकर और भुल्लर पहली बार इन खेलों में चुनौती पेश करेंगे।

भारतीय गोल्फर अदिति अशोक और दीक्षा डागर ने सोमवार को विश्व रैंकिंग के आधार पर पेरिस ओलंपिक के टिकट हासिल कर लिये। दोनों महिला खिलाड़ियों से पहले शुभंकर शर्मा और गगनजीत भुल्लर (पुरुष वर्ग) ने भी ओलंपिक के लिए क्वालिफिकेशन पक्का कर लिया था। इससे चार सदस्यीय भारतीय टीम 26 जुलाई से 11 अगस्त तक आयोजित होने वाले खेलों में चुनौती पेश करेंगी। अदिति पहली भारतीय गोल्फर है जो तीसरी बार ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करेंगी। दीक्षा के लिए यह दूसरा मौका होगा तो वहीं शुभंकर और भुल्लर पहली बार इन खेलों में चुनौती पेश करेंगे। ओलंपिक में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन अदिति ने ही किया है। वह तोक्यो ओलंपिक में पदक से चूक कर चौथे स्थान पर रही थी। ओलंपिक प्रविष्टियां भारतीय गोल्फ संघ द्वारा भेजी जाती हैं। ओलंपिक के लिए क्वालिफिकेशन रैंकिंग द्वारा निर्धारित की जाती है, जो आधिकारिक विश्व गोल्फ रैंकिंग (ओडब्ल्यूजीआर) के माध्यम से 60 पुरुष और इतनी ही महिला खिलाड़ियों तक सीमित है। ओडब्ल्यूजीआर में शीर्ष 15 खिलाड़ी ओलंपिक के लिए पात्र होते है। इसमें एक देश से अधिकतम चार गोल्फरों की अनुमति है।

इसके बाद ओलंपिक गोल्फ रैंकिंग (ओजीआर) के आधार पर खिलाड़ियों को कोटा मिलता है। इसमें एक देश से अधिकतम दो खिलाड़ी जगह पात्र होते है बशर्ते उस देश को ओडब्ल्यूजीआर के कोटे से जगह नहीं मिली हो। अदिति 24वें स्थान के साथ भारत की शीर्ष महिला खिलाड़ी है जबकि दीक्षा 40वें पायदान पर है। दीक्षा ओलंपिक और डेफलंपिक्स (बधिर खिलाड़ियों का विशेष ओलंपिक) में भाग लेने वाले इकलौती गोल्फर है। डेफलंपिक्स में उनके नाम दो पदक है।

18 की उम्र में कास्टिंग काउच की शिकार, ईशा का छलका दर्द...

अकेले में मिलो फिर करूंगा..

सिद्धार्थ कन्नन के साथ एक साक्षात्कार में, इंडस्ट्री में अपने शुरुआती दिनों के दौरान कास्टिंग काउच के अपने अनुभव पर चर्चा करते हुए ईशा की आंखें भर आईं। 'यह कभी इस बारे में नहीं था कि आप क्या कर सकते हैं।

ईशा कोप्पिकर कई साउथ फिल्मों में काम करने के बाद फिजा से बॉलीवुड में डेब्यू किया। उन्होंने 18 साल की उम्र में एक भयावह कास्टिंग काउच अनुभव के बारे में खुलकर बात की है। डरना मना है, पिंजर, एलओसी कारगिल, कृष्णा कॉटेज और डॉन जैसी फिल्मों में अभिनय करने के अलावा, ईशा कांटे से 'इश्क समुंदर' और कंपनी से 'खल्लास' जैसे विशेष डांस नंबरों का हिस्सा थीं।

सिद्धार्थ कन्नन के साथ एक साक्षात्कार में, इंडस्ट्री में अपने शुरुआती दिनों के दौरान कास्टिंग काउच के अपने अनुभव पर चर्चा करते हुए ईशा की आंखें भर आईं। 'यह कभी इस बारे में नहीं था कि आप क्या कर सकते हैं। हीरो और एक्टर तय करते थे। आपने #MeToo के बारे में सुना होगा, और अगर आपके पास मूल्य थे, तो यह बहुत मुश्किल था। मेरे समय में कई अभिनेत्रियों ने इंडस्ट्री छोड़ दी। या तो लड़कियों ने हार मान ली या उन्होंने हार मान ली। बहुत कम लोग हैं जो अभी भी इंडस्ट्री में हैं और हार नहीं मानी है, और मैं उनमें से एक हूं।

इस अनुभव को याद करते हुए ईशा ने कहा, मैं 18 साल की थी जब एक सेक्रेटरी और एक एक्टर ने कास्टिंग काउच के लिए मुझसे संपर्क किया। उन्होंने मुझसे कहा कि काम पाने के लिए, आपको एक्टर्स के साथ 'दोस्ताना' होना चाहिए। मैं बहुत दोस्ताना हूँ, लेकिन 'दोस्ताना' का क्या मतलब है? मैं इतनी दोस्ताना हूँ कि एकता कपूर ने एक बार मुझसे कहा था कि थोड़ा रवैया रखो।

स्वरा भास्कर के चौंकाने वाले खुलासे, बोली-

कोई भी निर्माता व निर्देशक नहीं करना चाहता काम..?

बॉलीवुड अभिनेत्री स्वरा भास्कर अपने विचारों और दृष्टिकोणों से लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती हैं। दिवा ने कहा कि उनका ट्विटर अकाउंट उनके लिए सबसे महंगी चीज थी क्योंकि इसकी वजह से उनका करियर बर्बाद हो गया। वैसे, खूबसूरत अभिनेत्री अपनी राय के बारे में काफी मुखर रही हैं और हाल ही में उन्होंने खुलासा किया कि निर्माता विवाद के डर से उन्हें फिल्मों में कास्ट नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें स्वरा जैसी अभिनेत्री चाहिए और उन्होंने यह भी खुलासा किया कि उनके प्रियजनों का मानना है कि उन्होंने खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली और अपना करियर बर्बाद कर लिया।

कनेक्ट सिने के साथ बातचीत में स्वरा भास्कर ने कहा कि बहुत से निर्माताओं के लिए, वह इंडस्ट्री में अछूत हैं और लोगों ने उनसे यह भी कहा है कि वे उन्हें कास्ट करना चाहते थे लेकिन स्टूडियो ने उनका नाम सुनकर मना कर दिया। स्वरा ने याद किया कि एक कास्टिंग डायरेक्टर ने उनसे कहा था कि उन्हें अक्सर स्वरा जैसी अभिनेत्री के लिए ब्रीफ मिल जाता है। उनसे पूछा गया कि उन्होंने उन्हें कास्ट क्यों नहीं किया और उन्होंने कहा कि वे नहीं चाहते कि विवाद हो और कहा कि डर है। स्वरा ने यहां तक कहा कि जब वे उन्हें सड़कों पर रोकते हैं या हवाई अड्डों पर उनसे बात करते हैं तो बहुत से लोग उनका समर्थन करते हैं। उसने यहां तक कहा कि उनमें से कुछ ने उससे कहा कि यह उसकी मूर्खता थी कि उसने अपना करियर बर्बाद कर दिया। उसने यहां तक कहा कि उसका भाई उसका सबसे बड़ा समर्थक है और उसे सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पर आता है कि वह खुद को पैर में गोली मार लेती है।

वर्कफ्रंट की बात करें तो स्वरा को आखिरी बार जहां चार यार में देखा गया था जो 2022 में रिलीज हुई थी। स्वरा ने फरवरी में राजनेता फहाद अहमद से शादी की और अपने पहले बच्चे, राबिया नाम की एक बच्ची का स्वागत किया।

कंगना पर इमरान का तंज...

अवॉर्ड मिलना बंद हो गया

बॉलीवुड एक्ट्रेस और मंडी से सांसद कंगना रनौत अपने बेबाक बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहती हैं। वह हर मुद्दे पर खुलकर अपने विचार रखती हैं। वहीं एक बार जब एक्ट्रेस अवॉर्ड फंक्शन में न जाने को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि अवॉर्ड फंक्शन में जाना उन्हें पसंद नहीं है। क्योंकि ये सिर्फ टीआरपी के लिए होता है। कंगना ने कहा कि एक स्टार परफॉर्म करता है और फिर उसे अवॉर्ड मिलता है। वहीं इमरान हाशमी भी अवॉर्ड फंक्शन में नजर नहीं आते इस पर एक्टर ने खुलकर बात की साथ ही कंगना पर भी तंज कसा है।

कंगना पर कसा तंज

एक पॉडकास्ट में बातचीत के दौरान इमरान हाशमी से पूछा गया कि क्या कंगना की तरह उन्हें भी अवॉर्ड शो बेकार लगते हैं। तो इमरान ने चुटकी लेते हुए कहा क्योंकि अवॉर्ड मिलना बंद हो गए उसके बाद? मुझे याद है कि एक बार मैं अवॉर्ड जीता था लेकिन जल्द ही मुझे इसके पीछे का सारा खेल समझ आ गया था। ये एक तरह की डील है तुम आओ और नाचो। इमरान ने आगे कहा,' अभी मैं ये नहीं कहूंगा कि ये अच्छा नहीं है। मैं अवॉर्ड से इनकार नहीं करूंगा जिन लोगों को अपना लिविंग रूम सजाना है वो करें, जाकर परफॉर्म करें।

इमरान नहीं जाते अवॉर्ड शो में

इमरान ने कहा कि मैं अपनी पीठ नहीं थपथपा सकता कि मैंने ऐसी परफॉर्मेंस दी हैं क्योंकि ये झूठ है। अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया होगा तो आपको अवॉर्ड मिलेगा ही। जीतने का क्या ही फायदा अगर ये बार्टर सिस्टम जैसा है?' इमरान हाशमी ने साफ किया कि उन्होंने इसी कारण अवॉर्ड शो का हिस्सा बनना बंद कर दिया।

नोरा फतेही ने निकाला तौबा तौबा ट्रेंड, गाने में अपने जिक्र पर शरमाते हुए डांस किया

नोरा फतेही को उनकी शानदार डांसिंग क्षमताओं के कारण बहुत सारे प्रशंसक मिले हैं। उन्होंने लगभग एक दशक पहले शोबिज की दुनिया में सनसनीखेज एंट्री की थी और कई चार्टबस्टर गानों में नज़र आईं।

नोरा फतेही को उनकी शानदार डांसिंग क्षमताओं के कारण बहुत सारे प्रशंसक मिले हैं। उन्होंने लगभग एक दशक पहले शोबिज की दुनिया में सनसनीखेज एंट्री की थी और कई चार्टबस्टर गानों में नज़र आईं। अब, तौबा तौबा पर उनके डांस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। क्लिप में, नोरा फतेही गाने की एक खास लाइन पर थिरकती हैं: 'बाज तेरी सोहनी सारी नूरी वरगी, जदों लक हिलदा ऐ ओहदा तन नोरा लगदी'।

क्लिप के साथ, उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'नोरा लग दी...@karanaujla @boscomartis आपने कमाल कर दिया! पूरी टीम को शुभकामनाएं @karanjohar @vickykaushal'। गाने पर उनकी प्रतिक्रिया देखकर प्रशंसक गदगद हो गए और कमेंट सेक्शन में भर गए। एक यूजर ने लिखा, 'हुस्न तेरा तौबा तौबा'। एक अन्य यूजर ने लिखा, 'जादो लक हिल्दा ओदो तो नौरा लगदी'। तीसरे यूजर ने लिखा 'तुम ही कारण हो कि हमें यह गाना इतना पसंद आ रहा है!! इसमें तुम्हारा नाम सुनकर हम तृप्त नहीं हो पा रहे हैं! #नोरा लगदी'। इस गाने को पंजाबी गायकी के मशहूर गायक करण औजला ने गाया है। उन्होंने न केवल गाया बल्कि गाने के बोल भी खुद लिखे हैं। गाने में विक्की कौशल और करण औजला कूल शेड्स में दिख रहे हैं और अपने मूव्स से स्वैग और चार्म दिखा रहे हैं। वहीं त्रिप्ति डिमरी गाने में बेहद खूबसूरत लग रही हैं।

बॉलीवुड डायरेक्टर आनंद तिवारी द्वारा निर्देशित फिल्म 'बैड न्यूज' 19 जुलाई, 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म में विक्की कौशल, त्रिप्ति डिमरी और एमी विर्क मुख्य भूमिकाओं में होंगे, साथ ही नेहा धूपिया, शीबा चड्ढा और फैजल राशिद भी अहम भूमिकाओं में होंगे। साथ ही, अनन्या पांडे भी फिल्म में कैमियो करती नजर आएंगी। 'बैड न्यूज़' मनोरंजन से भरपूर होने वाली है, जिसका दर्शक बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। विक्की कौशल, तृप्ति डिमरी और एमी विर्क अभिनीत आगामी फिल्म का ट्रेलर 28 जून, 2024 को लॉन्च किया गया था। दर्शकों को फिल्म में बेहतरीन कॉमेडी सीन और ढेर सारी मस्ती का वादा करने वाला टीज़र बहुत पसंद आया। ट्रेलर की शुरुआत एक नोट से होती है 'सच्ची घटनाओं से प्रेरित एक 'दुर्लभ' कॉमेडी आ रही है।' ट्रेलर में, तृप्ति उलझन में दिखाई देती है क्योंकि उसे कोई अंदाजा नहीं है कि जिस बच्चे से वह गर्भवती है उसका असली पिता कौन है। चाहे बच्चा विक्की का हो या एमी विर्क का। वह अपने दोस्त के क्लिनिक जाती है जो एक डॉक्टर है।

आशा नेगी ने अपनी डेटिंग लाइफ़ के बारे में अटकलों पर कहा

मैं खुशी से सिंगल हूँ

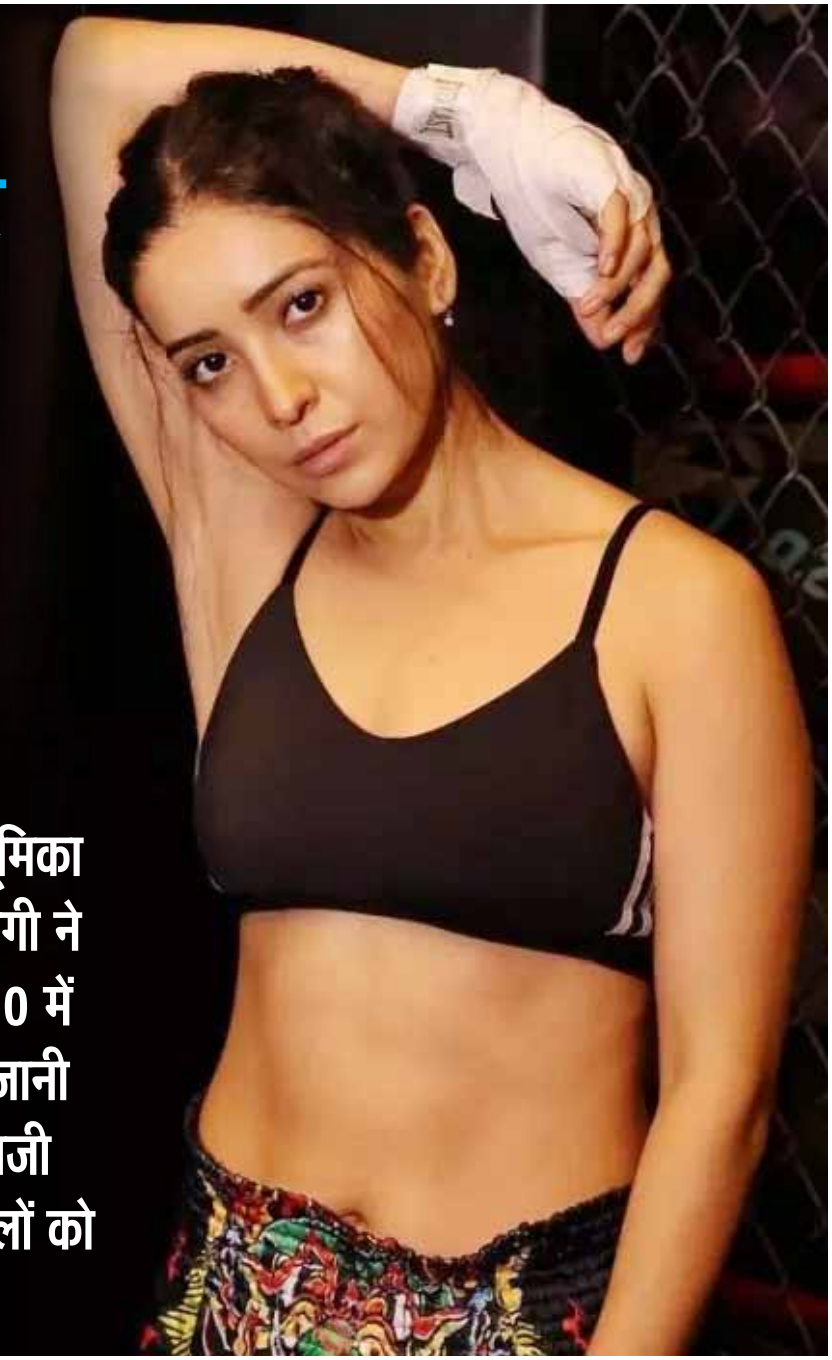

टीवी शो पवित्र रिश्ता में अपनी भूमिका के लिए मशहूर अभिनेत्री आशा नेगी ने सात साल की डेटिंग के बाद 2020 में अपने सह-कलाकार ऋत्विक धनजानी के साथ ब्रेकअप के बाद अपनी निजी ज़िंदगी के बारे में चल रही अटकलों को संबोधित किया।

टीवी शो पवित्र रिश्ता में अपनी भूमिका के लिए मशहूर अभिनेत्री आशा नेगी ने सात साल की डेटिंग के बाद 2020 में अपने सह-कलाकार ऋत्विक धनजानी के साथ ब्रेकअप के बाद अपनी निजी ज़िंदगी के बारे में चल रही अटकलों को संबोधित किया। प्रशंसकों की लगातार टिप्पणियों के बावजूद, नेगी ने अपने वर्तमान रिश्ते की स्थिति पर ज़ोर देते हुए कहा, 'मेरे सभी जिज्ञासु प्रशंसकों के लिए, मैं सिंगल हूँ और इस तरह से काफी खुश हूँ। मैं अपना जीवन जी रही हूँ, आगे बढ़ रही हूँ और विकसित हो रही हूँ। यह अच्छा चल रहा है। मेरा ध्यान काम और खुद पर है। व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों ही तरह से, मुझे एक ही कम्फर्ट ज़ोन में रहना पसंद नहीं है, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ।'

34 वर्षीय आशा नेगी, जिनके इंस्टाग्राम पर दो मिलियन से ज्यादा फ़ॉलोअर हैं, कहती हैं कि उन्हें अपनी डेटिंग लाइफ़ के बारे में होने वाली जांच का सामना करना पड़ता है, और व्यक्तिगत स्पष्टता के लिए सोशल मीडिया से ब्रेक लेने के महत्व पर ज़ोर देती हैं। उन्होंने कहा, 'अब तो आदत हो चुकी है। नेगी ने बताया 'पहले, यह मुझे परेशान करता था, लेकिन अब मुझे इसकी आदत हो गई है। कई बार ऐसा होता है जब मैं किसी से बातचीत नहीं करना चाहती और सोशल मीडिया से दूर रहना चाहती हूँ। मैं खुद को वह आज़ादी देती हूँ। मैं खुद पर हर समय दिखने या हर समय सोशल मीडिया पर रहने का दबाव नहीं डालती। जब भी मुझे अपना दिमाग साफ करना होता है, मैं कुछ समय के लिए छुट्टी ले लेती हूँ।

एक अभिनेता के रूप में सोशल मीडिया पर मौजूदगी बनाए रखने के दबाव के बारे में, नेगी कहती हैं कि किसी को 'इससे लाभ उठाने की कोशिश करनी चाहिए, न कि इसका मज़ाक उड़ाना चाहिए'। उन्होंने आगे कहा 'हाँ, सोशल मीडिया का बोझ अब अभिनेता की ज़िंदगी में आ गया है। लेकिन, सबसे अच्छा जो आप कर सकते हैं, वह है इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना। पुराने ज़माने कितने खूबसूरत थे जब सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन अब तो कुछ फ़ायदे भी हैं, कोई बस उस पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर सकता है।'

अपने करियर के बारे में बात करते हुए, नेगी, जिन्होंने टेलीविज़न से ओटीटी पर कदम रखा, हमें बताती हैं कि कुछ लोग अभी भी उन्हें टाइपकास्ट करते हैं। नेगी कहती हैं, 'लोग ऐसा सीधे तौर पर नहीं कहते, लेकिन आप अभी भी अपने साथ 'टीवी' का बोझ लेकर चलते हैं, खासकर तब जब आप घर-घर में मशहूर हो चुके हैं। लोग अभी भी मुझे पूर्वी के नाम से बुलाते हैं (पवित्र रिश्ता में उनका किरदार) और मुझे इस बात पर बेहद गर्व है क्योंकि इसी नाम की वजह से मैं आज इस मुकाम पर पहुँची हूँ।

उन्होंने आगे कहा, 'लेकिन लोग अभी भी कभी-कभी थोड़ा हिचकिचाते हैं।' हाल ही में वेब सीरीज़ इंडस्ट्री में नज़र आईं, जो मनोरंजन उद्योग की जटिलताओं की एक वास्तविक झलक पेश करती है, नेगी, जिन्होंने सान्या सेन की भूमिका निभाई, कहती हैं कि उन्हें यह भूमिका बहुत अच्छी लगी। 'मैं एक अभिनेता के जीवन के कई पहलुओं से जुड़ सकती हूँ जो मेरी अपनी यात्रा को दर्शाते हैं। इंडस्ट्री के अंदरूनी लोग भी सीरीज़ से जुड़ाव महसूस कर रहे हैं, जबकि इंडस्ट्री से बाहर के लोग इसके रहस्यों को खोज रहे हैं,' वह अंत में कहती हैं।

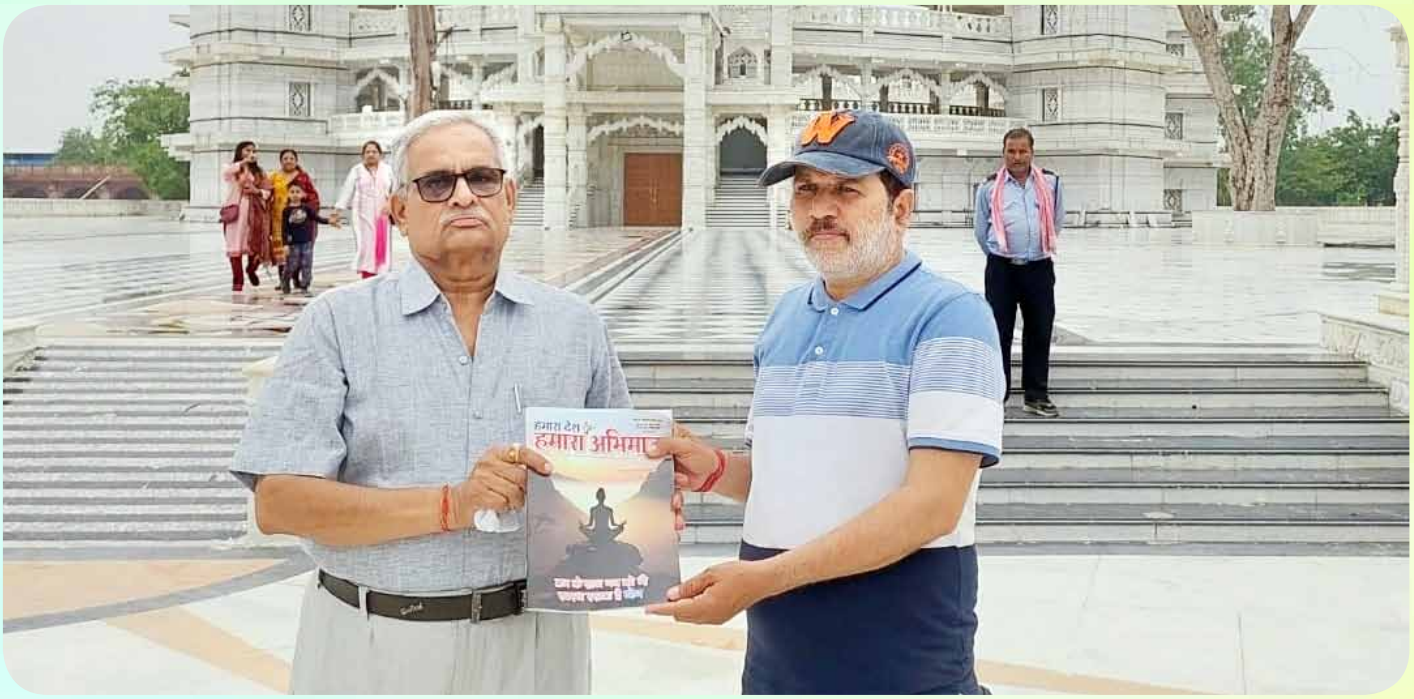

हमारा देश हमारा अभिमान पत्रिका के संरक्षक डॉक्टर श्रीमन नारायण मिश्रा दादा के साथ
हमारा देश हमारा अभिमान पत्रिका के संपादक मनोज चतुर्वेदी के साथ विशेष चर्चा।

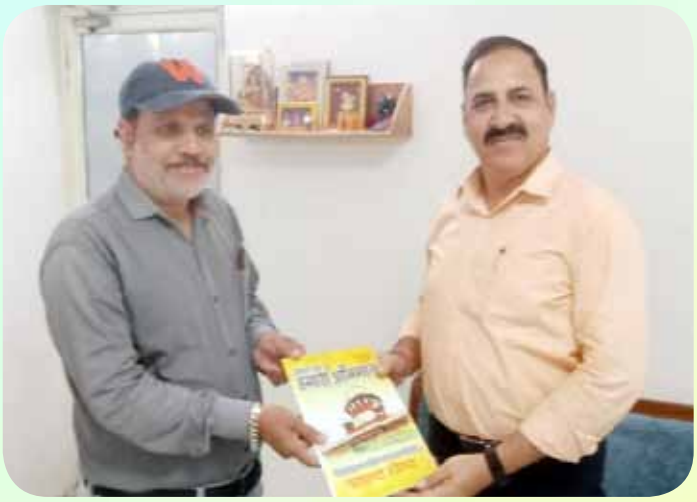

डीएसपी संजीव नयन शर्मा साइबर ग्वालियर एवं
मनोज चतुर्वेदी संपादक के साथ विशेष चर्चा

निरंजन शर्मा अति. पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ग्वालियर एवं
मनोज चतुर्वेदी। संपादक के साथ विशेष चर्चा।

हमारा देश हमारा अभिमान पत्रिका के वरिष्ठ संरक्षक दीदी डॉक्टर शालिनी कौशिक एवं संपादक मनोज चतुर्वेदी के साथ मैसर्स पलिया कंस्ट्रक्शन कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर इंजीनियर श्री अनूप शर्मा एवं उनके पुत्र इंजिनियर शिवम शर्मा।

हमारा देश हमारा अभिमान

हर-हर महादेव

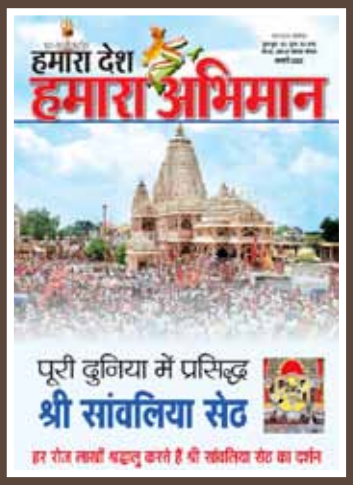

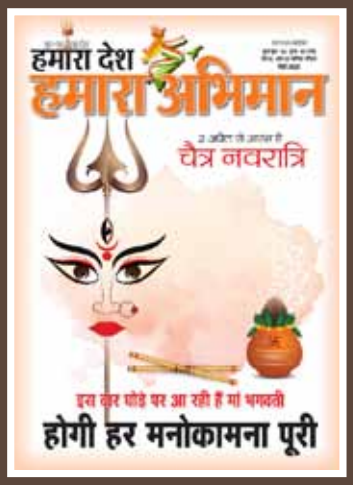

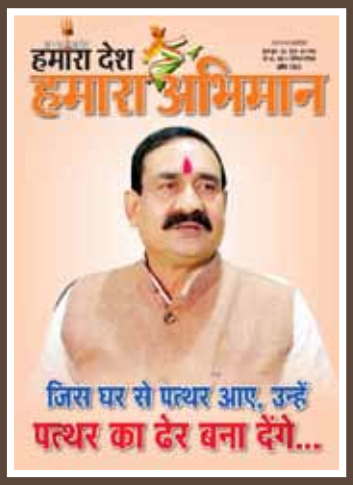

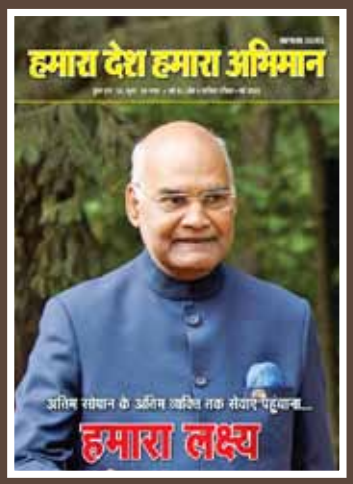

हमारा देश हमारा अभिमान मासिक पत्रिका की प्रति बुक करने के लिए सम्पर्क करें..

मनोज चतुर्वेदी : 98266 36922, 88392 59136